चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित

16 फरवरी–22 फरवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

किसानों की ज़मीन छीनी तो फिर आंदोलन होगा

साल 2011 से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है. यमुना का प्रदूषण स्तर काफी बढ़ चुका है. देश में नई सरकार आ चुकी है. विपक्ष मृतप्राय हो चुका है. कुछ नए राजनीतिक दल मैदान में ताल ठोंक रहे हैं. कुछ नए वादे किए जा रहे हैं. कुछ पुराने वादे तोड़े जा रहे हैं. देश नए रास्ते पर जाने का प्रयास कर रहा है तो कहीं से चिंगारी भड़कने की आवाज़ भी आ रही है. इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने गांव में बैठ कर एक बार फिर कुछ सवाल बुन रहे हैं. ये सवाल इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं. इनकी रोज़ी-रोटी से जुड़े हुए हैं. तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सवालों का कोई जवाब मिलेगा? या फिर इतिहास ख़ुद को इतनी जल्दी दोहराएगा? 2011 में भी लोगों ने तत्कालीन सरकार से कुछ सवाल पूछे थे. जवाब नहीं मिला. फिर जो हुआ, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है. लेकिन इतिहास दोहराने का अर्थ यह भी नहीं है कि वह उसी रूप में फिर से सामने आए. उसका नतीजा वैसा ही हो जैसा पहले था. लेकिन सवाल यह भी है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में, जहां विपक्ष हताश, निराश और मृतप्राय है, आख़िर कोई तो हो जो सवाल उठा सके.

शशि शेखर

30 जनवरी को गांधीजी को याद करते हुए अन्ना हजारे ने सबसे पहली बात यह कही कि पिछले कुछ महीनों से मैं पीठ के दर्द की वजह से लोगों में नियमित रूप से नहीं जा सका. अब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है. जनसेवा के लिए मैं फिर पहले जैसा काम करूंगा. यानी, अन्ना अब फिर से कोई शंखनाद करने को तैयार दिख रहे हैं. अन्ना हजारे मान रहे हैं कि नई सरकार ने अच्छे दिन लाने के वायदे तो ख़ूब किए लेकिन चंद पूंजीपतियों को छोड़ कर किसी भी वर्ग को अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं. अन्ना को इस बात से तकलीफ है कि एक तरफ जहां सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले वक्तव्य आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कामगार क़ानून में बदलाव कर मेहनत करने वालों के बुरे दिन लाए जा रहे हैं. इन दिनों अन्ना से मिलकर देश के किसान संगठन भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन वाले अध्यादेश को लेकर बात कर रहे हैं. किसान इससे चिंतित हैं और इस क़ानून के विरोध में आंदोलन करना चाहते हैं. इस सिलसिले में वे अन्ना हजारे से नेतृत्व करने को कह रहे हैं. अन्ना हजारे ने इस पर कहा है कि यह ऑर्डीनेंस लोकतांत्रिक दृष्टि से कतई ठीक नहीं है और इससे किसानों का दमन होगा. अन्ना हजारे सरकार को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सरकार को वक्त रहते ये बातें समझ लेनी चाहिए. वे देश के किसानों को आश्वस्त करते हैं कि वे लोकपाल के साथ-साथ इस प्रश्न पर भी आंदोलन करेंगे, सभी किसान संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे और किसानों के हक़ के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे. अन्ना हजारे कहते हैं कि किसानों के लिए आंदोलन जरूर करूंगा, क्योंकि मै भी एक किसान का बेटा हूं. पिछले कुछ दिनों में अन्ना हजारे के बयानों से इस बात के संकेत मिलते हैं कि अन्ना हजारे अब चुपचाप बैठ कर सब कुछ देखने के मूड में नहीं हैं. अन्ना ने अपनी नई टीम के गठन की बात की है. अब इस नई टीम में कौन-कौन लोग शामिल होते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा. अन्ना ने देशवासियों को फिर एक बार आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की है.

अन्ना हजारे ने अपने ब्लॉग में एक लेख के जरिए मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है. मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को अन्ना हजारे ने किसानों के खिलाफ बताते हुए मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया है. अन्ना ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि इस क़ानून का मक़सद कृषि योग्य भूमि को उद्योगपतियों के हवाले करना है. अन्ना ने सवाल उठाया कि भूमि अधिग्रहण क़ानून से किसका भला होने वाला है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ग्राम सभा के अधिकारों को कम करके लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है. अन्ना ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि आज़ादी के 68 साल बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

> अन्ना हजारे ने अपने ब्लॉग में एक लेख के जरिए मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है. मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को अन्ना हजारे ने किसानों के खिलाफ बताते हुए मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया है. अन्ना ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि इस क़ानून का मक़सद कृषि योग्य भूमि को उद्योगपतियों के हवाले करना है.

नए भूमि अधिग्रहण क़ानून से किसानों की आत्महत्याएं बढ़ने की आशंका है. विकास के नाम पर मोदी सरकार किसानों के साथ धोख़ा कर रही है. उन्होंने लिखा है कि भूमि अधिग्रहण क़ानून में से किसानों की रज़ामंदी की शर्त हटाना गलत है. सरकार लोकहित नज़रअंदाज़ कर मनमर्ज़ी से फैसले ले रही है. पुराने क़ानून को सही बताते हुए अन्ना ने ब्लॉग में लिखा कि इसमें यह प्रावधान था कि अधिग्रहित भूमि पर अगर पांच साल में विकास कार्य नहीं हुआ तो वह ज़मीन किसानों को वापस मिल जाती थी, पर सरकार ने यह शर्त हटाकर किसान से ज़मीन छीनकर उद्योगपतियों को ज़मीन का स्थाई मालिक बना दिया है. मोदी सरकार ने राष्ट्रहित के नाम पर अपने चहेते लोगों के हित साधने का

(शेष पृष्ठ 2 पर)

इस बार कहां तक आएंगे पीवी राजगोपाल...

नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर एकता परिषद के पी.वी. राजगोपाल ने एक बार फिर एक और आंदोलन यानी अपने स्टाइल में पदयात्रा की घोषणा कर दी है. राजगोपाल ने कहा है कि वे हज़ारों सत्याग्रहियों के साथ भू-अधिग्रहण अध्यादेश के ख़िलाफ 15 मार्च 2015 से पदयात्रा करते हुए आगरा से दिल्ली के लिए कूच करेंगे. राजगोपाल के मुताबिक कॉरपोरेट घरानों के हित के लिए केंद्र सरकार जिस तरह जल्दबाज़ी में जनविरोधी अध्यादेश ला रही है, ऐसे में संघर्ष को तेज़ करने की ज्यादा जरूरत हो गयी है. उन्होंने एक बार फिर से आगरा से दिल्ली तक पदयात्रा की तैयारी शुरू कर दी है. अब केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुर्नस्थापन में उचित क्षतिपूर्ति के अधिकार और पारदर्शिता क़ानून 2013 में लाए गए संशोधनों का एकता परिषद विरोध कर रही है. एकता परिषद के मुताबिक यह अध्यादेश अन्यायपूर्ण व किसान विरोधी है. 2012 में हुए भूमि सुधार समझौते को लागू कराने एवं संशोधन बिल 2014 को रद्द करने की मांग की गई है. मांग पूरी नहीं होने पर हज़ारों की संख्या में पुनः आदिवासी भूमिहीन दिल्ली के लिए पदयात्रा शुरू करने वाले हैं.

एकता परिषद के मुताबिक भारतीय संविधान में अनु. 39बी में प्राकृतिक संपदाओं पर नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रावधान हैं, यह अध्यादेश इन प्रावधानों को ख़ारिज करता है. कोई भी निर्वाचित सरकार न्यायोचित ढंग से ऐसा कृत्य नहीं कर सकती है, ऐसा अध्यादेश केवल विशेष परिस्थिति में या आपातकालीन स्थिति में ही जारी होता है. सरकार ने न तो संसद में और न जनता के सामने ऐसा कोई कारण दर्शाया है, तो फिर ऐसे अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ी? यह सच्चाई देश की जनता के सामने लाना जरूरी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस पदयात्रा का नतीजा क्या निकलेगा? इससे पहले भी पीवी राजगोपाल कई यात्राएं कर चुके हैं. पीवी राजगोपाल वर्ष-2007 में भी 25 हजार आदिवासियों और किसानों को लेकर ग्वालियर से दिल्ली तक पैदल आए थे. लेकिन दिल्ली से पहले ही हरियाणा के पलवल/फरीदाबाद में तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह वहां पहुंच गए. तब रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक सुचारू भूमि वितरण प्रणाली विकसित करने व लोगों को जमीनों का अधिकार देने की मांग को मंजूर किया था. जनसत्याग्रह आंदोलन 2012 के वक्त भी उनकी यह यात्रा बीच में ही रुक गई थी. केंद्र सरकार ने आगरा में रोक कर वार्ता की थी. तब सरकार के प्रतिनिधि तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश तथा जनसत्याग्रह 2012 के लीडर पीवी राजगोपाल के बीच देश में भूमि सुधार को लेकर 10 सूत्रीय समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत जो काम होने थे वे नहीं हुए. ■

वक्फ संपत्तियों पर ख़तरे के बादल
पेज-03

कितनी कारगर होगी, नई शिक्षा नीति
पेज-04

क्या सुधर पाएगी बदहाल स्वास्थ्य सेवा
पेज-06

साई की महिमा
पेज-12

किसानों की ज़मीन छीनी तो फिर आंदोलन होगा

पृष्ठ एक का शेष

रास्ता साफ किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार के इस अध्यादेश में और अंग्रेजों के दमनकारी शासन में क्या फर्क है?

इसके अलावा, अन्ना ने लोकपाल के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को खरी–खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा है कि देश में दिन प्रति–दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, सामान्य लोगों का जीना मुश्किल हो गया था. इस लिए देश की जनता ने लोकपाल, लोकायुक्त के लिए आंदोलन किया. ग़ौरतलब है कि लोकपाल क़ानून को 1 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है. क़ानून के प्रावधान के मुताबिक एक वर्ष के अंदर लोकपाल की नियुक्ति होना अनिवार्य है. लेकिन, अब तक ऐसा नहीं हो सका है. अब तक न तो केंद्र में लोकपाल का गठन हुआ है और न ही राज्यों में इस क़ानून के आधार पर लोकायुक्त का गठन हो सका है. अन्ना हजारे कहते हैं कि आज जो सत्ता में है, तब बड़े जोर शोर के साथ लोकपाल का समर्थन करते थे. तत्कालीन राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे अरुण जेटली ने पत्र लिख कर मुझे समर्थन दिया था. लेकिन मुझे आश्चर्य है कि जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली, सरकार ने लोकपाल के प्रति अपने रवैये में बड़ा यू टर्न ले लिया और सरकार के कामकाज संभाले हुए आठ महीने बीतने के बाद भी लोकपाल का गठन नहीं हुआ. अन्ना सरकार से सवाल करते हैं कि सरकार को खुलकर लोगों के सामने आना चाहिये और बताना चाहिये की

लोकपाल और भूमि अधिग्रहण के अलावा अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार पर काला धन के मामले में भी तल्ख़ टिप्पणी की है. अन्ना हजारे ने ऐसे काले धन को देश में गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा किया हुआ बताया है. अन्ना हजारे ने सरकार को यह भी याद दिलाया है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व आपने अपने प्रचार द्वारा देश को आश्वस्त किया था कि आपकी सरकार सत्ता में आने के बाद 100 दिनों मे काला धन वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध होगी. सरकार बनने के बाद एक एसआईटी के गठन की घोषणा भी की थी जिसके कारण लोगों की उम्मीद बढ़ रही थी. अन्ना हजारे, केंद्र सरकार पर इस बात के लिए आरोप लगाते हैं कि सौ दिनों में काला धन वापस लाने की घोषणा करते समय इसकी राह में आने वाली कठिनाईयों के बारे में सोचा जाना चाहिए था.

भाकियू भी करेगा आंदोलन

भारतीय जनता पार्टी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से देश के किसान संगठन नाराज़ हैं और मार्च के महीने में जंतर–मंतर, नई दिल्ली में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं. किसान आंदोलन की समन्वय समिति से सम्बद्ध देश के किसान संगठनों की दो दिन की बैठक पंजाब भवन नई दिल्ली में श्री अजमेर सिंह लाखोवाल की अध्यक्षता में हुई. इसमें किसानों के मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में भाकियू के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसान प्रतिनिधियों के साथ–साथ तमिलनाडु फार्मर एसोशिएशन, कर्नाटक राज्य रैयत संघ के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और 18 मार्च 2015 को होने वाली किसान पंचायत में लाखों किसानों की उपस्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की गई. 9 सूत्रीय एजेंडा के तहत सबसे पहले भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की बात है. भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में किसानों को बदलाव मंजूर नहीं है. इसके अलावा, किसानों को फसलों का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिए जाने की बात कही जा रही है. किसानों को उनकी उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत जोड़कर स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसलों का उचित एवं लाभकारी मूल्य देने की मांग की गई है. भारतीय किसान यूनियन शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों को भी नामंजूर कर रहा है. देश के किसान संगठन मानते हैं कि भारतीय खाद्य निगम को लेकर गठित शांताकुमार हाईलेवल कमेटी रिपोर्ट पूर्णत: किसान विरोधी व खाद्य सुरक्षा विरोधी है. शांता कुमार कमेटी की सभी सिफारिशों को नामंजूर करने की मांग भी की जा रही है. यूनियन किसानों का कर्जा पूर्णत: माफ किए जाने की मांग भी कर रहा है. देश में किसानों की आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. प्राकृतिक आपदाओं पर केंद्रीय नीति बनाने की मांग भारतीय किसान यूनियन कर रहा है. देश के किसानों की मांग है कि दूसरे वर्ग की तरह किसान परिवार की भी न्यूनतम आमदनी तय की जाए. इसके लिए एक किसान आय आयोग का गठन किया जाए. इसके द्वारा निश्चित किया जाए कि एक किसान परिवार की आमदनी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से कम न हो.

किसान यूनियन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषणा पत्र में वायदा किया गया था कि हम जैव परिवर्तित फसलों के प्रदर्शन, व्यापारीकरण और जैव परिवर्तित बीज, फसल और पौधों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. हमारी मांग है कि इस मुद्दे पर सरकार अपने किये गये वायदे को पूरा करें. इस 9 सूत्रीय एजेंडे के तहत गन्ना किसानों का भुगतान करने की मांग भी की गई है. देश के सभी राज्यों में पिछले दो वर्षों से गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है और न ही गन्ना किसानों को उनकी फसलों का भुगतान किया जा रहा है. भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि सरकार गन्ना किसानों को अविलंब उनका भुगतान करे. यूनियन के मुताबिक मुक्त व्यापार समझौतों में कृषि के मुद्दों पर कोई भी समझौता–वार्ता न की जाए. भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि देश का किसान पूर्णत: भारतीय जनता पार्टी सरकार की किसान नीतियों से सरोकार नहीं रखता है. पिछले 240 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसानों के विरोध में कई फैसले किए गए हैं. भारतीय किसान आंदोलन की समन्वय समिति ने देश के सभी संगठनों के साथ मिलकर 18 मार्च 2015 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी किसान महापंचायत करने का फैसला लिया है. इस पंचायत में देश की सरकार पर किसानों के हक़ में फैसले लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा. ■

क्या है भूमि अधिग्रहण अध्यादेश

नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के तहत अब ज़मीन अधिग्रहण के लिए 80 फ़ीसद किसानों की रज़ामंदी आवश्यक नहीं होगी. इसका अर्थ है कि सरकार जहां की भी ज़मीन, जितनी भी ज़मीन चाहेगी, उसका अधिग्रहण कर पाने में सक्षम हो जाएगी. ज़ाहिर है, विकास के नाम पर टाउनशिप, अस्पताल, होटल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाने का काम निजी कंपनियां करेंगी. उन्हें इस अधिग्रहीत ज़मीन से फ़ायदा होगा. मुनाफ़ा उक्त कंपनियां कमाएंगी. सवाल है कि क्यों नहीं ज़मीन की खरीद–बिक्री सीधे किसानों के ज़रिये कराने की कोशिश की जा रही है. दूसरी बात यह कि ऐसे संशोधन के बाद विकेंद्रीकृत सत्ता यानी ग्रामसभा जैसी संस्था की महत्ता क्या रह जाएगी? लोकतंत्र में जन–सहमति का क्या मतलब रहेगा? संसद की स्थाई समिति ने भी भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल (यूपीए–2 के वक्त) में कहा था कि किसी भी निजी अथवा पीपीपी प्रोजेक्ट, जिसे सार्वजनिक उद्देश्य के प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित न किया गया हो, के लिए ज़बरदस्ती ज़मीन का अधिग्रहण न किया जाए. लेकिन, तब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थाई समिति के इस सुझाव को सिरे से नकार दिया था. तब मंत्रालय ने कहा था कि किसी भी निजी प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले 80 फ़ीसद लोगों की सहमति मिलने पर ज़मीन अधिग्रहीत कर ली जाएगी. अब मौजूदा सरकार ने पीपीपी परियोजनाओं के लिए इस 80 फ़ीसद सहमति वाले प्रावधान को भी ख़त्म कर दिया है. इस संशोधन के ज़रिये कुछ ख़ास परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण से होने वाले सामाजिक प्रभाव के आंकलन वाले प्रावधान को हटा दिया गया है. जबकि ज़रूरी यह है कि किसी भी काम के लिए होने वाले ज़मीन अधिग्रहण से भविष्य में पड़ने वाले सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभाव का आंकलन किया जाना चाहिए. अधिग्रहीत की गई ज़मीन की वापसी को लेकर भी कई सवाल हैं. अनुभव यह बताता है कि ऐसी बहुत–सी अधिग्रहीत ज़मीनें हैं, जिनका इस्तेमाल 25 सालों तक नहीं हुआ और फिर भी वे इनके पुराने मालिकों को नहीं लौटाई गईं. ■

लोकपाल से वह इतना डरती क्यों है और अगर डरती नहीं है तो फिर क्या कारण है कि लोकपाल गठित नहीं हो रहा है? लोकपाल के गठन को लेकर अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री को अब तक तीन पत्र भी लिखे हैं. पहला पत्र 27 अगस्त 2014 , दूसरा पत्र 18 अक्टूबर 2014 और तीसरा पत्र 1 जनवरी 2015 को लिखा गया है. लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री या इनके कार्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, सिर्फ पत्र प्राप्त होने की जानकारी दी गई.

लोकपाल और भूमि अधिग्रहण के अलावा अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार पर काला धन के मामले में भी तल्ख़ टिप्पणी की है. अन्ना हजारे ने ऐसे काले धन को देश में गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा किया हुआ बताया है. अन्ना हजारे ने सरकार को यह भी याद दिलाया है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व आपने अपने प्रचार द्वारा देश को आश्वस्त किया था कि आपकी सरकार सत्ता में आने के बाद 100 दिनों मे काला धन वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध होगी. सरकार बनने के बाद एक एसआईटी के गठन की घोषणा भी की थी जिसके कारण लोगों की उम्मीद बढ़ रही थी. अन्ना हजारे, केंद्र सरकार पर इस बात के लिए आरोप लगाते हैं कि सौ दिनों में काला धन वापस लाने की घोषणा करते समय इसकी राह में आने वाली कठिनाईयों के बारे में सोचा जाना चाहिए था. अन्ना ने यह भी कहा है कि कहां तो सौ दिन के भीतर लोगों के खाते में 15 लाख रुपये आने वाले थे और आए एक भी पैसे नहीं. अन्ना इन वादों पर सवाल उठाते हैं कि क्या वे वादे महज़ एक चुनावी घोषणा भर थे? अन्ना इसे कथनी और करनी का अंतर बताते हैं. अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में यह भी कहा है कि मैंने विगत 35 सालों में कई आंदोलन किए, लेकिन किसी व्यक्ति या पक्ष अथवा पार्टी के विरोध में नहीं, केवल समाज और देश की भलाई के लिए. काला धन वापस लाना देश का अहम मुद्दा है और जरूरत होने पर मै इस मुद्दे पर फिर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटूंगा. बहरहाल, अन्ना की इस चेतावनी को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, अन्ना की नई टीम कैसी होती है, क्या अन्ना सचमुच आंदोलन करेंगे, क्या देश के किसान, आम आदमी और किसान संगठन अन्ना के समर्थन में आएंगे, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 50
दिल्ली, 16 फरवरी–22 फरवरी 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

> वक्फ बोर्ड की स्थापना के बाद वक्फ संपत्तियों, विशेषकर उन धार्मिक स्थलों की वापसी की मांग जोर पकड़ने लगी, जो अधिग्रहण होने के बावजूद बोर्ड की देखभाल एवं निगरानी या मुसलमानों के इस्तेमाल में थीं. तब 1970 के दशक में केंद्र सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी, जिसकी रिपोर्ट सैय्यद मुजफ्फर हुसैन बर्नी के नेतृत्व में तैयार हुई, जिसे बर्नी रिपोर्ट भी कहते हैं. इस कमेटी ने ऐसी 250 संपत्तियां चिन्हित कीं, जो वक्फ की थीं. इस रिपोर्ट पर अमल करने के लिए मीर नसीरुल्लाह के नेतृत्व में एक और कमेटी गठित की गई, जिसने इन 250 संपत्तियों में से 123 ऐसी संपत्तियों का खुलासा किया, जिन्हें वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया जा सकता था.

दिल्ली
वक्फ संपत्तियों पर ख़तरे के बादल

> इस्लाम के प्रावधान के अनुसार, जब कोई संपत्ति जनकल्याण के लिए विशेष रूप से दान की जाती है, तो उसे वक्फ संपत्ति कहा जाता है. ऐसी संपत्तियां महान उद्देश्य के लिए वक्फ की जाती हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इनका राजनीतिक और अन्य स्वार्थों के लिए बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई में मस्जिद व यतीम खाना की वक्फ संपत्ति को प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के हाथों बेचा जाना है. इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी चुप्पी साधे है, बल्कि उसके वरिष्ठ सदस्य एवं क़ानूनी सलाहकार यूसुफ हातिम मुछाला उसमें शरीक भी हैं. जहां तक दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियों का सवाल है, वे भी राजनीतिक और क़ानूनी पेचीदगियों में पिछले सौ वर्षों से उलझी हुई हैं. आइए देखते हैं कि दिल्ली की इन वक्फ संपत्तियों का मामला क्या है...

ए यू आसिफ

मैं ने माना कि कुछ नहीं गालिब
मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है...

भारत की छह लाख एकड़ भूमि पर फैली हुई 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों में से अधिकतर की स्थिति दयनीय है. स्वार्थी तत्वों की नज़र हमेशा से इन पर रही है और आज भी है, क्या सरकारी और क्या ग़ैर सरकारी. हद तो यह है कि संपत्ति दान करने वाले की मंशा के विरुद्ध इन पर नाजायज कब्जे हैं और ऐसा महसूस होता है कि हर एक व्यक्ति बकौल मिर्जा गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है...पर अमल कर रहा है. आश्चर्य की बात तो यह है कि मुसलमान, उनके कुछ संगठन और संस्थान भी अवैध कब्जेदारों की सूची से बाहर नहीं हैं. दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियां, जो पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार द्वारा डी–नोटिफिकेशन के निर्णय के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन प्राय: एक वर्ष पूर्व आ चुकी हैं, का भी कमोबेश यही हश्र हो रहा है.

यही वजह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष राणा परवीन सिद्दीकी को सारे जहां से नाराज़गी और शिकायत है. उन्हें शिकायत सरकार, प्रशासन, मुसलमानों एवं उनके कुछ संगठनों से भी है. उन्हें इस बात की शिकायत है कि इन 123 वक्फ संपत्तियों में से आईटीओ स्थित मस्जिद अब्दुन नबी एवं मस्जिद गौसियान उर्फ झील के प्याऊ पर जमीयतुल उलमा हिंद के दोनों धड़े उसके आसपास की भूमि समेत काबिज हैं. दिल्ली वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष सिद्दीकी, जो प्रसिद्ध वकील भी हैं, का कहना है कि 123 वक्फ संपत्तियों को बोर्ड को ट्रांसफर करने के संबंध में दो मार्च, 2014 के मनमोहन सिंह सरकार के निर्णय पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जांच शुरू कराना समझ से परे है. उनका कहना है कि ये तमाम संपत्तियां दान की हुई हैं, इसलिए 104 वर्ष के बाद उनकी वापसी पर जांच की आख़िर आवश्यकता क्यों आ पड़ी. उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने 22 मई, 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अब जांच शुरू की है. वह कहती हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड भी अपना पक्ष न्यायालय के सामने जल्द ही पेश करेगा.

इस विवाद का विश्लेषण करते समय यह समझना आवश्यक है कि दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियां आख़िर हैं क्या. ग़ौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने 1911–15 में कोलकाता से हटकर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाते समय यहां के विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहण किया था, जिनमें बहुत–सी भूमि मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों एवं अन्य वक्फ की भी थीं, जिन्हें बिना अलग किए हुए सरकार के अधीन कर लिया गया. इसके विरुद्ध मुकदमे भी किए गए. यही कारण है कि दिल्ली मजलिस औकाफ, जिसका उत्तराधिकारी दिल्ली वक्फ बोर्ड है, ने औकाफ की भूमि का मुआवज़ा लेने से इंकार कर दिया था. देश आज़ाद होने के बाद तक उक्त मुकदमे विभिन्न अदालतों में लटके रहे.

वक्फ बोर्ड की स्थापना के बाद वक्फ संपत्तियों, विशेषकर उन धार्मिक स्थलों की वापसी की मांग जोर पकड़ने लगी, जो अधिग्रहण होने के बावजूद बोर्ड की देखभाल एवं निगरानी या मुसलमानों के इस्तेमाल में थीं. तब 1970 के दशक में केंद्र सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी, जिसकी रिपोर्ट सैय्यद मुजफ्फर हुसैन बर्नी के नेतृत्व में तैयार हुई, जिसे बर्नी रिपोर्ट भी कहते हैं. इस कमेटी ने ऐसी 250 संपत्तियां चिन्हित कीं, जो वक्फ की थीं. इस रिपोर्ट पर अमल करने के लिए मीर नसीरुल्लाह के नेतृत्व में एक और कमेटी गठित की गई, जिसने इन 250 संपत्तियों में से 123 ऐसी संपत्तियों का खुलासा किया, जिन्हें वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया जा सकता था. सरकार ने 1984 की शुरुआत में निर्णय लिया कि इन 123 संपत्तियों का मालिकाना हक़ दिल्ली वक्फ बोर्ड को वापस कर दिया जाए. इस संबंध में 27 मार्च, 1984 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया. उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं. सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पूर्व सेक्रेटरी डॉ. मोहम्मद रिजवानुल हक़ कहते हैं कि उस समय दो ग़लत घटनाएं हुईं. नोटिफिकेशन प्रकाशित होने से दो दिनों पहले यह बात मीडिया तक पहुंच गई, जिसके कारण एक दिन पहले यह ख़बर इस तरह प्रकाशित की गई कि सरकार इन संपत्तियों को एक रुपये वार्षिक प्रति एकड़ की दर से लीज पर दे रही है. दूसरी घटना यह हुई कि नोटिफिकेशन में इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपने के बजाय एक रुपये वार्षिक प्रति एकड़ की दर से उसी बोर्ड को लीज पर देने की बात कही गई, जो पूर्ण रूप से सही नहीं थी, बल्कि सरकार के निर्णय एवं मंशा के विरुद्ध भी थी. उस समय मोहसिना किदवई संबंधित मंत्रालय की मंत्री थीं.

इन दोनों घटनाओं का प्रभाव यह पड़ा कि रातोंरात एक संगठन इंद्रप्रस्थ हिंदू महासभा के नाम से अस्तित्व में आ गया और उसने नोटिफिकेशन जारी होते ही दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और उस पर स्थगनादेश ले लिया. यह स्थगनादेश 27 वर्षों तक कायम रहा. डॉ. रिजवानुल हक़, जो उस समय सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सचिव थे, ने चौथी दुनिया को बताया कि उस समय सेंट्रल वक्फ काउंसिल के आग्रह पर सात अप्रैल, 2008 को केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी के चैंबर में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें वह स्वयं भी मौजूद थे. मंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में ज़रूरी फ़ैसले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा ही लिए जा सकते हैं. इस तरह केंद्र सरकार इस मसले पर टाल–मटोल करती रही. तब दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जनवरी, 2011 को 123 वक्फ संपत्तियों से संबंधित इंद्रप्रस्थ हिंदू महासभा की याचिका सी–1512/1984 खारिज कर दी और सरकार को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में छह माह के अंदर अंतिम फ़ैसला करे, लेकिन सरकार समय पर समय लेती रही.

बहरहाल, इस संबंध में मनमोहन सिंह सरकार ने दो मार्च, 2014 को अंतिम निर्णय लेते हुए इन 123 वक्फ संपत्तियों को डी–नोटिफाई किया और दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ट्रांसफर कर दिया. तब विश्व हिंदू परिषद ने 22 मई, 2014 को याचिका दायर की और कहा कि उक्त संपत्तियों का दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर भूमि अधिग्रहण क़ानून के सेक्शन 48 का उल्लंघन है. विश्व हिंदू परिषद का दावा था कि संपत्तियां, जो सरकार द्वारा अधिग्रहण करके कब्जे में ली गई हैं, को न डी–नोटिफाई किया जा सकता है और न उन्हें अधिग्रहण से आज़ाद किया जा सकता है. इस संबंध में वर्तमान शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू का कहना है कि उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के विरुद्ध एक रिप्रेजेंटेशन मिला है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वह इन संपत्तियों के ट्रांसफर में सबसे आगे थे. शहरी विकास मंत्रालय की राय है कि उस वक्त पूरा निर्णय जल्दबाजी में लिया गया, इसलिए मंत्रालय ने क़ानून मंत्रालय से इस संबंध में लिखित राय मांगी है.

ज्ञात रहे कि गत वर्ष डी–नोटिफिकेशन के समय इन 123 वक्फ संपत्तियों में 61 लैंड एवं डेवलपमेंट ऑफिस, जबकि बाकी 22 दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन थीं. इनमें से कुछ तो सरकार के इस्तेमाल में थीं, तो कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों एवं व्यक्तियों के कब्जे में थीं. इन वक्फ संपत्तियों में से अधिकतर कनाट प्लेस, मथुरा रोड, लोदी रोड, मान सिंह रोड, पंडारा रोड, अशोक रोड, जनपथ, संसद भवन, करोल बाग, सदर बाज़ार, आज़ाद मार्केट, दरियागंज, आईटीओ एवं जंगपुरा में स्थित हैं. प्रत्येक वक्फ भूमि से मस्जिद सटी हुई है, जबकि कुछ संपत्तियों में दुकानें एवं आवासीय भवन भी हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि इन 123 वक्फ संपत्तियों पर एक बार फिर ख़तरे के बादल मंडरा रहे हैं. पिछली बार हिंदू महासभा ने 1984 में सरकार के नोटिफिकेशन पर स्थगनादेश ले लिया था, लेकिन 24 वर्षों के बाद 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सरकार इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति मानती है, तो उसे इन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप देना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जनवरी, 2011 को यह याचिका खारिज भी कर दी और सरकार को कोई अंतिम निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया. अब देखना यह है कि मार्च 2014 के अंतिम निर्णय को विश्व हिंदू परिषद की याचिका से जो चुनौती मिली है, उसका क्या होता है और अदालत इस संबंध में क्या निर्णय लेती है और इसी के साथ–साथ वर्तमान सरकार का रुख भी क्या होता है? ■

वक्फ संपत्तियों से खिलवाड़ बंद हो

विश्व हिंदू परिषद द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को लेकर विभिन्न पक्षों की बैठक बुलाने का निर्देश न्यायालय ने दिया है. इस निर्देश पर अमल करने से पूर्व मोदी सरकार ने यह जांच शुरू कर दी है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने जाने से पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियां सौंपने का जो निर्णय लिया था, कहीं वह ग़ैर क़ानूनी तो नहीं है. इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव डॉ. मोहम्मद मंजूर आलम कहते हैं कि सरकार को इस मामले में राजनीति के बजाय अदालती निर्देश पर अमल करना चाहिए, वरना वक्फ के महान उद्देश्य के साथ खिलवाड़ होगा और न्यायालय की अवमानना भी. उनका मानना है कि इस तरह की राजनीति के ज़रिये 103 वर्षों के बाद सुलझा मामला एक बार फिर से उलझाया जा रहा है. मरकज़ी जमीअत अलेहदिस हिंद के महासचिव मौलाना असगर अली इमाम मेहंदी सल्फी मदनी का कहना है कि वक्फ के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है. जमाअत इस्लामी हिंद के महासचिव मौलाना नुसरत अली कहते हैं कि जब पूर्व केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशानुसार निर्णय लिया था, तो फिर किसी विवाद की आवश्यकता ही नहीं थी. उनका कहना है कि यह समस्या बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए सरकार न्यायालय के निर्देशानुसार ही इसे सुलझाए. बिहार राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डॉ. एमए इब्राहिमी, जिनकी आईएएस अधिकारी के तौर पर वक्फ की समस्या पर गहरी नज़र रही है, कहते हैं कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध जनकल्याण से है. इब्राहिमी ने चौथी दुनिया से बात करते हुए कहा कि यही कारण है कि उन्होंने इस संबंध में अपने व्यवहारिक तजुर्बे माई एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस में बताए हैं. उनका साफ़ तौर पर कहना है कि 123 वक्फ संपत्तियों का मामला अदालत पर छोड़ देना चाहिए. 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इंद्रप्रस्थ हिंदू महासभा की 1984 की याचिका भलीभांति निपटाई. इसलिए उम्मीद है कि 2014 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा दायर याचिका भी अदालत उसी तरह निपटाएगी, तभी इस मामले में इंसाफ़ हो पाएगा. ■

वक्फ आख़िर क्या है

पैगंबर मोहम्मद के कथित हदीस में वक्फ की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि मूल को इस तरह ख़ैरात में दो कि वह न बेची जा सके, न उसे उपहार में दिया जा सके और न उसमें विरासत का सिलसिला जारी हो, बल्कि उसके फ़ायदे आम लोगों को मिलें. उक्त हदीस के अनुसार, पूरे संसार में मुसलमानों में वक्फ करने का सिलसिला जारी है और यह जनकल्याण का एक लाभदायक एवं प्रभावकारी साधन बना हुआ है. जहां तक भारत का मामला है, 17 नवंबर, 2006 को मनमोहन सिंह सरकार को सौंपी गई सच्चर रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में छह लाख एकड़ भूमि पर 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी क़ीमत पिछले वर्ष छह हजार करोड़ रुपये आंकी गई थी और उनसे सालाना आमदनी कम से कम 163 करोड़ रुपये बताई गई थी. इसी रिपोर्ट में दिल्ली की 318 वक्फ संपत्तियों की सूची भी प्रकाशित की गई है और उन पर तमाम कब्जों को ग़ैर क़ानूनी बताया गया है. इन्हीं में इस समय विवादास्पद दिल्ली की 123 वक्फ सपंत्तियां भी शामिल हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अब अगर हम मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति से संबंधित वर्तमान पहल की तुलना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से करें, तो इसमें अधिकतर विषय तो पुराने ही हैं. हालांकि, इन विषयों को वर्तमान परिस्थितियों के तहत विस्तृत करने की कोशिश की गई है. उदाहरण के तौर पर, शिक्षा का अधिकार क़ानून लागू होने के बाद अब देश भर के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश देने का दबाव पड़ने लगा है. इसी के मद्देनज़र मोदी सरकार ने लोगों से राय मांगी है कि कैसे इस समस्या को बेहतर ढंग से हल किया जाए.

कितनी कारगर होगी, नई शिक्षा नीति

क़मर तबरेज़

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 29 वर्षों के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति बनाने जा रही है, जिसके लिए उसने देश-विदेश के विद्वानों, शिक्षाविदों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों से इस क्षेत्र के 33 विभिन्न विषयों के तहत सुझाव आमंत्रित किए हैं. उक्त सभी 33 विषयों की सूची केंद्र सरकार की वेबसाइट ु.ग्रूर्सी.ळप पर बीती 25 जनवरी को अपलोड की गई है, ताकि लोग सरकार को प्रत्यक्ष रूप से अपने सुझाव एवं प्रस्ताव भेज सकें. सरकार सभी सुझावों एवं प्रस्तावों को इसी वर्ष जून में राष्ट्रीय शिक्षा समिति के सामने रखेगी. इसके बाद समिति उक्त सभी सुझावों एवं प्रस्तावों की रौशनी में एक नई शिक्षा नीति बनाएगी, जिसे आने वाले दिनों में देश भर में लागू किया जाएगा. फिलहाल पूरे भारत में राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है, जिसमें 1992 में थोड़ा-बहुत संशोधन किया गया था. इससे पूर्व स्वतंत्र भारत में पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई थी. नई शिक्षा नीति से संबंधित मोदी सरकार की इस पहल पर बात करने से पहले आइए देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश राज में भारत में शिक्षा की क्या स्थिति थी.

हम सभी यह जानते हैं कि अंग्रेज भारत में एक व्यापारी के रूप में आए थे. उस समय भारत में मुगलों का शासन था. मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत व्यापार करने की मंज़ूरी हासिल करने बाद अंग्रेजों ने पूरे देश भर में अपनी व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर दीं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने मुगलों को शिकस्त देने के बाद भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया. शुरुआत में अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई. अंग्रेजों द्वारा 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज और 1781 में कलकत्ता मदरसा इसलिए स्थापित किया गया, ताकि इन दोनों जगहों से हिंदुओं एवं मुसलमानों के धार्मिक क़ानूनों के विशेषज्ञ तैयार किए जा सकें, जो अदालती कार्यवाही में अंग्रेजी हुकूमत की मदद कर सकें. लेकिन, समय जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ईसाई मिशनरियों और कुछ भारतीयों की ओर से आधुनिक शिक्षा विकसित करने के लिए दबाव बढ़ने लगा. आख़िरकार ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 के चार्टर एक्ट के रूप में भारतीयों की शिक्षा के लिए पहला क़ानून लेकर आई. इस क़ानून के तहत पहली बार भारत में मॉर्डन साइंस के विकास और उच्च शिक्षा के शौकीन भारतीयों का साहस बढ़ाने के लिए वार्षिक एक लाख रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अंग्रेज सरकार के सामने दो बड़े सवाल खड़े हो गए.

पहला सवाल यह था कि क्या भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा दी जाए या फिर पारंपरिक भारतीय शिक्षा आगे बढ़ाई जाए? दूसरा सवाल यह था कि उन्हें यह शिक्षा भारतीय भाषाओं में ही दी जाए या फिर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए? इन दोनों सवालों का जवाब 1835 में उस समय मिला, जब थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने भारतीयों की शिक्षा से संबंधित 36 बिंदुओं पर आधारित अपना एक प्रस्ताव तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के सामने रखा. मैकाले ने उस प्रस्ताव में न केवल अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया, बल्कि भारतीयों को आधुनिक विज्ञान पढ़ाने की भी भरपूर वकालत की, लेकिन उस प्रस्ताव की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसमें आम भारतीयों की शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था. इसके उलट अंग्रेज भारतीयों में से कुछ ऐसे लोग तैयार करना चाहते थे, जो देखने में तो भारतीय लगें, लेकिन उनकी सोच और जीवनशैली अंग्रेजों जैसी हो. यही नहीं, अंग्रेजों ने उन भारतीयों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया, जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों एवं कॉलेजों से अपनी शिक्षा पूरी की हो. अंग्रेजों के ही ज़माने में इस कमी को उस समय दूर किया गया, जब 1854 में सर चॉर्ल्स वुड ने एक नया शिक्षा स्वरूप पेश किया, जो वुड्स डिसेच के नाम से मशहूर है. इसमें न केवल आम भारतीयों की शिक्षा पर ज़ोर दिया गया, बल्कि लड़कियों की शिक्षा, स्थानीय भाषा का सुधार एवं विकास और धर्म निरपेक्षता पर आधारित शिक्षा पर बल दिया गया. स्वतंत्रता के बाद जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, तो उसमें

वे 33 विषय, जिन पर सुझाव मांगे गए हैं

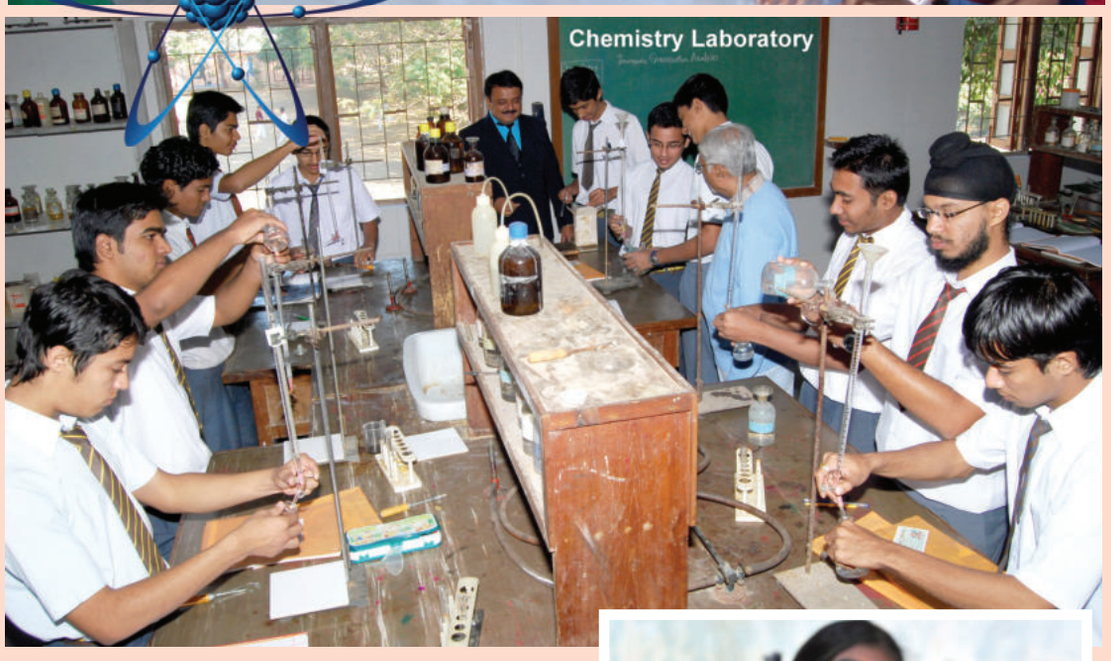

- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार.
- उच्च शिक्षा को समाज से जोड़ना.
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास
- राज्य लोक विश्वविद्यालयों में सुधार.
- गति निश्चित करने में केंद्रीय संस्थानों की भूमिका
- समावेशी शिक्षा को सक्षम बनाना. लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और विशेष ज़रूरतों के साथ बच्चों की शिक्षा.
- प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण साक्षरता में तेजी.
- स्कूल परीक्षा प्रणाली में सुधार.
- स्कूल के मानकों, स्कूल मूल्यांकन और स्कूल प्रबंधन प्रणाली में सुधार.
- नया ज्ञान.
- अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना.
- रोज़गार को शिक्षा से जोड़ने के लिए उद्योगों के साथ तालमेल.
- उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय प्रबंधन.
- भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना.
- सबसे अच्छे शिक्षक तैयार करना.
- क्षेत्रीय असमानता को दूर करना.
- संस्थाओं की रैंकिंग और प्रत्यायन
- नए ज्ञान, शिक्षण और स्कूलों में छात्रों को विज्ञान, गणित एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने के लिए बेहतर प्रणाली.
- व्यवसायिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना.
- प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार सुनिश्चित करना.
- उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण.
- निजी क्षेत्र के साथ सार्थक साझेदारी.
- लैंगिक और सामाजिक असमानता को पाटना.
- नियमन की गुणवत्ता में सुधार.
- व्यापक शिक्षा-नैतिकता, शारीरिक शिक्षा, कला एवं शिल्प, जीवन कौशल.
- स्कूल और वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों का प्रयोग.
- प्रौद्योगिकी सक्षमता हासिल करने के लिए अवसर.
- बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान.
- भाषाओं का विकास.
- शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए शिक्षक शिक्षा सुधार.
- मुक्त, दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना.
- गुणवत्ता के लिए प्रशासन में सुधार.
- छात्र समर्थन प्रणाली को बनाए रखना.

संविधान की धारा 45 को मद्देनज़र रखते हुए देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य मूल शिक्षा सुनिश्चित की गई. इसके अलावा अध्यापकों की बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण, हिंदी-अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास, सबको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने, विज्ञान की शिक्षा में शोध के साथ-साथ कृषि एवं व्यवसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया. इस नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में 1023 शिक्षा व्यवस्थाएं भी लागू की गईं. इससे पहले 1961 में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) स्थापित कर उसे पहली से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की ज़िम्मेदारी जवाहर लाल नेहरू के शासनकाल में दी जा चुकी थी, जो कि कमोबेश अब तक यह ज़िम्मेदारी निभा रही है. इसके बाद राजीव गांधी के शासनकाल में 1986 में दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई. इसके तहत शिक्षा तक सभी वर्गों की पहुंच पर सबसे अधिक ज़ोर दिया गया, विशेष रूप से महिलाओं एवं अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों की शिक्षा पर. इसके अलावा 1992 में एक नया संशोधन करके इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश के लिए पहली बार तीन परीक्षाओं की शुरुआत की गई, ज्वाइंट इंटर्न्स एग्जामिनेशन (जेईई) एवं ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंटर्न्स एग्जामिनेशन (एआईईईई) राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट लेवल इंजीनियरिंग इंटर्न्स एग्जामिनेशन (एसएलईईई) राज्य स्तर पर.

अब अगर हम मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति से संबंधित वर्तमान पहल की तुलना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से करें, तो इसमें अधिकतर विषय तो पुराने ही हैं. हालांकि, इन विषयों को वर्तमान परिस्थितियों के तहत विस्तृत करने की कोशिश की गई है. उदाहरण के तौर पर, शिक्षा का अधिकार क़ानून लागू होने के बाद अब देश भर के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश देने का दबाव पड़ने लगा है. इसी के मद्देनज़र मोदी सरकार ने लोगों से राय मांगी है कि कैसे इस समस्या को बेहतर ढंग से हल किया जाए. इसी तरह देश में दूसरी समस्या यह है कि लोग शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा कोई हुनर नहीं होता, जिसकी बुनियाद पर वे किसी उद्योग में नौकरी हासिल कर सकें. इसके लिए मोदी सरकार शुरू से ही हुनरमंदी के विकास (स्किल डेवलपमेंट) पर ज़ोर दे रही है. शिक्षा के क्षेत्र में भी उसकी कोशिश है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही अगर छात्रों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ दिया जाए, तो वे शिक्षा हासिल करने के बाद अच्छी नौकरियां पा सकेंगे और इस प्रकार बेरोज़गारी की समस्या हल की जा सकती है. इसके लिए उद्योग और शिक्षा के बीच तालमेल बनाने और पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल अपनाने की भी कोशिश की जा रही है.

स्वतंत्रता के बाद जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, तो उसमें संविधान की धारा 45 को मद्देनज़र रखते हुए देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य मूल शिक्षा सुनिश्चित की गई. इसके अलावा अध्यापकों की बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण, हिंदी-अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास, सबको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने, विज्ञान की शिक्षा में शोध के साथ-साथ कृषि एवं व्यवसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया. इस नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में 1023 शिक्षा व्यवस्थाएं भी लागू की गईं. इससे पहले 1961 में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) स्थापित कर उसे पहली से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की ज़िम्मेदारी जवाहर लाल नेहरू के शासनकाल में दी जा चुकी थी, जो कि कमोबेश अब तक यह ज़िम्मेदारी निभा रही है.

इसके पीछे दलील यह है कि हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए सरकारी मदद के साथ-साथ निजी क्षेत्र के सहयोग की भी आवश्यकता है, तभी सकारात्मक परिणाम आएंगे. इसके अलावा नई शिक्षा नीति में पहली बार नई शिक्षा प्राप्त करने पर भी ज़ोर दिया गया है. इसके तहत सरकार का यह प्रयास रहेगा कि पूरी दुनिया में नई-नई तकनीकों के आविष्कार के चलते शिक्षा के जो नए-नए माध्यम सामने आ रहे हैं, उन्हें चिन्हित करके भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में भी उन पर आधारित विभाग बनाए जाएं, ताकि भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया की इन तकनीकों से संबंधित आवश्यकताएं पूरी की जा सकें. इसके साथ ही भारत सरकार की पिछले कई वर्षों से एक चिंता यह भी रही है कि भारतीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड रैंकिंग में अपना स्थान नहीं बना पाते. लिहाजा, मोदी सरकार ने लोगों से यह राय भी मांगी है कि सरकार ऐसे कौन-से क़दम उठाए, जिनसे भारतीय विश्वविद्यालयों को वर्ल्ड रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त हो सके. इसके अलावा मोदी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन अध्यापक भी तैयार करना चाहती है, जो पूरी दुनिया में जाकर अपनी सेवाएं दे सकें और भारत के विश्वगुरु (वर्ल्ड टीचर) बनने का सपना साकार कर सकें.

अध्यापकों की बेहतर शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर 1968 और उसके बाद 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ज़ोर दिया गया था. अब इसमें विश्वगुरु शब्द का इज़ाफ़ा करके देश में बड़ी संख्या में ऐसे अध्यापक तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जो न केवल देश के स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा कर सकें, बल्कि वे गणित एवं विज्ञान भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पढ़ा सकें और ऐसे छात्र तैयार कर सकें, जो आगे चलकर गणित एवं विज्ञान के क्षेत्र में नए शोध आगे बढ़ाएं. अब देखना यह है कि सरकार कब तक इस नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देती है और उसने इसके लिए जो स्वरूप पेश किया है, वह कब तक व्यवहारिक रूप धारण कर पाता है. 29 वर्षों के बाद देश में शैक्षणिक ढांचा बेहतर बनाने की यह कोशिश इसलिए भी सराहनीय है, क्योंकि पुरानी शिक्षा व्यवस्था पर कायम रहते हुए हम भारत को विकासशील देशों की सूची में शामिल नहीं करा सकते. दुनिया भर में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन कुछ न कुछ नया ज़रूर होता है. अगर हमें दूसरे विकासशील देशों के साथ स्वयं को आगे बढ़ाना है, तो वक्त के साथ सामने आने वाली तब्दीलियों के अनुरूप खुद को अपडेट करना होगा और आने वाली नई नस्ल को भी.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

दोराहे पर खड़ी कांग्रेस

राधिका

बिहार में कांग्रेस का चिंतन शिविर ख़त्म होने के बाद भी कांग्रेसी नेताओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय यह बना हुआ है कि आख़िर वे करें, तो क्या करें? कांग्रेस हमेशा से अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है, लेकिन शायद कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी की बिहार में कोई रणनीति नहीं बन पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ-साथ कार्यकर्ताओं में भी असमंजस का दौर चल रहा है. कांग्रेस के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह आख़िर किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए काम करेगी. चिंतन शिविर के चारों दिन एक विचारधारा रखने वाली पार्टी के नेताओं के विचार अलग-अलग नज़र आ रहे थे. इसके साथ ही बिहार कांग्रेस प्रभारी भी कहीं न कहीं राज्य के नेताओं को समझाने में असमर्थ नज़र आ रहे थे. जहां एक तरफ़ बिहार कांग्रेस में फूट की बातें लगातार निकल कर सामने आ रही हैं, वहीं आलाकमान से लेकर प्रदेश के नेता तक असमंजस में पड़े हैं कि आख़िर जाएं, तो कहां जाएं.

बिहार में कई वर्षों से राजद के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात में जहां राजद एवं जदयू विलय की तैयारी में लगे हैं, वहीं कांग्रेस अब समझ नहीं पा रही है कि वह विधानसभा चुनाव में अकेले उतरे या फिर लालू एवं नीतीश के साथ गठबंधन करे. चिंतन शिविर में इशारों-इशारों में बिहार कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने यह कह दिया है कि पार्टी को बैसाखी की ज़रूरत है. दूसरी तरफ़ ज़मीनी कार्यकर्ता मैदान में अकेले उतरने की बात कर रहे हैं. यह बात तो साफ़ हो गई है कि बिहार में कांग्रेस की ज़मीन दिनोंदिन खिसकती जा रही है. विधानसभा चुनाव को लगभग सात महीने शेष रह गए हैं, लेकिन कांग्रेस दोराहे पर खड़ी नज़र आ रही है. इस संदर्भ में बिहार प्रदेश कांग्रेस की पूर्व महासचिव जया मिश्रा ने बताया कि पार्टी अपना काम कर रही है और वक्त के साथ लोगों को उसकी रणनीति भी पता चल जाएगी. रही बात बिहार में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर की, तो यह शिविर जनता के लिए नहीं, बल्कि कुछ गिने-चुने राजनेताओं के लिए आयोजित कराया गया था, इसलिए शिविर में ज़्यादा लोग नहीं दिखे. अब इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो कांग्रेस के नेता ही ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं. बहरहाल जो भी हो, कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिख रही है, जहां से वह आगे का रास्ता तय नहीं कर पा रही है. चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समीर सिंह ने कहा कि इस सिलसिले में सीपी जोशी ही बता सकते हैं. उन्होंने कहा कि सीपी जोशी राज्य के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क और राय-मशविरा करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे. उन्होंने बताया कि पार्टी के चिंतन शिविर में अधिकांश नेताओं ने बिना कोई गठबंधन किए अकेले चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है. प्रदेश कांग्रेस के नेता राजद से जुड़कर चुनाव लड़ने के ख़िलाफ़ हैं. उनका मानना है कि राजद के साथ लड़ने से पार्टी को नुक़सान के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा. जदयू से गठबंधन के सवाल पर समीर सिंह ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार और

लालू यादव सिर्फ़ साथ थे, तब तक नीतीश की छवि काफी अच्छी थी, पर लालू यादव से हाथ मिलाकर उन्होंने अपनी छवि भी दागदार कर ली है. इतना ही नहीं, समीर सिंह ने तो नीतीश को लालू से अलग होने का सुझाव तक दे दिया और कहा कि अगर अपनी छवि सही करनी है, तो उन्हें लालू का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब-जब लालू यादव की बात होती है, तब-तब राज्य की जनता को जंगलराज का भूत डराने लगता है.

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने यह बात खारिज कर दी कि कांग्रेस दोराहे पर खड़ी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के पास गई ही नहीं, तो खारिज कैसे बता दिया गया? दल का प्रदेश नेतृत्व भले दुविधाग्रस्त है, लेकिन कांग्रेस जन पूरे दमखम के साथ चुनावी समर में उतरने के ख्वाहिशमंद हैं. कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता बिहार में पार्टी के सुनहरे दिन वापस लाना चाहते हैं. निष्ठावान कांग्रेसी पार्टी को बिहार में नंबर एक का राजनीतिक दल बना सकते हैं. अब चुनाव में क्या होगा और क्या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस की तस्वीर अभी तक साफ़ नहीं हो पाई है. हालांकि, कांग्रेस के बारे में एक संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि वह राजद-जदयू के साथ जाएगी. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस हारे या जीते, लेकिन वह इस बार अपना अस्तित्व बचाने के लिए अकेले ही चुनाव मैदान में कूदेगी. इस दूसरी संभावना को लेकर कांग्रेस के बिहार प्रभारी सीपी जोशी ने भी हाल में सदाकत आश्रम में आयोजित शिविर में अपना रुख साफ़ कर दिया है. अभी तो महज एक शुरुआत हुई है, माहौल में अभी कई और दिलचस्प नज़ारे सामने आने वाले हैं. कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी या गठबंधन के साथ, अभी यह कहना बहुत मुश्किल है. समय कम है और असमंजस ज़्यादा. ऐसे में कांग्रेस द्वारा निर्णय लिया जाना बहुत ज़रूरी है. कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए! ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

नदियों के अच्छे दिन आएंगे

मंगलानंद

केंद्र सरकार झारखंड की नदियों को जोड़ने और उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाएगी. पिछले दिनों केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सफाई मंत्री उमा भारती ने यह घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड को गंगा के लिए मॉडल स्टेट बनाया जाएगा. यहां गंगा मोक्ष के साथ-साथ लोगों को रोटी भी देगी. गंगा को प्रदूषण मुक्त करके उसके किनारे बसे गांवों में ऑर्गेनिक खेती और मछली उत्पादन को को बढ़ावा दिया जाएगा. राज्य में चल रही स्वर्ण रेखा परियोजना निश्चित तौर पर पूरी की जाएगी. इस संदर्भ में जो भी कठिनाइयां पेश आ रही हैं, उन्हें बहुत जल्द दूर किया जाएगा.

उमा भारती ने कहा कि गंगा मंथन कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों एवं सुझावों को गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना में शामिल किया जा रहा है. झारखंड में दामोदर नदी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है. गंगा के साथ-साथ दामोदर को भी प्रदूषण मुक्त करना बहुत ज़रूरी है. दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग के लिए उसके किनारे स्थित उद्योगों और कोल इंडिया के अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है. उमा भारती ने कहा कि नदियों में गाद की समस्या है, जिसके निराकरण के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव और बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों की एक समिति गठित की जाएगी, जो इस समस्या का अध्ययन करके अपने सुझाव देगी. उन्होंने कहा कि भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए भी योजना बनायी जाएगी, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके. उमा भारती ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को हरसंभव सहयोग के लिए तैयार है. राज्य की उक्त तमाम समस्याओं के निदान के लिए पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी. केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से झारखंड का विकास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यद्यपि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, फिर भी यहां के 22 ज़िले नक्सल प्रभावित हैं. इस लिहाज से झारखंड स्वत: विशेष राज्य की श्रेणी में आता है. उमा भारती ने मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें केंद्र सरकार के उच्चाधिकारी भी शामिल हुए. बैठक में राज्य में चल रही स्वर्ण रेखा परियोजना, गंगा सफाई परियोजना एवं पेयजल समस्या समेत जल संसाधन के विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा की गई.

उल्लेखनीय है कि गंगा नदी झारखंड में साहेबगंज एवं राजमहल ज़िले से गुजरती है. उक्त ज़िलों की पेयजल आपूर्ति, सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि बिंदुओं पर भी चर्चा हुई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम के लिए सुरक्षित प्रक्रिया अपनाए जाने पर विचार किया गया. गंगा नदी में इनका प्रवाह और प्रदूषण रोकने के लिए मूलभूत उपाय किए जाने के निर्देश दिए गए. सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल कृषि कार्य में खाद के रूप में किए जाने पर जोर दिया गया और सबसे कठिन लिक्विड वेस्ट का निदान नए तरीके से किए जाने की ज़रूरत पर बल दिया गया. दामोदर नदी के प्रदूषण के कारणों, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय एवं पेयजल की वर्तमान स्थिति, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, पूजन सामग्री के विसर्जन, साहेबगंज में चल रही मेगा रूरल पाइप वाटर सप्लाई स्कीम आदि पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया.■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड

संकट में हरीश सरकार

हरीश रावत की जनसेवा और उन्हें मिल रही सफलता ने भाजपाई थिंक टैंक के माथे पर पसीना उकेर दिया है. भाजपा के दिग्गज येन-केन-प्रकारेण हरीश सरकार को धराशायी करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर विजय बहुगुणा को अपना हथियार बनाया है.

राजकुमार शर्मा

राज्य की हरीश रावत सरकार इन दिनों एक गंभीर संकट से गुज़र रही है. हरीश रावत चक्रव्यूह में फंसे नज़र आ रहे हैं. उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने निशाने पर ले रखा है. पतजंलि पीठ पहुंच कर अमित शाह ने रामदेव के साथ जो हुंकार भरी थी, उसे हरीश की सक्रियता ने बेअसर कर दिया था. पंचायत एवं छावनी परिषद के चुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा. विरोधियों ने शपथ ग्रहण के बाद से ही हरीश की राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए थे, लेकिन विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत दिल्ली दरबार में बेअसर साबित हुए. प्रदेश में आई केदारनाथ आपदा के बाद मुख्यमंत्री बने हरीश रावत ने राहत कार्यों को तेजी प्रदान की. इस बार तीन फुट से अधिक बर्फ से ढंके केदारनाथ धाम में गणतंत्र दिवस मनाया गया. चार धाम यात्रा के लिए सेना के सहयोग से केदारनाथ धाम में पांच हज़ार यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था कराई जा रही है. हरीश रावत की जनसेवा और उन्हें मिल रही सफलता ने भाजपाई थिंक टैंक के माथे पर पसीना उकेर दिया है. भाजपा के दिग्गज येन-केन-प्रकारेण हरीश सरकार को धराशायी करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर विजय बहुगुणा को अपना हथियार बनाया है. हेमवती नंदन बहुगुणा का पुत्र होने के नाते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने वाले विजय बहुगुणा का इस काम में साथ देने की ज़िम्मेदारी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए सतपाल महाराज और उनकी विधायक पत्नी अमृता रावत को सौंपी गई है. सतपाल महाराज अपनी पूरी ताकत विजय बहुगुणा के साथ लगाकर हरीश सरकार को धराशायी कराने की योजना पर जुट गए हैं. बावजूद इसके मुख्यमंत्री हरीश ने पीडीएफ को अभयदान देते हुए कांग्रेस का भविष्य उज्ज्वल होने की बात कही. हरीश ने साफ़ कहा कि जो लोग बुरे दिनों में कांग्रेस के साथ थे, उन्हें छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता. उनका इशारा पीडीएफ को साथ रखने से है.

भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक प्रयोग दिल्ली चुनाव में किया है, उसी को अब वह देवभूमि उत्तराखंड में दोहराना चाहती है. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कांटे से कांटा निकालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और शायद इसी वजह से विजय बहुगुणा को आगे किया जा रहा है. उधर भाजपा के अंदरखाने भी हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा सभी पांच सीटें जीतने के बावजूद उत्तराखंड के किसी नेता को केंद्र सरकार में शामिल नहीं किया गया. आने वाले समय में यह बात पार्टी हाईकमान के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है. वहीं भाजपा ने जिन बाबा रामदेव को उत्तराखंड के लिए अपना खेवनहार बनाया, उन्हें जनता एक व्यवसायी संत से अधिक कुछ नहीं मानती है.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें
CHAUTHI DUNIYA APP

> नई नीति में सरकारी अस्पतालों के काम की मनोदशा में बदलाव लाने की बात कही गई है. सरकारी अस्पतालों को सामाजिक संस्था मानने की सोच से बाहर निकलना होगा. अब सरकारी अस्पतालों को टैक्स फाइनेंस्ड सिंगल प्लेयर हेल्थ केयर सिस्टम के रूप में काम करना होगा, जहां लोगों का इलाज मुफ्त में नहीं हो रहा है. सरकार ने लोगों के इलाज के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है. जैसा कि व्यवसायिक हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, जो लोगों की स्वास्थ्य ज़रूरतें पूरा करने का एक प्रभावी लागत वाला कार्यक्रम है.

स्वास्थ्य नीति-2015

क्या सुधर पाएगी बदहाल स्वास्थ्य सेवा

चौथी दुनिया ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य पूरे करने में थोड़ा पीछे छूट गया है. भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए पिछले दशक में उठाए गए क़दम अपर्याप्त रहे. इस वजह से वर्ष 2000 से 2015 तक के लिए निर्धारित लक्ष्यों तक भारत नहीं पहुंच सका. इनमें पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के लक्ष्य पाने में हुई चूक शामिल है. साथ ही भारत प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रसव कराने का लक्ष्य नहीं पा सका है. आज भी भारत में 27 प्रतिशत बच्चों का जन्म घरों में होता है. जन्म लेने वाले प्रति एक लाख बच्चों में से 178 मौत के मुंह में चले जाते हैं.

अब मोदी सरकार देश के लिए एक नई स्वास्थ्य नीति लेकर आई है. इससे पहले वर्ष 1983 और 2002 में भी सरकार स्वास्थ्य नीति लेकर आई थी. सरकार उन नीतियों के अंतर्गत बनाए गए लक्ष्य पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर हासिल करने में असफल रही. सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का दो प्रतिशत व्यय का लक्ष्य भी पूरा करने में असमर्थ रही. इसका सीधा प्रमाण संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पंद्रह वर्षों की दीर्घ अवधि में भी हासिल न कर पाना है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का ड्राफ्ट मोदी सरकार ने जनता के बीच विचार-विमर्श और सुझावों के लिए रखा है. नीति का उद्देश्य और लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाना है. राइट टू हेल्थ देने की दिशा में भी केंद्र सरकार की योजना है. इन नीतियों में स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में इज़ाफा कर कुल जीडीपी का 2.5 प्रतिशत खर्च करने की दिशा में सरकार काम करेगी. स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का अंश खर्च करने के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों से बहुत पीछे है. कुल स्वास्थ्य बजट का 40 प्रतिशत रिसर्च, मैन पॉवर के विकास, नियंत्रण और महंगी दवाएं थोक में खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा.

सरकार का लक्ष्य प्राथमिक स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे द्वितीय और तृतीय स्तर पर भार कम होगा और वहां भी बेहतर सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा सकेंगी. भारत में हेल्थ इंडस्ट्री (स्वास्थ्य उद्योग) प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है. यह वृद्धि दर देश के अन्य किसी भी औद्योगिक क्षेत्र से दोगुनी और देश की जीडीपी से तिगुनी है. स्वास्थ्य के रखरखाव का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है. इसे देश में ग़रीबी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है. इसी वजह से देश में सरकार द्वारा ग़रीबी हटाने के लिए किए जा रहे उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं. इसलिए देश में एक ऐसी स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता है, जो बदलती ज़रूरतों के अनुकूल हो. ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया में वस्तुओं और लोगों का आवागमन बढ़ा है. इस वजह से कुछ जगह विशेष में केंद्रित रहने वाली बीमारियां भी वैश्विक स्तर पर फैल रही हैं. उदाहरण के लिए इबोला, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों ने वैश्विक रूप ले लिया है. महामारी फैलने की स्थिति में इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम को स्वास्थ्य नीति में शामिल किया गया है.

देश में स्वास्थ्य उद्योग के विकास के साथ-साथ एक नई समस्या भी उभरी है. निजी अस्पतालों में उपचार का खर्च बेतहाशा बढ़ गया है. जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है, वे तो बिना किसी मोल-भाव के ऐसे अस्पतालों में इलाज करा सकने में सक्षम हैं, लेकिन आम आदमी जिसके पास बीमा नहीं है, उसके लिए इन पंच सितारा अस्पतालों में इलाज कराना नामुमकिन है. निजी अस्पतालों में इलाज की क़ीमतें-दरें रेगुलेट करने की कोई नीति नहीं है. ऐसे में हेल्थ टूरिज्म की वजह से इन अस्पतालों में इलाज कराना मुश्किल होता जा रहा है. भारत दुनिया भर में सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना जाता है. नई नीति में इन अस्पतालों में इलाज की दर के रेगुलेशन का जिक्र कहीं नहीं है. हालांकि, आवश्यक दवाओं के दामों का निर्धारण, स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट का निर्धारण पहले की तरह स्थापित संस्थाओं के ज़रिये होगा. सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति के तहत 58 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है. अगले पांच वर्षों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर 14 नए हॉस्पिटल खोले जाएंगे. नए मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद देश में सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 600 के आसपास पहुंच जाएगी. देश में फिलहाल 398 मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की डिग्री देते हैं, जिनमें 52,105 सीटें हैं. यह संख्या भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए अपर्याप्त है. दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या कम है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उत्तर भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या जनसंख्या के लिहाज से बेहद कम है. उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 32 और बिहार में केवल 12 मेडिकल कॉलेज हैं. लेकिन, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन नए संस्थानों के लिए गुणवत्ता वाली वर्क फोर्स का चुनाव करना है, ताकि नए संस्थान एम्स के बराबर गुणवत्ता से कार्य कर सकें.

नई नीति में सरकारी अस्पतालों के काम की मनोदशा में बदलाव लाने की बात कही गई है. सरकारी अस्पतालों को सामाजिक संस्था मानने की सोच से बाहर निकलना होगा. अब सरकारी अस्पतालों को टैक्स फाइनेंस्ड सिंगल प्लेयर हेल्थ केयर सिस्टम के रूप में काम करना होगा, जहां लोगों का इलाज मुफ्त में नहीं हो रहा है. सरकार ने लोगों के इलाज के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है. जैसा कि व्यवसायिक हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, जो लोगों की स्वास्थ्य ज़रूरतें पूरा करने का एक प्रभावी लागत वाला कार्यक्रम है. सरकारी अस्पतालों में लोगों को मुफ्त दवाइयां, जांच और निदान उपलब्ध हो, इसके लिए उन्हें दूसरों से बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से काम करना होगा. सरकारी सेवाओं को मुफ्त की जगह प्री-पेड के रूप में देखने से लोगों और अस्पताल में काम करने वालों के नज़रिये में अवश्य ही बदलाव आएगा.

देश में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की बेहद कमी है. देश के कई हिस्सों में अस्पताल तो हैं, लेकिन वहां डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के चलते लोगों का समुचित इलाज संभव नहीं हो पा रहा है. लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के अलावा उच्चस्तरीय इलाज के लिए निकट के मेडिकल कॉलेजों या ज़िला अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है. ऐसे में डॉक्टरों की कमी को पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है. निजी अस्पतालों की ओर डॉक्टरों के रुख करने की वजह से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी हो रही है. सरकार की योजना है कि प्रत्येक दस लाख की आबादी के लिए 1000 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त अस्पताल होना चाहिए. सरकार अस्पतालों के सुधार के लिए नियमित अंतराल में उनका आकलन करेगी. अस्पतालों को न्यूनतम मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और उन्हें गुणवत्ता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा. नियत समयांतराल में अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा. साथ ही निश्चित समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्ता में सुधार करने वाले अस्पतालों को पुरस्कृत करने की भी योजना है.

देश में ब्लड बैंकों में खून की कमी की वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है. ज़िला स्तर पर ब्लड बैंक और ब्लड की सुरक्षा एक गंभीर मसला है. वर्तमान में मान्यता प्राप्त ब्लड बैंकों की संख्या ज़िला और तहसील स्तर पर इतनी नहीं है कि लोगों के लिए संक्रमण रहित ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके. रिपोर्ट्स के अनुसार, देश के ज़िला एवं तहसील स्तर पर अधिकांशत: ब्लड की पूर्ति ग़ैर-ब्लड बैंक स्रोतों से होती है. इसलिए सरकार इस दिशा में भी काम करेगी और लोगों के लिए सुरक्षित ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी. देश में लंबे समय से नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी बनाने की बात कही जा रही है. पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने इस दिशा में कुछ क़दम भी उठाए थे, लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. बदलते समय के साथ ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में भी बदलाव की आवश्कताओं को जानते-परखते हुए ब्लड ट्रांसफ्यूजन (रक्ताधान) के लिए अथॉरिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था.

सरकार का लक्ष्य जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ लिंगानुपात को भी संतुलित करना है. सरकार ने महिला नसबंदी के साथ-साथ पुरुषों की नसबंदी में इजाफा करने का लक्ष्य रखा है. वर्तमान में यह दर 5 प्रतिशत है, जिसे 30 प्रतिशत या इससे जितना ज़्यादा हो सके, करने का लक्ष्य रखा गया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनाई जाने वाली आक्रामक विधियां न तो उचित हैं और न लक्ष्य पाने की दिशा में प्रभावी. शिक्षा के स्तर और पहुंच में बढ़ोत्तरी से ही जनसंख्या वृद्धि में प्रभावी तरीके से लगाम लगाई जा सकती है. टीबी एवं एड्स के अलावा मानसिक बीमारियों को भी नीति में प्राथमिकता के साथ रखा गया है. इसके अलावा आयुष को भी जगह दी गई है. कुल मिलाकर यह नीति भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत जल्द बड़ा बदलाव नहीं करने जा रही है और न कुछ दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प होने वाला है. यदि इस नीति की बदौलत सरकार सबके लिए बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाती है, तभी इसे सफल कहा जाएगा. अभी लोगों के सुझाव नई स्वास्थ्य नीति के ड्राफ्ट में शामिल किए जाने बाकी हैं. हालांकि, सरकार राइट टू हेल्थ लागू करने की दिशा में काम करती दिख रही है. यदि वह ऐसा करने में सफल होती है, तो यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

मुंह की बीमारियों को जगह नहीं

भारत में तंबाकू से होने वाले कैंसर के रोगियों की भरमार है. तंबाकू का सेवन करने वालों को अधिकांशत: मुंह का कैंसर होता है. नई नीति में मुंह से संबंधित बीमारियों के इलाज का स्पष्ट तौर पर कोई जिक्र नहीं है. विशेषज्ञों का मानना है कि मुख का स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य का सूचक होता है. मुंह में होने वाली बीमारियों का इंफेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकता है. यह अवधारणा ग़लत है कि मुंह की बीमारियां जानलेवा नहीं होतीं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मुख कैंसर भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. मुख कैंसर का प्रभावशाली तरीके से निदान उसी सूरत में किया जा सकता है, जबकि इसकी पहचान प्रारंभिक दौर में हो जाए. एक तरफ़ सरकार तंबाकू उत्पादों पर लगातार टैक्स बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ़ उसने खुली सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगा दी है.

रिक्शा पर ग़ैर ज़रूरी प्रतिबंध लगाने वाले क़ानूनों को देखते हुए कहा जा सकता है कि देश में अनावश्यक रूप से जबरदस्ती बेरोज़गारी पैदा की जा रही है. श्रम करने वालों का रास्ता क़दम–क़दम पर सरकार की ग़लत नीतियां रोके हुए हैं. दिल्ली में मौजूद अधिकांश रिक्शा चालक उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के हैं, जो रोज़गार और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यहां आते हैं.

बुनकर आंदोलन पर भारी पड़ी यूनियनबाजी

खुनील सौरभ

बिहार का मैनचेस्टर कहे जाने वाले गया के मानपुर पटवा टोली में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर क़रीब दस हज़ार बुनकर मज़दूरों के अचानक हड़ताल पर चले जाने से 20 हज़ार पावरलूमों की धड़कन नौ दिनों तक बंद रही. जिसके चलते पावरलूम मालिकों को क़रीब पांच करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा. लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति और प्रतिदिन कमाकर पूरे परिवार का भरण पोषण करने की लाचारी के चलते बुनकर मज़दूरों को नौ दिनों के बाद ही मांग पूरी हुए बिना काम पर वापस लौटना पड़ा. हड़ताल का आह्वान करने वाली यूनियन के नेताओं ने इस दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि पावरलूम संचालकों और हड़ताली बुनकर मज़दूरों के बीच मारपीट होने लगी, एक-दूसरे के ख़िलाफ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज भी कराई गई. श्रम अधीक्षक का हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास भी विफल हो गया. लेकिन जब आर्थिक तंगी के चलते बुनकर मज़दूरों के घरों में चूल्हे जलने बंद होने की नौबत आने लगी, तो वे धीरे-धीरे काम पर वापस लौटने लगे.

श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें बढ़ती महंगाई के हिसाब से मेहनताना नहीं मिल रहा है, इसलिए मेहनताने में 15 फ़ीसद का इजाफा होना चाहिए. उधर पावरलूम मालिक-संचालक मज़दूरी में पांच फ़ीसद वृद्धि की बात कह रहे थे, जो उन्होंने कर भी दी. लेकिन, मज़दूरों की हालत देखते हुए यह वृद्धि काफी नहीं मानी जा सकती. बुनकर मज़दूरों का कहना है कि राज्य सरकार भी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. मानपुर में आठ हज़ार पावरलूम चल रहे हैं, एक भी मिल मालिक ग़रीब नहीं हैं, फिर भी उन्हें सरकार से करोड़ों रुपये की ऋण माफी मिल रही है. यहां से हर वर्ष लगभग आठ-दस छात्र आईआईटी एवं एनआइटी की पढ़ाई के लिए चुने जाते हैं, लेकिन आज तक एक भी मज़दूर के लड़के को आईआईटी में अवसर नहीं मिला. क्या इन मज़दूरों की माली हालत पर किसी भी संगठन या राजनेता का ध्यान नहीं जाना चाहिए? बुनकर मज़दूर रात-दिन मशीन चलाते हैं, उन्हें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण का सामना करना पड़ता है. यही नहीं, मज़दूर आएदिन नई-नई बीमारियों के शिकार बनते हैं. पूरा भविष्य दांव पर लगा होने के बावजूद पावरलूम मालिक-संचालक कभी मज़दूरों के बारे में नहीं सोचते.

मानपुर पटवा टोली के वस्त्र उद्योग में मज़दूरों ने पहली बार इतनी लंबी हड़ताल की. अब तक पावरलूम मालिकों-संचालकों और बुनकर मज़दूरों की आपसी सहमति से मज़दूरी आदि तय हो जाती थी और काम चलता रहता था. मज़दूरों की समस्याओं का हल भी आपस में मिलजुल कर निकाल लिया जाता था. लेकिन, कुछ यूनियनबाज नेताओं की वजह से जहां मानपुर वस्त्र उद्योग को क्षति पहुंच रही है, वहीं बुनकर मज़दूरों को भी उनका वाजिब हक़ नहीं मिल पा रहा है. पावरलूम मालिकों-संचालकों के अनुसार, जिस तरह यूनियनबाजी करके रोहतास इंडस्ट्रीज डालमिया नगर, गुरारु चीनी मिल, वारसलीगंज चीनी मिल, गया कॉटन एवं जूट मिल समेत बिहार के अन्य कई उद्योग बंद कराकर कामगारों को भूखे मरने के लिए विवश किया, उसी तरह मानपुर वस्त्र उद्योग भी बंद कराने की साजिश रची गई थी. दरअसल, किसी भी मज़दूर ने अपने पावरलूम संचालक या मालिक से लिखित रूप से कोई मांग नहीं की थी. ज़िला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए ट्रेड यूनियन के नेताओं ने उन्हें 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया, तब पता चला कि मज़दूरों की मांगें क्या-क्या हैं. मूल रूप से वर्तमान मज़दूरी में 20 फ़ीसद बढ़ोत्तरी की मांग थी. पावरलूम पर काम करने वाले मज़दूरों को एक मशीन पर आठ घंटे काम करने की 80 रुपये मज़दूरी दी जाती है. एक शिफ्ट में एक मज़दूर एक साथ तीन पावरलूमों पर काम करता है.

श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें बढ़ती महंगाई के हिसाब से मेहनताना नहीं मिल रहा है, इसलिए मेहनताने में 15 फ़ीसद का इजाफा होना चाहिए. उधर पावरलूम मालिक-संचालक मज़दूरी में पांच फ़ीसद वृद्धि की बात कह रहे थे, जो उन्होंने कर भी दी. लेकिन, मज़दूरों की हालत देखते हुए यह वृद्धि काफी नहीं मानी जा सकती.

वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेम नारायण पटवा ने कहा कि हड़ताल के पहले ही हमने मज़दूरी में पांच फ़ीसद की वृद्धि कर दी थी, लेकिन बुनकर कामगार संघ ने 20 फ़ीसद वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर दी. बाद में उद्योग मालिकों और पचास फ़ीसद कामगारों के बीच आपसी सहमति से मामला सुलट गया और सभी कामगार वापस लौट आए. 12 से 20 जनवरी तक हुई इस हड़ताल के चलते वस्त्र उद्योग को क़रीब पांच करोड़ रुपये का घाटा हुआ. बुनकर मज़दूर नंदू प्रसाद ने बताया कि इससे पहले कभी इतनी लंबी हड़ताल नहीं हुई. जब हम मज़दूरी बढ़ाने की बात करते, तो मालिक-संचालक हमारी बात मान लेते थे. इस लंबी हड़ताल के चलते घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया. बुनकर मज़दूर नूर आलम के अनुसार, काम करते हैं, तभी हमें और परिवार को भोजन मिलता है. सच भी यही है कि कामगारों को रोज कमाना-रोज खाना के हिसाब से चलना पड़ता है. अगर वे एक दिन भी काम छोड़कर बैठ जाएं, तो परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो जाता है. ■

रिक्शा चालकों की सुध कब लेगी सरकार

कुमार कृष्णन

रिक्शा हमारे देश में शहरी यातायात के मुख्य साधन हैं. निम्न-मध्यम वर्ग की यह प्रमुख सवारी है. महानगरों से लेकर छोटे-छोटे शहरों, कस्बों तक रिक्शा चालकों की अपनी एक अलग पीड़ा है, जिसकी परवाह सरकार को नहीं है. दिन भर खून-पसीना बहाने के बावजूद रिक्शा चालकों को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता. एक ओर करोड़ों रुपये खर्च करके सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, जबकि दूसरी ओर कई ऐसे क़ानून भी हैं, जो आम आदमी को ईमानदारी से चार पैसे कमाने से रोकते हैं. रिक्शा चालकों से संबंधित क़ानून इसका जीता-जागता उदाहरण है. रिक्शा भले ही अब लगभग लुप्त प्राय: हो चुका है, लेकिन उसकी शैली एक परिवहन के रूप में आज भी लोगों को आकर्षित करती है. भारत में सन् 1920 में पहली बार रिक्शा शिमला में दिखाई पड़ा. तक़रीबन 18 साल बाद 1938 में कोलकाता में रिक्शा दिखा. इसके बाद उसकी पहुंच बढ़ती गई.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें, तो सन् 2000 में यहां 40 हज़ार रिक्शा चालक थे, जबकि वर्तमान में लगभग एक लाख रिक्शा चालक हैं, जो हर जगह दिख जाते हैं. मेट्रो स्टेशनों के आसपास निकटतम स्थान पर जाने का यह सस्ता और सर्वसुलभ माध्यम है. सरकार का ध्यान इन रिक्शा चालकों पर नहीं है, क्योंकि ये सरकार द्वारा बनाई गई किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते. स्थिति इतनी जटिल हो गई है कि सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाली केंद्र सरकार इन ग़रीबों पर भारी पड़ रही है. नगर निगम ने यातायात पुलिस के सहयोग से दिल्ली को तीन क्षेत्रों में बांट दिया है-मुक्त, प्रतिबंधित और सीमित क्षेत्र. मुक्त क्षेत्र में रिक्शा चलाने की आज़ादी है, प्रतिबंधित क्षेत्र में बिल्कुल मनाही है और सीमित क्षेत्र में रिक्शा चलाने के लिए कुछ शुल्क अदा करना पड़ता है.

दरअसल, प्रतिबंधित और सीमित क्षेत्र तय करने के पीछे नीति निर्माताओं का तर्क यह है कि रिक्शों की वजह से सड़क जाम की समस्या पैदा होती है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिन सड़कों पर रिक्शे नहीं चलते, क्या वहां जाम नहीं लगता? तो फिर कार या बसों की संख्या भी सीमित कर दी जानी चाहिए. यदि कार या अन्य वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए आम आदमी द्वारा अदा किए गए टैक्स की रकम से फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं, तो फिर रिक्शा चालकों के लिए अलग से कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? ग़ौरतलब है कि राजकोष का अधिकांश हिस्सा परोक्ष कर से एकत्र होता है, जिसमें साधारण, निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों का भी योगदान होता है. यदि रिक्शा चालक सस्ती और आरामदायक सेवा दे सकते हैं और लोग रिक्शा की सवारी करना चाहते हैं, तो फिर कहीं भी रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध क्यों?

रिक्शा पर ग़ैर ज़रूरी प्रतिबंध लगाने वाले क़ानूनों को देखते हुए कहा जा सकता है कि देश में अनावश्यक रूप से जबरदस्ती बेरोज़गारी पैदा की जा रही है. श्रम करने वालों का रास्ता क़दम-क़दम पर सरकार की ग़लत नीतियां रोके हुए हैं. दिल्ली में मौजूद अधिकांश रिक्शा चालक उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के हैं, जो रोज़गार और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यहां आते हैं. वे यह सोचकर आते हैं कि रिक्शा चलाना एक आसान रोज़गार है, जिसमें अन्य रोज़गारों की तुलना में कोई खास औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होती. रिक्शा भी आसानी से भाड़े पर मिल जाता है. अधिकांश रिक्शा चालक दिल्ली आने से पहले दूसरे लोगों के खेतों में काम करते थे या रोज दिहाड़ी पर आश्रित थे.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें, तो सन् 2000 में यहां 40 हज़ार रिक्शा चालक थे, जबकि वर्तमान में लगभग एक लाख रिक्शा चालक हैं, जो हर जगह दिख जाते हैं. मेट्रो स्टेशनों के आसपास निकटतम स्थान पर जाने का यह सस्ता और सर्वसुलभ माध्यम है. सरकार का ध्यान इन रिक्शा चालकों पर नहीं है, क्योंकि ये सरकार द्वारा बनाई गई किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते.

आम तौर पर रिक्शा चलाना ठेकेदारी प्रथा पर आश्रित है और ठेकेदार ही रिक्शा चालकों की ज़िंदगी चलाता है. सस्ते परिवहन में रिक्शा की अहम भूमिका है. कोई सहारा न होने की वजह से 60 वर्ष की आयु वाले लोग भी रिक्शा चलाते दिख जाते हैं. हर रिक्शा चालक रोजाना औसतन 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 12-14 घंटे कमरतोड़ मेहनत करता है. बावजूद इसके उसके हाथ तीन-चार सौ रुपये प्रतिदिन लगते हैं तथा उसमें से 50-60 रुपये किराये के रूप में रिक्शा मालिक को देने पड़ते हैं. अधिकांश: रिक्शा चालक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और उनके पास रिक्शा खड़ा करने की जगह भी नहीं होती, इसलिए वे रिक्शा नहीं खरीद पाते. उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वे किराए पर झुग्गी ले सकें. इसलिए वे अपना जीवनयापन फुटपाथ पर या फिर गैराज में रहकर करते हैं.

अधिकांश रिक्शा चालक अनपढ़ या थोड़े-बहुत पढ़े-लिखे होते हैं. इससे साफ़ निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनके परिवार की माली हालत कैसी होगी. सरकारी नीति और पहचान के सुबूतों के अभाव के चलते उनका क़दम-क़दम पर शोषण किया जाता है. रिक्शा चालक ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, नगरपालिका और निजी वाहन चालकों के शोषण से पीड़ित रहते हैं. कभी टायर पंचर करके, तो कभी रिक्शा जब्त करके उन्हें परेशान किया जाता हैं और उनसे वसूली की जाती है. अधिकांश रिक्शा चालक मांसपेशियों में दर्द, सूजन, थकान, कमजोरी, खिंचाव से पीड़ित रहते हैं. बीमार पड़ने पर वे सरकारी अस्पताल या झोलाछाप डॉक्टरों के पास ही जाते हैं. दैनिक थकान से बचने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन भी रिक्शा चालकों में आम बात है, जिनमें शराब, सिगरेट, बीड़ी और गांजा शामिल है.

सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र रवि का कहना है कि शहरी परिवहन नीति में कहा गया है कि हर योजना लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी. शहरों को इस तरह विकसित किया जाएगा कि वे सामाजिक एवं आर्थिक विकास में मददगार साबित हों. इसके लिए परिवहन भी एक आवश्यक इकाई है. यह नीति सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने की बात करती है, लेकिन साथ ही साइकिल चलाने और पैदल चलने को ख़तरनाक घोषित करती है. मौजूदा समय में समाज एक स्वच्छ, सस्ता और अपने घर तक यातायात की सुविधा चाहता है और रिक्शा इन तमाम बिंदुओं पर खरा उतरता है. बावजूद इसके सरकार की नीतियों में रिक्शा एवं रिक्शा चालकों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कोई प्रावधान नहीं है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत हर भारतीय को अपनी आजीविका के लिए कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है. इस तरह रिक्शा चालक भी संवैधानिक रूप से अपने जीवनयापन के हक़दार हैं, तो फिर उनका शोषण क्यों? ■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

अब दिल्ली चुनाव की बात. जैसा मैंने कहा था कि चाहे परिणाम जो हो, यहां जो भी हुआ, अच्छा नहीं हुआ. भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा को छोड़कर कहीं भी स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल कर सकी. महाराष्ट्र एवं झारखंड में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. कश्मीर का तो सवाल ही अलग है. मेरे हिसाब से अगर वे लंबे समय के लिए कांग्रेस को मुख्य पार्टी के तौर पर हटाना चाहते हैं, तो उन्हें कांग्रेस से सहन शक्ति भी सीखनी चाहिए. जिस तरह की घटनाएं हुईं, वे हास्यास्पद हैं. भाजपा सत्ता में रहकर भी विपक्ष की तरह व्यवहार करती दिखी.

भाजपा विपक्ष की तरह व्यवहार कर रही है

पिछले दिनों हर तरफ़ दिल्ली चुनाव की चर्चा थी. एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए इतना हंगामा समझ से बाहर है. इसमें दो बातें हैं. पहली यह कि एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी गई, चाहे वह प्रदेश दिल्ली ही क्यों न हो. दूसरी यह कि प्रचार के स्तर, भाषा के इस्तेमाल और जो आरोप लगाए गए, इन सबसे भारतीय लोकतंत्र को कोई लाभ नहीं होगा. सबसे बदतर बात यह कि न जाने किसकी सलाह पर स्वयं प्रधानमंत्री ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जैसी भाषा का इस्तेमाल उन जैसे कद्दावर नेता को कौन कहे, किसी आम पार्टी लीडर द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी. नरेंद्र मोदी ने अपने बल पर लोकसभा चुनाव में 282 सीटें हासिल की थीं. उन्हें इस चुनाव से बाहर रहना चाहिए था. वह कह सकते थे कि भाजपा निश्चित रूप से यह चुनाव जीत जाएगी. पार्टी की स्थानीय इकाई यह चुनाव लड़ेगी. प्रधानमंत्री यह कह सकते थे कि मैंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी और दिल्ली की जनता ने पहले से ही कांग्रेस को नकार दिया है. इसलिए मेरा काम पूरा हो गया. अब अगर भाजपा जीतती है और केजरीवाल की पार्टी कड़ा मुक़ाबला करती है, तो लोकतंत्र में नए लोगों को सामने आना चाहिए. केजरीवाल का स्वागत है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी पार्टी मेहनत करेगी और चुनाव जीत जाएगी. मोदी को यह लड़ाई यहीं छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ने वाला है. पुलिस और क़ानून व्यवस्था लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है और ज़मीन का अधिकार डीडीए के पास है. दिल्ली सरकार के पास बहुत कम अधिकार हैं. लेकिन, कुल मिलाकर इससे एक सोचने-विचार करने वाले व्यक्ति के मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है.

जिस दिन किरण बेदी को चुनाव में उतारा गया, उसी दिन से मुंह का स्वाद बिगड़ गया, क्योंकि दिल्ली में भाजपा की जड़ें बहुत मज़बूत हैं. उसके पास दिल्ली में नेतृत्व की एक लंबी कतार है. फिर भी एक बाहरी शख्स को नेता बनाया गया, जो भाजपा को भला-बुरा कहता था. एक ऐसा बाहरी शख्स, जो भाजपा के लिए हमदर्दी नहीं रखता था. किरण बेदी को पार्टी में लाना और कहीं से चुनाव मैदान में उतारना तो ठीक है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में दे देना मेरे ख्याल से आत्मघाती है. भाजपा से हमदर्दी रखने वाले बहुत सारे लोग, खास तौर पर संघ से जुड़े लोग इसे लेकर बहुत निराश हैं. वे भाजपा के रोजाना के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जब अकेले में मिलते हैं, तो अपनी निराशा भी नहीं छिपाते. और, मैं पिछले दस दिनों के दौरान ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं.

दूसरा, भारत से वापस जाने के बाद मुझे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने अपने दौरे पर दोबारा ग़ौर करने के बाद यह पाया कि भारत में धार्मिक कलह एक गंभीर समस्या बन गई है. उन्होंने वाशिंगटन में कहा कि आज अगर महात्मा गांधी ज़िंदा होते, तो भारत की मौजूदा हालत देखकर आश्चर्यचकित हो जाते. यह भारतीय मीडिया में पेश की गई उस तस्वीर से बिल्कुल अलग है, जिसमें यह कहा गया था कि ओबामा इस दौरे से बहुत खुश थे और यह दौरा बहुत ही सफल रहा. धार्मिक कलह एक गंभीर समस्या है. एक केसरिया वस्त्र पहने सांसद या संघ परिवार के दूसरे नेताओं का इस तरह का बयान सामान्य देश के वातावरण के लिए, विशेष रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है.

घर वापसी एक ऐसी अवधारणा थी, जो किसी की समझ में नहीं आई. हिंदू धर्मग्रंथों में यह कहीं नहीं लिखा है. मैं एक अच्छा हिंदू होने का दावा कर सकता हूं, जिसने धार्मिक किताबें पढ़ रखी हैं. लेकिन ये लोग भारत को पाकिस्तान की तर्ज पर बनाना चाहते हैं यानी भारत पाकिस्तान का हिंदू वर्जन हो. लेकिन, इससे हिंदुत्व का महत्व घटेगा. इसलिए हिंदूवाद की तुलना अन्य से करके आप हिंदू दर्शन को कमतर बना देते हैं. इस बात पर आरएसएस को ध्यान देना चाहिए था, न कि भाजपा को. आरएसएस को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर वे हिंदू धर्म की वाकई सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी. मुसलमानों और ईसाइयों को कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उन्हें इस पर विचार करना होगा. ऐसे लोगों के इस तरह के बयान, जो अपने नेताओं को खुश करना चाहते हैं, वाकई निदंनीय हैं, ग़लत हैं. भाषा ग़लत है, सोच ग़लत है. इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. अगर वे मोदी के पांच साल को लड़ाई-झगड़े में निपटा देना चाहते हैं, तो बात अलग है. लेकिन, मेरे विचार से उन्हें मोदी को सरकार चलाने में मदद करनी चाहिए, ताकि ऐसे बेकार के मुद्दों को अलग रखा जा सके.

जिस दिन किरण बेदी को चुनाव में उतारा गया, उसी दिन से मुंह का स्वाद बिगड़ गया, क्योंकि दिल्ली में भाजपा की जड़ें बहुत मज़बूत हैं. उसके पास दिल्ली में नेतृत्व की एक लंबी कतार है. फिर भी एक बाहरी शख्स को नेता बनाया गया, जो भाजपा को भला-बुरा कहता था. एक ऐसा बाहरी शख्स, जो भाजपा के लिए हमदर्दी नहीं रखता था. किरण बेदी को पार्टी में लाना और कहीं से चुनाव मैदान में उतारना तो ठीक है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में दे देना मेरे ख्याल से आत्मघाती है.

अब दिल्ली चुनाव की बात. जैसा मैंने कहा था कि चाहे परिणाम जो हो, यहां जो भी हुआ, अच्छा नहीं हुआ. भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा को छोड़कर कहीं भी स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल कर सकी. महाराष्ट्र एवं झारखंड में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. कश्मीर का तो सवाल ही अलग है. मेरे हिसाब से अगर वे लंबे समय के लिए कांग्रेस को मुख्य पार्टी के तौर पर हटाना चाहते हैं, तो उन्हें कांग्रेस से सहन शक्ति भी सीखनी चाहिए. जिस तरह की घटनाएं हुईं, वे हास्यास्पद हैं. भाजपा सत्ता में रहकर भी विपक्ष की तरह व्यवहार करती दिखी. कांग्रेस सब कुछ खो चुकी है, लेकिन उसका अंदाज़ बताता है, मानो वह अभी भी सत्ता में है. मैं सोचता हूं कि उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि राजनीति भी ज़िंदगी की तरह एक ऐसा मंच है, जहां अपने लिए चुनी गई भूमिका को निभाना है. भाजपा को सरकार की तरह व्यवहार करना चाहिए और कांग्रेस को नम्र बनकर पार्टी का पुनर्निर्माण करना चाहिए. चुनाव के बाद मैंने कांग्रेस की एक भी बैठक होते नहीं देखी. कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से उनके नेताओं का मिलना मुश्किल हो गया है. कांग्रेस को अपने वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनानी चाहिए, जो हर राज्य में जाए, पार्टी की बैठक करे और कांग्रेस में ऊर्जा भरने का काम करे. मैं नहीं जानता कि कांग्रेस की रणनीति क्या है? अभी इंतज़ार कीजिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

मृत्यु का कोई उपाय कीजिए-2
अब जीने की इच्छा नहीं है...

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं. नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

वर्ष 1934 में हमारा और जयप्रकाश जी का घनिष्ठ संबंध हुआ. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से वह बनारस में रहते थे. वहां कबीरचौरा में अस्पताल के सामने म्युनिसिपेलटी के शिक्षा अधीक्षक रामेश्वर सिंह के मकान में जयप्रकाश जी रहते थे. वहीं दफ्तर भी था. उसी मकान में हमारी उनकी ज़्यादा घनिष्ठता हुई. उसके बाद हम लोग बराबर मिलते रहे और सिर्फ़ एक साथी की तरह नहीं, बल्कि राजनीति के अलावा और निकटतर संबंध के नाते भी. 1937 के अप्रैल में जब जयप्रकाश जी जेल चले गए, तो सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर में कोई नहीं बचा. तब मैं क़दमकुआं में, जो सोशलिस्ट पार्टी का दफ्तर था, वहां चला आया. 1937 में जब जयप्रकाश जी जेल में थे, तो उनके पिता जी बहुत अस्वस्थ हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई. पिता जी की मृत्यु के बाद जयप्रकाश जी ने यह सोचा कि अब अपने बहनोई के यहां, जो हाईकोर्ट में सुपरिन्टेंडेंट थे, न रहकर अलग कहीं रहेंगे. तब क़दमकुआं में एक मकान लिया गया, स्मृति कला उसका नाम था. उसी मकान में हम लोग साथ रहने लगे. जयप्रकाश जी भी आ गए, प्रभावती जी भी आ गईं. 1937 में हम तीनों की गृहस्थी शुरू हुई. और, वह गृहस्थी जब वह जेल में रहते या जब मैं जेल में रहता, को छोड़कर 1955 तक चलती रही.

पिछले दिनों जेपी अक्सर मृत्यु की चर्चा करते रहते थे. ऐसी ही चर्चाओं के दौरान मैंने उन्हें बतलाया था कि रवींद्र नाथ ने मरण पर कई कविताएं लिखी हैं. मरण को उन्होंने नितांत स्पृहणीय बना दिया है. एक बार मैंने उनको रवींद्र नाथ की भानुसिंहेर पदावली की मरण रे तुहु मम श्याम समान तथा मरण ओहे मोर मरण कबे तुमि आमाके करिबे वरण आदि कविताएं सुनाईं. जयप्रकाश जी इनसे बहुत प्रभावित हुए तथा इनका आनंद लिया. लेकिन इस सबके बाद उन्होंने कहा, रवींद्र नाथ ने अपनी प्रतिभा के बल पर मृत्यु को इतना बढ़िया, इतना फैसिनेटिंग बना दिया है. क्या मृत्यु सचमुच इतनी फैसिनेटिंग है, फिर लोग डरते क्यों हैं? फिर घबराते क्यों हैं? मुझे लगता है कि रवींद्र नाथ की प्रतिभा ने इसको बहुत ऊंचा उठा दिया है. शायद वास्तविकता से बहुत ऊंची उठ गई है यह चीज. एक वर्ष पहले उन्होंने यह कहा था.

इस बार बंबई से लौटकर जब आए, तो एक रोज उन्होंने अचानक मुझसे कहा, आपने रवींद्र नाथ की कविताएं सुनाई थीं, कुछ याद हैं? पहले तो मैंने उन्हें बहुत-सी कविताएं सुनाई थीं, लेकिन आख़िर में यही दोनों कविताएं मुझे याद थीं, यह दोनों मैंने उनको सुनाईं. तब उन्होंने कहा, आपको स्मरण होगा, मैंने कहा था कि यह थोड़ा कल्पनापूर्ण है. वास्तविकता नहीं है, इसमें कल्पना ही है. बंबई से लौटने के बाद मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि रवींद्र नाथ वाज करेक्ट. डेथ इज ए वैरी फैसिनेटिंग थिंग. मृत्यु डरने की चीज नहीं है, मृत्यु घबराने की चीज नहीं है. बल्कि मैं तो यह अनुभव करता हूं कि जिस पीड़ा से होकर मैं गुज़र रहा हूं, जो कष्ट मैं भोग रहा हूं, उससे मृत्यु तो हज़ार गुनी अच्छी है. सिर्फ़ तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी नहीं है, मेरा ख्याल है कि मृत्यु कष्टदायक नहीं है और इसका कुछ अनुभव मुझे बंबई में हुआ है. वह उन्होंने बताया भी. मुझे क्षमा कीजिए, समय गुज़रने दीजिए, तो मैं बतलाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, बंबई में किस तरह का अनुभव किया. आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि मुझसे कई बार रसखान के छंदों को सुनाने को उन्होंने कहा था. इस पर रसखान के कई छंद मैंने उन्हें सुनाए. इसमें दो छंद उनको सबसे ज़्यादा पसंद थे. दोनों ही छंदों को उन्होंने दोबारा-तिबारा सुना. रसखान के प्रसिद्ध छंद, मानुष हौ तो वही रसखानि... तथा चाखन के मिस माखन मांगत...को उन्होंने कई बार सुना. इधर कई महीनों से इस श्लोकार्थ को वह बार-बार दोहराते थे, जिसे मैं बार-बार मना करता था-मुहूर्तम् ज्वलितं श्रेयो-न च तु मारितम चिरः

यह इधर उनका मंत्र-सा हो गया था. शायद ही कोई दिन ऐसा गुज़रा हो पिछले छह महीनों में, जब यह दो-चार बार वह नहीं कहते हों. दूसरी चीज एक यह हो गई थी कि महाभारत का जो सावित्री मंत्र है, उसे वह बार-बार कहते थे. इधर मेरी-उनकी बातचीत होती थी साहित्य के संबंध में, कला के संबंध में, कभी-कभी आध्यात्मिकता के संबंध में, संस्कृति के संबंध में. दूसरे इधर प्राय: वह कहते थे कि अब जीने की इच्छा नहीं है. इस जीवन से मृत्यु बढ़िया है, गंगा बाबू, कुछ उपाय कीजिए. आप भी मित्र होकर यह नहीं समझते हैं कि मैं कितना कष्ट भोग रहा हूं. इस जीवन का अंत शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, कुछ कीजिए उपाय कि शांतिमय तरीके से हो. बार-बार मैं उनसे बहस करता था. कितनी बहस, कितनी बातों का उल्लेख करूं. तरह-तरह की दलीलें देने पर भी, अंत में वह यही कहते थे, गंगा बाबू, आप जो कह रहे हैं, यह आपके हृदय की बात नहीं है, बुद्धि की बात है. दलील के लिए आप कह रहे हैं. यह भावना का प्रश्न नहीं है. और, वह समझते थे कि मैं उनको कायल करने की कोशिश कर रहा हूं. जब मैं कहता था, जब जीवन आपने स्वयं पैदा नहीं किया, मैंने या आपने या किसी ने, तो इसके अंत का हमको कौन अधिकार है. आप कहते हैं कि जीवन का अंत कर देना चाहिए, उसका उपाय कीजिए. जो हमारी बनाई हुई चीज नहीं है, उसे समाप्त करने का भी हमें अधिकार नहीं है. (इसके आगे गंगा बाबू बोल नहीं सके...)

(गंगा शरण सिंह से बातचीत के आधार पर, 14 अक्टूबर, 1979)

पिछले दिनों जेपी अक्सर मृत्यु की चर्चा करते रहते थे. ऐसी ही चर्चाओं के दौरान मैंने उन्हें बतलाया था कि रवींद्र नाथ ने मरण पर कई कविताएं लिखी हैं. मरण को उन्होंने नितांत स्पृहणीय बना दिया है. एक बार मैंने उनको रवींद्र नाथ की भानुसिंहेर पदावली की मरण रे तुहु मम श्याम समान तथा मरण ओहे मोर मरण कबे तुमि आमाके करिबे वरण आदि कविताएं सुनाईं. जयप्रकाश जी इनसे बहुत प्रभावित हुए तथा इनका आनंद लिया. लेकिन इस सबके बाद उन्होंने कहा, रवींद्र नाथ ने अपनी प्रतिभा के बल पर मृत्यु को इतना बढ़िया, इतना फैसिनेटिंग बना दिया है. क्या मृत्यु सचमुच इतनी फैसिनेटिंग है, फिर लोग डरते क्यों हैं?

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

महान देश के महान राजनेता

"नरेंद्र मोदी जी, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है. तकनीक उपलब्ध है. मैंने अपनी आंखों से वायुमंडल से पानी बनते हुए देखा है और एक मशीन रोज 1000 लीटर पेयजल बना सकती है यानी एक गांव के लिए 2000 लीटर पेयजल काफी है. पर ऐसी मशीनें न नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है और न राज्य सरकारों की. ये सब ऐसे प्रोजेक्ट्स की तलाश में हैं, जिनमें मंत्री और मुख्यमंत्री की जेब में पैसा पहुंचे, वही प्रोजेक्ट सेंक्शन हों."

नरेंद्र मोदी की सरकार को आए आठ महीने हो गए हैं. इससे पहले 64 वर्षों तक केंद्र और राज्यों में लगभग हर राजनीतिक दल की सरकार रही है. इसके बावजूद देश में हर चुनाव में मुख्य मुद्दा बिजली, पानी, सड़क और भ्रष्टाचार बनता है. जिन समस्याओं को आज़ादी के पांच साल के भीतर हल हो जाना चाहिए था, वे समस्याएं आज भी हर चुनाव में मुद्दा बनती हैं और पांच साल के बाद जब अगला चुनाव आता है, तो फिर वही समस्याएं दोबारा मुद्दों के रूप में सामने आ जाती हैं.

प्रश्न इतना ही नहीं है, इससे आगे का सवाल यह है कि हर बीतता हुआ साल स्थितियां खराब करता जाता है और मैं इन्हीं मुद्दों की बात कर रहा हूं. हर बीतते साल बिजली उत्पादन क्षमता घटती जाती है, पानी अनुपलब्ध होता जाता है, सड़कें टूटती जाती हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है. जो भी पार्टी सत्ता में होती है, चुनाव के बाद सबसे पहले इन्हें अपनी प्राथमिकताओं से हटा देती है. यह हर पार्टी के ऊपर लागू होता है और यह रहस्य समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है.

दुनिया के विकसित देशों में भ्रष्टाचार के अलावा बाकी तीन मुद्दे हल करने में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है. पर हमारे देश में इन्हें सबसे ज़्यादा अनदेखा किया जाता है. जर्मनी का उदाहरण है. पूरी जर्मनी की गंदगी लेकर रॉटरडैम शहर के पास राइन नदी समुद्र में मिलती है और यह नदी पेयजल का सबसे बड़ा साधन है. लेकिन राइन नदी के पानी को शुद्ध करके हर घर में पानी देना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार सैकड़ों वर्षों से यह करती चली आ रही है और आज भी राइन नदी के पानी से शुद्ध हुआ जल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों के ऊपर खरा उतरता है.

हमारे देश में हर सरकार ने वे सारे काम किए, जिनसे पैसे आएं. कम से कम पिछले दो-ढाई साल या पिछले पांच साल या पिछले दस साल का तो यही किस्सा है. लेकिन किसी भी सरकार ने बिजली, पानी और सड़क के ऊपर काम नहीं किया. राज्य चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, ओडिशा हो, कहीं पर भी ये बुनियादी प्रश्न सरकारों की चिंता के विषय नहीं रहे. पर प्राथमिकता में सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए, उनमें पैसे खर्च हुए और यह निस्संदेह आसानी से कहा जा सकता है कि उनमें पैसा सीधे अधिकारियों और राजनेताओं की जेब में गया. हम यह नहीं कहते कि आप घूस मत लीजिए. आप घूस लीजिए, क्योंकि घूस को राजनेताओं और अधिकारियों ने हमारे देश की मुख्य रक्तवाहिनी में घोल दिया है. पर कुछ तो काम जनता के लिए कीजिए! कुछ तो ऐसे काम कीजिए, जिनसे लोगों की ज़िंदगी में कुछ सुधार आए. उदाहरण के तौर पर पावर प्रोजेक्ट्स हैं. ऐसे कितने राज्य हैं, जिनमें पावर प्रोजेक्ट्स पांच साल, दस साल, पंद्रह साल में पूरे हुए हों और उन्होंने बिजली का उत्पादन शुरू किया हो?

और, इससे भी मजेदार बात दूसरी यह है कि ऐसी तकनीक आ गई है, जिससे बिजली उत्पादन 11 से 12 महीने में शुरू हो सकता है. ऐसी तकनीक भी आ गई है, जिससे हवा से पानी बनाया जा सकता है. वायुमंडल में उपलब्ध नमी का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन सरकारें, जिनमें सचिवों से लेकर मुख्यमंत्री तक शामिल हैं, इन तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहतीं. कारण साफ़ है, क्योंकि इस तरह की तकनीकों में उनकी जेब में पैसा नहीं पहुंचता. इस तरह की तकनीकों से जनता को तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अफसरों और राजनेताओं को फ़ायदा नहीं होता. और चूंकि फ़ायदा नहीं होता, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स उनकी प्राथमिकता में नहीं हैं.

यही स्थिति केंद्र सरकार की है. आठ महीने से ज़्यादा बीत गए, किसी भी विभाग में कोई काम नहीं हुआ और किसी विभाग की नीति नहीं बनी. किसी विभाग में काम शुरू नहीं हुआ और खासकर बिजली, पानी के स्तर पर केंद्र सरकार भी उसी पुराने रास्ते पर चल रही है कि जिस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं है, उसमें अगर लोगों का फ़ायदा है, तो उस प्रोजेक्ट को पीछे रखो. मैं एक प्रदेश का हाल जानता हूं, जहां पीने के पानी का प्रोजेक्ट तीन हज़ार करोड़ रुपये में बना और वह जल्दी से पास हो गया, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से किसी मुख्यमंत्री की जेब में 400 करोड़ रुपये पहुंच गए. उतनी ही क्षमता का प्रोजेक्ट उसी सरकार के दूसरे विभाग ने 500 करोड़ रुपये में लगाया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को स्वयं मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ने नहीं दिया.

केंद्र सरकार के मंत्रियों के बारे में बात करें. खुद विद्युत मंत्री के विभाग में जोर-शोर से प्रचार अभियान चलाया जा रहा है कि सौर ऊर्जा से देश की बिजली की आवश्यकता पूरी होगी, क्योंकि न अब पानी है, न कोयला है. लेकिन, खुद विद्युत मंत्री सोए हुए हैं और सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं. शायद वहां भी तलाश है कि कौन-सा प्रोजेक्ट कितना पैसा उन्हें देता है.

ये सवाल यक्ष प्रश्न हैं और इन यक्ष प्रश्नों को हल करना नरेंद्र मोदी के लिए अति आवश्यक है. अगर वह केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर एक समन्वय स्थापित नहीं करेंगे और केंद्र व राज्यों को मोटिवेट नहीं करेंगे, तो उनका यह पूरा पांच साल का कार्यकाल भी वादों का कार्यकाल रह जाएगा, क्योंकि देश में आज भी सड़क, बिजली, पानी की स्थिति वैसी ही है, जैसी आठ महीने पहले थी. नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इनमें कोई परिवर्तन आता दिखाई नहीं दे रहा है.

फ़ैसला नेता को लेना होता है. हमारे देश की व्यवस्था में प्रधानमंत्री बहुत बड़े कारक की भूमिका निभाता है. इसलिए प्रधानमंत्री को शायद सर्वोच्च प्राथमिकताओं के रूप में बिजली, पानी और सड़क को रखना चाहिए. देश के गांवों में पीने का पानी समाप्त हो रहा है. जिस पेयजल समस्या का हल सात से दस दिनों में निकल सकता है, उसे बीस साल के बाद निकालने की योजना बनाई जा रही है और उन्हें नदियों से जोड़ने की बात कही जा रही है तथा देश के लोगों में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि जब नदियां जुड़ेंगी, तब पेयजल की उपलब्धता होगी.

नरेंद्र मोदी जी, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है. तकनीक उपलब्ध है. मैंने अपनी आंखों से वायुमंडल से पानी बनते हुए देखा है और एक मशीन रोज 1000 लीटर पेयजल बना सकती है यानी एक गांव के लिए 2000 लीटर पेयजल काफी है. पर ऐसी मशीनें न नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है और न राज्य सरकारों की. ये सब ऐसे प्रोजेक्ट्स की तलाश में हैं, जिनमें मंत्री और मुख्यमंत्री की जेब में पैसा पहुंचे, वही प्रोजेक्ट सेंक्शन हों. वे प्रोजेक्ट न सेंक्शन हों, जिनसे लोगों को पानी मिले. सवाल नरेंद्र मोदी से शुरू होता है और देश के सभी मुख्यमंत्रियों तक जाता है.

मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के लोगों को अभी बिजली, पानी और सड़क की किल्लत झेलनी पड़ेगी और यह शायद इस देश की नियति है कि हम जिसे भी चुनेंगे, वह भ्रष्टाचार की गंगा से नई नहर निकालने की योजना बनाएगा. भ्रष्टाचार समाप्त कर लोगों को बिजली, पानी और सड़क नहीं उपलब्ध कराएगा. धन्य है यह महान देश और धन्य हैं इसके राजनेता. ■

editor@chauthiduniya.com

भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति

मेघनाद देसाई

दरअसल, यह एक रहस्य ही है कि समान विचारधारा वाले देश होने के बावजूद भारत और अमेरिका ने यह रिश्ता मज़बूत करने के लिए इतने दिनों तक इंतज़ार क्यों किया? इसकी एक वजह शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के प्रति कम्युनिज्म का दुर्भाव हो सकता है. यह वह समय था, जब भारत तुरंत आज़ाद हुआ था. भारत में उस समय सोवियत संघ और नेहरू के अमेरिका विरोध (जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के प्रति था) की वजह से वामपंथ की तरफ़ झुकाव अधिक था. विदेश मंत्रालय का अमेरिका विरोध वर्तमान तक जारी रहा.

कहानी कुछ इस तरह से है कि जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश को यह पता चला कि भारत में एक अरब लोग रहते हैं, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि अमेरिका को भारत के साथ सामरिक संबंध स्थापित कर लेना चाहिए. मनमोहन सिंह से उनकी मुलाक़ात के बाद दोनों नेताओं में तुरंत दोस्ती हो गई. एक सच्चे ईसाई के नाते बुश ने इस मुलाक़ात के दौरान बाइबिल के कई हवाले दिए. और, जब मनमोहन सिंह ने न्यू टेस्टामेंट की अपनी बेहतर समझ का उदाहरण देते हुए उसके हवाले से बात की, तो बुश प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके. बुश बहुत खुश हुए और इस तरह एक भारतीय प्रधानमंत्री और एक अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच व्यक्तिगत दोस्ती की बुनियाद पड़ी.

पिछले दिनों जो भी दिखा, वह एक भारतीय प्रधानमंत्री और एक अमेरिकी राष्ट्रपति की दूसरी जोड़ी के निकट संबंधों की एक विस्तृत पुनरावृत्ति थी. पहली मुलाक़ात में भारत की तरफ़ से यह संदेश गया था कि वह गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त करने के लिए तैयार है और एक राष्ट्र के तौर पर परिपक्व हो गया है. बुश ने दो क़दम आगे बढ़कर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के बहिष्कार से भारत को मुक्त करके उसे वापस परमाणु राष्ट्रों के सम्मानजनक समूह में शामिल करा दिया. लेकिन, अमेरिका-भारत संबंधों में वास्तविक परिवर्तन के लिए यह केवल एक प्रलोभन था. मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ (आवश्यकता पड़ने पर) सामरिक-रणनीतिक साझेदारी पर भारत की सहमति जता दी थी. यह एक गोपनीय सहमति थी, लेकिन कम से कम मनमोहन सिंह ने इसका महत्व समझ लिया था. इसलिए उन्होंने अपनी यूपीए सरकार दांव पर लगा दी और विश्वास मत जीत लिया. यह ऐसी घटना थी, जिसने कम्युनिस्ट वामपंथ का सफाया कर दिया. ज़ाहिर है, यह जानकर बुश को बुरा नहीं लगा होगा.

अब हाल के घटनाक्रम की तरफ़ लौटते हैं, जिसमें हमने इस दोस्ती पर मुहर लगते देखा.

परमाणु रिएक्टर बहुत ख़तरनाक होते हैं, जो समय-समय पर फट पड़ते हैं. शायद 10 वर्षों में एक ऐसी घटना घट जाती है, जिसमें भारी नुक़सान होता है, थ्री-माईल आइलैंड, चेर्नोबेल एवं फुकुशीमा की घटनाएं इसकी मिसालें हैं. दरअसल, रिएक्टरों के निजी आपूर्तिकर्ता किसी तरह का आर्थिक दायित्व उठाने के लिए तैयार नहीं हैं. इसलिए रिएक्टरों में विस्फोट या दुर्घटना की स्थिति में बीमा फंड उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी भारत सरकार पर होगी. मिलिट्री डील और एफडीआई आकर्षित करने के लिए इस तरह का क़दम उठाना ज़रूरी था. तेल की क़ीमतों में गिरावट की वजह से असैनिक परमाणु ऊर्जा पहले से अधिक अलाभकर हो गई है. न्यूक्लियर पॉवर से पैदा होने वाली बिजली सबसे महंगी बिजली बन गई है. हम केवल यह आशा ही कर सकते हैं कि कहीं यह प्रयोग वास्तव में न हो जाए. परमाणु संयंत्रों को एक ग़लती के सुबूत के तौर सुरक्षित करके औद्योगिक संग्रहालय में रख देना चाहिए.

यहां तक कि जब बुश-मनमोहन के बीच परमाणु समझौता हुआ था, उस समय भी इसके पीछे कुछ और था. वास्तविक समझौता या सहमति दरअसल सामरिक भागीदारी थी. चीन यह जानता था, इसलिए चाय पे चर्चा और गले मिलने के तुरंत बाद उसने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी. भारत को यह जटिल खेल जारी रखना चाहिए, न केवल इसलिए कि उसे चीन से युद्ध करना है, बल्कि इसलिए भी कि कोई देश संभावित ख़तरे से निपटने के उपाय किए बिना बचा नहीं रह सकता. 1962 में हमें ऐसी ही लापरवाही की बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ी थी और अब हम वह ग़लती दोहरा नहीं सकते. एक तरह से देखा जाए, तो परमाणु रिएक्टरों के लिए जो बीमा पूल बनाने की बात की गई है, उसे भी सबसे ख़राब स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है. अगर रिएक्टर आपूर्तिकर्ता दुर्घटना के दायित्व के संदर्भ में जिद्दी बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहते हैं, तो यही सही. भोपाल त्रासदी जैसी दूसरी घटना होने और विदेशी कंपनी के भाग जाने पर (शायद उस समय की कंपनी केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत से भागी थी), भारत अक्खड़ और कंजूस नहीं हो सकता. भारत विदेशी निवेश और इस दोस्ती का फ़ायदा उठा सकता है.

दरअसल, यह एक रहस्य ही है कि समान विचारधारा वाले देश होने के बावजूद भारत और अमेरिका ने यह रिश्ता मज़बूत करने के लिए इतने दिनों तक इंतज़ार क्यों किया? इसकी एक वजह शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के प्रति कम्युनिज्म का दुर्भाव हो सकता है. यह वह समय था, जब भारत तुरंत आज़ाद हुआ था. भारत में उस समय सोवियत संघ और नेहरू के अमेरिका विरोध (जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के प्रति था) की वजह से वामपंथ की तरफ़ झुकाव अधिक था. विदेश मंत्रालय का अमेरिका विरोध वर्तमान तक जारी रहा. जैसा कि देवयानी खोब्रागड़े के मामले में देखा गया. इस मामले को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया गया (क्या विदेश सचिव को इसी वजह से अचानक हटा दिया गया?). अमेरिका अपने अप्रवासी समुदाय को अपने विदेशी संबंधों के लिए इस्तेमाल करता है. इसलिए एक पोलिश-अमेरिकन पोलैंड का राजदूत बन जाता है और एक भारतीय-अमेरिकी दिल्ली का राजदूत बन जाता है. भारत को अपनी प्रवासी आबादी को अपने राजनयिक संबंधों के लिए रचनात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए. मौजूदा प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में केवल अपनी प्रवासी आबादी की वजह से खुद को संभाले रखने में कामयाब हो सके. उन्हें इन प्रवासियों को गले लगाना जारी रखना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

घुटने की प्रत्यारोपण सर्जरी आसान विकल्प है

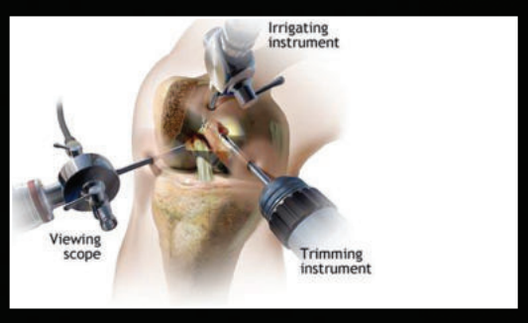

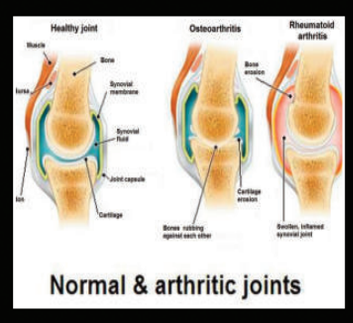

"भारत में 18 करोड़ से ज़्यादा लोग आर्थराइटिस से ग्रस्त हैं और इनमे से हज़ारों लोग हर साल सर्जरी का ऑप्शन अपना कर नया जीवन हासिल कर रहे हैं. आर्थराइटिस जोड़ों को ख़राब करने वाली बीमारी है. यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और ज्वाइंट ख़राब कर देती है. नी (घुटने) की कार्टिलेज खराब होने से होने वाली असहनीय पीड़ा से बचने के लिए नी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र इलाज है.

-डॉक्टर एल. तोमर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल"

चौथी दुनिया ब्यूरो

मॉडर्न लाइफ स्टाइल, काम का कोई समय नहीं और काम के लिए दिन-रात एक जैसे होने की वजह से जो बीमारी काफी अधिक बढ़ी है वो है आर्थराइटिस. जब जोड़-जोड़ दर्द करे तो इसे आम बोलचाल में गठिया कहते हैं और यही गठिया मेडिकल साइंस में आर्थराइटिस कहलाता है. डॉक्टरों का कहना है आर्थराइटिस की करीब 200 किस्म हैं. गठिया के किसी भी रूप में जोड़ों में सूजन दिखाई देने लगती है. इस सूजन के चलते जोड़ों में दर्द, जकड़न और फुलाव होने लगता है. रोग के बढ़ जाने पर तो चलने-फिरने या हिलने-डुलने में भी परेशानी होने लगती है. बढ़ती उम्र, अतिरिक्त मोटापा, हड्डियों की कमजोरी (ऑस्टियोपरोसिस), रूमेटॉयड अर्थराइटिस, डायबिटीज और यूरिक एसिड की समस्या की वजह से कई तरह के गठिया होते हैं. गठिया कैसा भी हो, उसमें न केवल बहुत ज्यादा दर्द होता है, बल्कि घुटना भी विकृत हो जाता है. ऐसे में सबसे बड़ी समस्या चलने-फिरने को लेकर होती है. इसकी वजह से कई बार तो बहुत कम उम्र में ही चलने-फिरने में दिक्कत आने लगती है, लेकिन शुरुआती दौर में ही इलाज करा लिया जाए तो जोड़ों की सतह को आपस में रगड़ खाने से काफी हद तक बचाया जा सकता है. उसके बाद चलने-फिरने में आराम मिल जाता है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है घुटने का नियमित व्यायाम. घुटने को जितनी बार मोड़ा और सीधा किया जाए, उतना ही ज्यादा आराम मिलता है. दरअसल, घुटने को सहारा देने वाली मांसपेशियों के व्यायाम से घुटनों पर जोर कम पड़ता है. दर्द का अहसास भी कम होता है. टने के असहनीय दर्द और चलने-फिरने की लाचारी का सबसे अचूक इलाज है घुटने की सर्जरी. घुटने की तकलीफ ज्यादा बढ़ जाने पर आजकल घुटना प्रत्यारोपित (नी ट्रांसप्लांट) कर दिया जाता है.

ऑर्थराइटिस अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग तरीके से प्रभाव डालता है. जोड़ों की हड्डी बचपन में नरम रहती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कड़ी हो जाती है. ऐसा बीमारी की वजह से भी हो सकता है और जोड़ से गुजरती किसी हड्डी के टूटने से भी. फिर तरह-तरह की दवाओं और किसी सहारे की जरूरत पड़ने लगती है. जटिल स्थिति से बचने के लिए घुटने की प्रत्यारोपण सर्जरी आसान विकल्प है. हालांकि सर्जरी की आवश्यकता तब ज्यादा होती है जब ऑर्थराइटिस मीडियम लेवल का हो अथवा एक्स-रे में साफ दिख रहा हो. ज्यादातर केसेज में मरीज को सर्जरी के बाद दर्द न के बराबर होता है. कम उम्र में सर्जरी को लेकर आशंका होती है और यह भी लगता है कि सर्जरी के बाद उनकी समस्या कितनी कम हो पाएगी. लेकिन ऑर्थराइटिस की समस्या का इलाज करने के लिए ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही सेफ और इफेक्टिव है. सर्जरी के बाद ज्वाइंट पेन से तो रिलीफ मिलती ही है, बल्कि लाइफ की क्वॉलिटी भी बेहतर हो जाती है. दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एल. तोमर का कहना है कि भारत में 18 करोड़ से ज़्यादा लोग आर्थराइटिस से ग्रस्त हैं और इनमे से हज़ारों हर साल सर्जरी का ऑप्शन अपना कर नया जीवन हासिल कर रहे हैं. डॉक्टर तोमर कहते है कि आर्थराइटिस जोड़ों को ख़राब करने वाली बीमारी है जिसमें कार्टिलेज और इसके इर्दगिर्द मौजूद बहुत से टिशू शामिल होते हैं. यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और ज्वाइंट ख़राब कर देती है. नी की कार्टिलेज खराब होने से होने वाली असहनीय पीड़ा से बचने के लिए नी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र इलाज है. कार्टिलेज के डैमेज हो जाने पर बॉडी के उस पार्ट में लगातार दर्द बना रहता है. कार्टिलेज डैमेज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्पाइन और नीज के साथ आती है. डॉक्टर तोमर के मुताबिक नी या हिप ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट लगातार बेहतर होता जा रहा है.

घुटनों में दर्द की समस्या लेकर आने वाले मरीजों में करीब 70 प्रतिशत महिलाएं होती हैं. महिलाओं को ऐसी स्थिति का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है. आम तौर पर वे ऑस्टियोअर्थराइटिस की शिकायत करती हैं. उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को लगता हैं कि सर्जरी के बाद वे घर का काम नहीं कर पाएंगी और बहुत दिनों तक बिस्तर पर ही रहना होगा.

घुटनों में दर्द की समस्या लेकर आने वाले मरीजों में करीब 70 प्रतिशत महिलाएं होती हैं. महिलाओं को ऐसी स्थिति का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है. आम तौर पर वे ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत करती हैं. उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि सर्जरी के बाद वे घर का काम नहीं कर पाएंगी और बहुत दिनों तक बिस्तर पर ही रहना होगा. इस डर से वे सर्जरी करवाने से घबराती हैं. इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि घुटने की ट्रांसप्लांट सर्जरी के तीसरे ही दिन पेशंट चल फिर सकता है. घुटने के ट्रांसप्लांट के 90 प्रतिशत तक मरीज सामान्य जिंदगी बिता रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

रिचर्डसोर्गे: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस की मदद की

"रिचर्ड सोर्गे को सोवियत रूस के बड़े जासूसों में जगह मिलती है. इसने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां रूसियों को सौंपी. रिचर्ड सोर्गे का जन्म रूसी जार के शासनकाल में अजरबैजान में हुआ था. उसके अंकल कार्लमार्क्स के अनुयाई थे, जिसकी वजह से उसे प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का मौका मिला. इसने रूसी सेना के साथ काम किया और प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कई सैनिको को मौत के घाट उतारा. इस दौरान रिचर्ड सोर्गे बुरी तरह घायल हो गया और उसकी टांगे तक टूट गई. इसके बाद उसने रूसी सेना में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम किया और पत्रकार के तौर पर यूरोपीय देशों में गया."

चौथी दुनिया ब्यूरो

पूरी दुनिया में युद्धों के लिए सेना जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जासूसी का नेटवर्क जो समय रहते न सिर्फ जानकारियां दे, बल्कि दुश्मन की हर एक रणनीति नाकाम कर दे. रिचर्ड सोर्गे (जन्म-1895, मृत्यु-1944) ने सोवियत रूस के लिए जापान में जासूसी की. सोर्गे ने एक पत्रकार के रूप में जासूसी की. उसे कई यूरोपीय देशों में सम्भावित कमयुनिस्ट आन्दोलन का पता लगाने के लिए भेजा गया. 1920 से 1922 के बीच सोर्गे जर्मनी में था. वहां वो क्रिस्टीना गेर्लेच से मिला. क्रिस्टीना वहां के एक धनी कम्युनिस्ट डा. कुर्ट अलबर्ट की पूर्व पत्नी थी. सोर्गे ने क्रिस्टीना से 1921 में शादी कर ली. इसके बाद वे फ्रैंकफर्ट चले गए. यहां पर सोर्गे ने बिजनेस कम्युनिटी के बारे में जानकारी जुटानी शुरु कर दी. फ्रैंकफर्ट में सोर्गे ने एक नए मार्क्सिस्ट थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फार सोशल रिसर्च को मदद करने का काम किया. 1924 में अपनी पत्नी के साथ सोर्गे मास्को चला आया. 1929 में सोर्गे रेड आर्मी में शामिल हो गया. 1929 में सोर्गे ब्रिटेन गया जहां उसने श्रमिक आन्दोलन का और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का अध्ययन किया. वह वहां की राजनीति से दूर रहा और अंडर कवर रह कर काम करता रहा.

रिचर्ड सोर्गे को सोवियत रूस के बड़े जासूसों में जगह मिलती है. इसने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां रूसियों को सौंपी. रिचर्ड सोर्गे का जन्म रूसी जार के शासनकाल में अजरबैजान में हुआ था. उसके अंकल कार्लमार्क्स के अनुयाई थे, जिसकी वजह से उसे प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का मौका मिला. इसने रूसी सेना के साथ काम किया और प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कई सैनिको को मौत के घाट उतारा. इस दौरान रिचर्ड सोर्गे बुरी तरह घायल हो गया और उसकी टांगे तक टूट गई. इसके बाद उसने रूसी सेना में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम किया और पत्रकार के तौर पर यूरोपीय देशों में गया. इस बीच उसे रूसी कम्युनिस्ट सरकार ने 1922 में व्यापारियों की जासूसी करने के लिए फ्रैंकफुर्ट में भेजा. सोवियत रूस के लिए वो कितना महत्वपूर्ण था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस ने उसे 1933 में जापान में जासूसी नेटवर्क खड़ा करने की जम्मेदारी. इसी ने 14 सितंबर 1941 में रूस को सूचना दी कि जापानी सेना रूस पर हमला करने नहीं जा रही, बल्कि साइबेरिया में सिविल वार को बढ़ावा देने की तरफ उसका ध्यान है. रिचर्ड सोर्गे 18 अक्टूबर 1941 में टोकियो में गिरफ्तार किया गया, जब उसकी प्रेमिका ने उसकी एक पर्ची फेंक दी. उसने पकड़े जाने पर खुद के रूसी होने से इनकार कर दिया. उसे रूस ने भी युद्ध कैदी के तौर पर स्वीकार नहीं किया और वो टॉर्चर होता रहा. रिचर्ड सोर्गे को 7 नवंबर 1944 को फांसी दे दी गई. सोवियत रूस ने 1964 में उसे अपना जासूस स्वीकार किया. इससे पहले उसके रूसी जासूस होने का बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाया था.

1954 में पश्चिमी जर्मनी के फिल्मकार वेट हैरलान ने जापान में सोर्गे की भूमिका पर एक फिल्म बनाई. फिल्म का नाम बीट्रेयल आफ जर्मनी है. हैरलान नाजियों के प्रचार मंत्री जोसेग गोएबल्स का पसंदीदा फिलमकार था, जिसने कई प्रोपेगेंडा फिल्मे बनाईं. इस फिल्म को पश्चिमी जर्मनी में रीलिज के दो दिन बाद ही प्रतिबन्धित कर दिया गया था जिसे फिर से सम्पादित करने के बाद ही जारी किया जा सका. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
First International Urdu Weekly

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

गृहयुद्ध की ओर बढ़ता पाकिस्तान

पाकिस्तान में सार्वजनिक स्थलों एवं इबादतगाहों पर जिस तरह से बम धमाके और आत्मघाती हमले हो रहे हैं, हत्या-लूटमार का बाज़ार गर्म है और क्षेत्रीय एवं भाषाई उन्माद चरम पर है, उससे लगता है कि यह देश 1971 वाली स्थिति से एक बार फिर गुज़र रहा है. सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सरकार इस ख़तरनाक रुझान को रोक पाएगी या फिर गृहयुद्ध में फंसकर एक बार फिर देश का विभाजन हो जाएगा?

वसीम अहमद

पाकिस्तान के हालात के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वहां कब क्या स्थिति होगी. बम धमाके और आत्मघाती हमले आम ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. धार्मिक उन्माद और इबादतगाहों पर हमले आम बात हो चुकी है. बम धमाकों और हमलों में अब तक सैकड़ों निर्दोषों की जानें जा चुकी हैं. हर धमाके के बाद सरकार हरकत में आती है, आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई करती है, कुछ लोगों की पकड़-धकड़ होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर सब कुछ पहले जैसा चलने लगता है. अभी हाल में सिंध सूबे के शिकारपुर के इमामबाड़े में हुए एक बम धमाके में 57 लोगों की जानें चली गईं. इससे पहले पेशावर के एक आर्मी स्कूल पर हमला हुआ और 132 बच्चों समेत 142 लोगों की जानें चली गईं. ये दो बड़ी घटनाएं बिल्कुल ताज़ा हैं. वैसे ऐसी अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं.

अब सवाल यह पैदा होता है कि आख़िर पाकिस्तान सरकार ऐसी घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लगा पाती? आख़िर ज़र्ब-ए-अज़ब और खैब़र-1 जैसे ऑपरेशन के बाद भी आतंकवाद ख़त्म क्यों नहीं होता? इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए हमें पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य का जायज़ा लेना होगा. पाकिस्तान की स्थापना के समय से ही एक ऐसा वर्ग मौजूद है, जो धार्मिक कट्टरता पर कायम है. इस वर्ग को विशेष रूप से सिंध सूबे और वजीरिस्तान में फलने-फूलने का अवसर मिला. यह एक कबायली क्षेत्र है. कबायली सरकार के किसी भी ऐसे क़ानून को नहीं मानते, जो उनकी खानदानी परंपरा के विरुद्ध हो. यही वजह है कि सरकार की ओर से कई क़दम उठाए गए, कई ऑपरेशन हुए, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं निकले. भौगोलिक एवं पारंपरिक रूप से यह क्षेत्र कट्टरपंथियों के लिए बहुत प्रभावशाली-लाभकारी साबित हुआ. धार्मिक कट्टरपंथियों ने इस क्षेत्र को अपनी पनाहगाह बनाया. 2007-08 में सिपाहे सहाबा ने इसी क्षेत्र के सेखर में अपना ज़बरदस्त नेटवर्क फैलाया था. दूसरी ओर तालिबानियों ने ब्लूचिस्तान और दक्षिणी पंजाब से सटे क्षेत्रों में अपनी जड़ें मज़बूत कीं. हक्कानी नेटवर्क ने यहां से धार्मिक हिंसा को हवा देने के लिए मैदान तैयार किया. यह क्षेत्र हिंसा की ज़मीन तैयार करने के लिए उपजाऊ रहा है.

पाकिस्तान सरकार की ग़लती यह है कि उसने कभी इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं किया कि कट्टरपंथियों को क़बायलियों की ओर से सहयोग मिलने का असल कारण क्या है. आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर इस क्षेत्र में बेरोज़गारी, व्यवसायिक अवसरों एवं मूलभूत सुविधाओं, जैसे शिक्षा, बिजली-पानी का अभाव आदि दूर करने के लिए गंभीर कोशिश नहीं की गई. इसका अंजाम यह हुआ कि नौजवान तेज़ी से इन कट्टरपंथी जमाअतों में शामिल होते चले गए. जब उनकी ताकत बहुत बढ़ गई और पानी सिर से ऊपर बहने लगा, तो सरकार ने उन्हें कुचलने की कोशिश की. ज़र्ब-ए-अज़ब और खैब़र-1 ऑपरेशन के नाम पर उत्तरी वज़ीरिस्तान में ज़बरदस्त सैन्य कार्यवाही हुई. वज़ीरिस्तान के मशहूर क्षेत्रों, जैसे मीर अली, मीर निशाह, दत्ता खैल, बोया एवं वानावरदीगान आदि में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हुए. उक्त ऑपरेशनों के चलते कुछ आतंकवादी और जेहादी संगठनों के लोग गिरफ्तार किए गए या मारे गए, लेकिन जो मज़बूत व प्रभावशाली थे, जैसे हक्क़ानी नेटवर्क आदि, वे सब अफगानिस्तान में स्थानांतरित हो गए. परेशान वे हुए, जो आम आदमी थे. उन्हें बेघर होकर दूसरे क्षेत्रों में पनाह लेनी पड़ी.

उत्तरी वज़ीरिस्तान से लगभग तीन लाख लोग पलायन करके पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं. वे अपना घर-बार छोड़कर गए हैं. उन्हें दोबारा आबाद करने के लिए 70 करोड़ डॉलर की ज़रूरत होगी, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी धनराशि है. ज़ाहिर है, जो लोग पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं, उन्हें रोज़गार चाहिए. अगर रोज़गार न मिला, तो नौजवान हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं. पाकिस्तान के लिए यह एक गंभीर समस्या है. इन तमाम परिस्थितियों को जन्म देने के पीछे पाकिस्तान सरकार की दो मूल भूलें हैं. पहली यह कि वज़ीरिस्तान की रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते वहां के नौजवान आसानी से भटक गए और कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ते चले गए. दूसरी ग़लती यह कि सरकार ने धर्म के नाम पर कट्टरपंथी संगठनों को नज़रअंदाज़ कर दिया, जिसके चलते उक्त संगठन इस क्षेत्र के नौजवानों को गुमराह करने में कामयाब हो गए.

दिलचस्प बात यह है कि कट्टरपंथी संगठनों में भी दो समूह थे. एक समूह वह था, जो पाकिस्तान के अंदर तो कुछ नहीं करता था, लेकिन धर्म के नाम पर अफगानिस्तान, कश्मीर और भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी गतिविधियां अंजाम देता था. ऐसे लोगों में हाफिज़ सईद और लखवी आदि का नाम लिया जा सकता है. इस समूह को पाकिस्तान सरकार में उच्च पदों पर बैठी शख्सियतों द्वारा संरक्षण-समर्थन दिया जाता था. दरअसल, सईद और लखवी जैसे लोग या समूह दूसरे देशों में कुछ भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई नुक़सान नहीं पहुंचाते. लिहाज़ा, सरताज अज़ीज़ और परवेज़ मुशर्रफ़ जैसे क़द्दावर रहनुमा उनके हक़ में बयान दे चुके हैं. जो दूसरा समूह था, वह देश के अंदर हिंसा को बढ़ावा दे रहा था. उस समूह में सिपाहे सहाबा आदि शामिल थे. उस समूह ने शुरुआत में सिंध में कुछ जनहित के कार्य किए, जिसके चलते नौजवानों की एक बड़ी संख्या उससे जुड़ गई. जब उसकी ताक़त बढ़ गई, तो उसने धर्म के नाम पर पाकिस्तान के अंदर शिया और कादियानियों के विरुद्ध गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया. उनकी इबादतगाहों और इमामबाड़ों पर हमले किए. पाकिस्तान में मस्जिदों और इमामबाड़ों पर वर्ष 2014 में पांच बड़े हमले हुए, जिनमें 12 लोग मारे गए और 65 घायल हुए. वर्ष 2015 के पहले महीने में ही दो बड़े हमले हो गए. पहला हमला नौ जनवरी को रावलपिंडी के इमामबाड़े में हुआ, जिसमें आठ लोग मारे गए और 25 घायल हुए. फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह में शिकारपुर के एक शिया इमामबाड़े पर हमला हुआ, जिसमें लगभग 57 लोग मारे गए. हालांकि, अब सिपाहे सहाबा नामक संगठन कमज़ोर पड़ चुका है और वह ऐसे हमलों की ज़िम्मेदारी भी नहीं लेता, लेकिन उसने जिस मानसिकता की बुनियाद डाल दी है, वह अपना काम जारी रखे हुए है और धर्म के नाम पर दूसरे समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है. जाहिर है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है. जब शिया समुदाय की इबादतगाहों पर हमले होते हैं, तो जवाब में सुन्नी इबादतगाहों पर भी हमले होते हैं. और, इस सबके बीच पाकिस्तान गृहयुद्ध की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है. वज़ीरिस्तान के जो लाखों लोग इधर-उधर पनाह लिए हुए हैं, वे सब कबायली हैं और अपनी खानदानी परंपराओं के मुक़ाबले में किसी नियम-क़ानून को नहीं मानते. वे धार्मिक मामले में भी बहुत कट्टर होते हैं. लिहाज़ा, पाकिस्तान के लिए वे सब अलग एक ख़तरा बने हुए हैं.

ऐसे में इस आशंका को ख़ारिज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान एक तरफ़ धार्मिक हिंसा और दूसरी तरफ़ वज़ीरिस्तान के दबाव में है और एक बार फिर दो हिस्सों में बंट सकता है. वज़ीरिस्तान उसी तरह स्वयं को पाकिस्तान से अलग होने का दबाव बनाना शुरू कर सकता है, जिस तरह बांग्लादेश ने धार्मिक बुनियाद पर स्वयं को अलग कर लिया था. अगर किसी देश में जनता का रुझान केंद्रीय विचारधारा के विरुद्ध दिशा में हो, तो वह देश विभाजन के ख़तरे में पड़ जाता है. यह स्थिति पाकिस्तान में चरम पर है. सरकार देश में लोकतंत्र की बहाली और सबके लिए समान अधिकारों का दावा करती है, धार्मिक भेदभाव को ख़ारिज करती है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में जनता धार्मिक भेदभाव में इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि अगर एक मसलक पर आफत आती है, तो दूसरी उस ओर ध्यान नहीं देती. इसकी मिसाल शिकारपुर में देखी गई, जहां एक धार्मिक स्थल पर हुए हमले में 57 लोग मारे गए, लेकिन अफ़सोस कि वहां के चैनलों और अख़बारों में इस घटना को कोई विशेष कवरेज नहीं दी गई. निश्चित तौर पर यह निहायत घटिया सोच है. यह सोच सवाल खड़ा करती है कि क्या पाकिस्तान की जनता इस हद तक बंट चुकी है कि उसके लिए दूसरी मसलक वालों के खून की कोई अहमियत नहीं है. अगर वाकई यही स्थिति है, तो मतलब साफ़ है कि देश गृहयुद्ध और विभाजन की ओर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

ताइवान में विमान दुर्घटना, 31 की मौत

राजधानी ताइपे के पास कीलुंग नदी में गिरे ट्रांस एशिया के विमान में सवार 31 लोगों के मारे जाने की पुष्टि अब तक हो चुकी है. हादसे के बाद राहत एवं बचाव दल ने 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया था. ताइवान के विमानन अधिकारियों के मुताबिक़, मृतकों में विमान के पायलट एवं सह-पायलट भी शामिल हैं. इस विमान में सवार यात्रियों में से 31 चीन के निवासी थे. ट्रांस एशिया के विमान संख्या एटीआर-72 ने ताइपे के सोंघसान हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी. वह किनमेल आइलैंड जा रहा था. ट्रांस एशिया ताइवान की एक विमानन कंपनी है, जो घरेलू रूटों के साथ-साथ कुछ अंतरराष्ट्रीय रूटों पर भी अपनी सेवाएं देती है. ट्रांस एशिया के निदेशक पीटर चेन ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया. स्थानीय मीडिया में प्रसारित की जा रही पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हुई बातचीत में पायलट ने इंजन में आग लगने की बात कही है.■

पाक में ओबामा के भारत दौरे का असर

भारत के गणतंत्र दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुख्य अतिथि बनने के बाद पाकिस्तान अपनी सालाना सैन्य परेड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने जा रहा है. पाकिस्तान में सालाना सैन्य परेड सात साल बाद होने वाली है. पाकिस्तान में इस तरह की परेड अंतिम बार 28 मार्च, 2008 में तब हुई थी, जब परवेज़ मुशर्रफ़ राष्ट्रपति थे. बिगड़ती क़ानून व्यवस्था की वजह से यह परेड बंद कर दी गई थी. इसमें सेना के तीनों अंगों के प्रमुख समेत तमाम अधिकारी भाग लेते हैं और तरह-तरह के सैन्य साजो-सामान का प्रदर्शन किया जाता है. भारत में इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूदगी एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक नए गठजोड़ के तौर पर देखी गई है.■

रूसी बच्चे के सीने में भारतीय दिल

दो साल नौ महीने का ग्लेब कुद्रिआत्सेव भारत में सफलतापूर्वक शिशु हृदय प्रतिरोपण कराने वाला पहला बच्चा है. यह ऑपरेशन चेन्नई में हुआ. ग्लेब को बंगलुरू के मणिपाल हॉस्पिटल में 18 दिसंबर को ब्रेन डेड घोषित किए गए दो साल के एक बच्चे का दिल लगाया गया. ग्लेब कई मायनों में किस्मत वाला साबित हुआ. दो साल के बच्चे के दिल को एयर एंबुलेंस से रिकॉर्ड 47 मिनट में बंगलुरू से चेन्नई के फोर्टिस मालार हॉस्पिटल में लाया गया. डॉक्टरों ने चार घंटे के अंदर प्रतिरोपण की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली. सबसे बेहतरीन पहलू यह रहा कि प्रतिरोपण के सारे मापदंड मसलन दिल का वजन, ब्लड ग्रुप सभी मैच कर गए.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

आईएस ने पायलट को ज़िंदा जलाया

जॉर्डन के सरकारी टेलीविजन ने इस बात की पुष्टि की है कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने जिस पायलट को बंधक बनाया था, उसकी हत्या कर दी गई है. आईएस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि मोएज अल कसासबेह नामक इस पायलट को तब तक जलाया गया, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. वीडियो में एक लोहे के पिंजरे में आग की लपटें उठ रही हैं और उसके भीतर नारंगी रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति है. यह वीडियो ट्वीटर पर जारी किया गया. इस ट्वीटर एकाउंट के ज़रिये ही आईएस अपनी गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करता है. कसासबेह को पिछले साल दिसंबर महीने में उस वक्त बंधक बनाया गया था, जब उसका विमान सीरिया में रक्का के पास उड़ रहा था. यह विमान अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं की मदद के लिए जा रहा था. हत्या के वीडियो पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी. ओबामा ने कहा कि अगर यह सही है, तो यह आईएस की विचारधारा का दिवालियापन दिखाता है और इससे चरमपंथियों को नष्ट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता और मज़बूत होगी.■

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

एक दिन भरपेट खाने के बाद गधे की तबीयत मस्त होने लगी. वह भी लगा लोट लगाने. बाघ की खाल तो एक ओर गिर गई. गधे के लोट लगाने के समय पौधों के रौंदे जाने और चटकने की आवाज फैली. एक रखवाला चुपचाप बाहर निकला. खेत में झांका तो उसे एक ओर गिरी बाघ की खाल नजर आई और खेत से बाहर आता एक गधा दिखाई दिया. वह चिल्लाया अरे, यह तो गधा है. उसकी आवाज औरों ने भी सुनी. क्रोध से भरे रख वालों ने उसे वहीं ढ़ेर कर दिया. उसकी सारी पोल खुल चुकी थी. धोबी को भी वह नगर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा.

साई की महिमा अपरंपार

चौथी दुनिया ब्यूरो

एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे. गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के प्रति दोषारोपण में इतने कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी. बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करके विवाद उत्पन्न करते हैं. संत तो परदोषों को दूसरी दृष्टि से देखा करते हैं. उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की युक्ति भिन्न होती है. वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जिव्हा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार देखा जाए तो, वे दूसरों की निंदा करके उनका उपकार ही करते हैं, जिसके लिए दरअसल, वे धन्यवाद के पात्र हैं. निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साई बाबा की पद्धति सर्वथा भिन्न थी. वह तो सर्वज्ञ थे, इसलिए उस निंदक के कार्य को समझ गए. जब लेंडी के समीप उस भक्त से भेंट हुई, तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा कि देखो, वह कितने प्रेमपूर्वक विष्ठा खा रहा है. तुम जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश है. अनेक शुभ कर्मों के परिणामस्वरूप तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ और यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया, तो शिरडी तुम्हारी क्या सहायता कर सकेगी. कहने का तात्पर्य केवल यही है कि भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वह वहां से चला गया. इस प्रकार प्रसंगानुसार ही वह उपदेश दिया करते थे. यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए, तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर नहीं होगा.

आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए सबको अनवरत परिश्रम करना चाहिए. बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूं और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूं. केवल उनके भ्रम निवारणार्थ, जिनकी दृष्टि में वह साढ़े तीन हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए. इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण में आए और उन्होंने दिन-रात उनका ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई, जिस प्रकार माधुर्य एवं मिश्री, लहर एवं समुद्र और नेत्र एवं कांति में अभिन्नता हुआ करती है. जो लोग आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहें, वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें. दुखदायी-कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखी न करके सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भयरहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए. जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निस्संदेह आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी. उन्होंने अनेक लोगों से नाम का जापकर के अपनी शरण में आने को कहा. जो यह जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूं, बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण-मनन करने का परामर्श दिया. किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पाद पूजन, तो किसी को अध्यात्म रामायण, ज्ञानेश्वरी एवं धार्मिक ग्रंथों का पठन-अध्ययन करने को कहा. कई लोगों को उन्होंने अपने चरणों के समीप रखा, बहुतों को खंडोबा मंदिर भेजा और कई लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम का जाप और छांदोग्य उपनिषद एवं गीता का अध्ययन करने को कहा. उनके उपदेशों की कोई सीमा नहीं थी. उन्होंने किसी को प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत दिए. एक बार वह एक मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रगट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब उसने मद्यपान त्यागने की शपथ खाई, तभी उसे छोड़ा. किसी-किसी को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया और कुछ हठयोगियों को हठयोग छोड़ने की राय देकर चुपचाप बैठकर धैर्य रखने को कहा. उनके सुगम पथ और विधि का वर्णन असंभव है.

साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए. एक दिन बाबा ने राधाकृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा. एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके कहे अनुसार वामन गोंदकर के घर पर उसे लगाया. वह उनके घर पर चढ़ गए और राधाकृष्ण माई के छप्पर पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उतर आए. इसका अर्थ किसी की समझ में नहीं आया. राधाकृष्ण माई उस समय ज्वर से कांप रही थीं. इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कार्य किया हो. नीचे उतरने के बाद शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को दो रुपये पारिश्रमिक स्वरूप दिए. तब एक ने साहस करके उनसे पूछा कि इतने अधिक पैसे देना क्या अर्थ रखता है. उन्होंने कहा कि बिना परिश्रम का मूल्य चुकाए किसी से कार्य नहीं कराना चाहिए और कार्य करने वाले को उदार हृदय से मज़दूरी देनी चाहिए. यदि बाबा के इस नियम का पालन किया जाए, यानी मज़दूरी का भुगतान शीघ्र और संतोषप्रद हो, तो मज़दूर अधिक उत्तम कार्य करेंगे और लगन से कार्य करेंगे. फिर कार्य छोड़ने एवं हड़ताल जैसी कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी और न मालिक और मज़दूरों के बीच वैमनस्य पैदा होगा. ■

आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए सबको अनवरत परिश्रम करना चाहिए. बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूं और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूं. केवल उनके भ्रम निवारणार्थ, जिनकी दृष्टि में वह साढ़े तीन हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए. इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण में आए और उन्होंने दिन-रात उनका ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई, जिस प्रकार माधुर्य एवं मिश्री, लहर एवं समुद्र और नेत्र एवं कांति में अभिन्नता हुआ करती है.

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

नदियों को जोड़ने की जरूरत

देश के अनेक बुद्धिजीवियों की राय है कि देश में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटारा पाने का सर्वोत्तम उपाय नदियों को जोड़ने की नीति है. बरसात के मौसम में जब बांधों में पानी छोड़ा जाता है तो सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और कई गांव बाढ़ में डूब जाते हैं. कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनावृष्टि की स्थिति में सूखा पड़ जाता है. नदियों को जोड़ने से यह लाभ होगा कि जहां अतिरिक्त पानी है, उसे कम पानी वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर हम बाढ़ और सूखे दोनों से देशवासियों को बचा सकते हैं.

-राजकिशोर पाण्डेय, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

व्यक्तित्व की लड़ाई

कवर स्टोरी-दिल्ली विधानसभा चुनाव, मद्दे की नहीं व्यक्तित्व की लड़ाई है(02 फरवरी-08 फरवरी 2015) पढ़ा. मनीष कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपने जो विचार व्यक्त किए हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं. दिल्ली विधानसभा चुनाव मुद्दों के बजाय व्यक्तितत्व की लड़ाई हो गया था और व्यक्तित्व के आगे मुद्दे गौड़ हो गए थे. भाजपा हो या आम आदमी पार्टी दोनों ही मुद्दो को भूल गई थीं. कोई भी जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठा रहा था. आम आदमी पार्टी किरन बेदी पर हमला कर रही थी और भाजपा भी केजरीवाल पर वार-वार पर कर रही थी. अब यह देखना होगा कि दिल्ली वालों को सरकार कितनी सुविधाएं देती है.

-कपिल विश्वकर्मा, पालम, दिल्ली

नीतीश के गले की फांस बने मांझी

आलेख-दल और सरकार दोनों में दरार(02 फरवरी-08 फरवरी 2015)पढ़ा. बहुत अच्छा आलेख है. सुकांत का यह आलेख जदयू और उसकी सरकार दोनों पर अपने तथ्यपरक विचार व्यक्त किए हैं. नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया कि उनको रिमोट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन मांझी ने नीतीश को ही ठेंगा दिया. मांझी ने बार-बार नीतीश के खिलाफ जाकर बयान देते हैं, जिससे सरकार और पार्टी दोनों की किरकिरी होती है. नीतीश कुमार की गली की हड्डी बन चुकें हैं जीतन राम मांझी, जिसे नीतीश न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं. नीतीश अगर मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाते हैं तो उनको डर है कि उनका दलित मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव में उनसे कट जाएगा. मांझी नीतीश के लिए गले की फांस बन चुके हैं.

-पवन कुमार, बक्सर, बिहार.

सपा का अन्तर्विरोध

आलेख-समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन, पिचा-पुत्र की सामान्तर सूची नेता-कार्यकर्ता हैरान(02 फरवरी-08 फरवरी 2015) पढ़ा काफी विचारोत्तेजक आलेख है. प्रभात रंजन दीन का आलेख यह बताता है कि सपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव बार-बार अखिलेख सरकार पर सवाल खड़ कर चुके हैं और अखिलेश के मंत्रियों को भी नसीहत चदे चुके हैं. यह सूची जारी होने के बाद तो आपस में ही घनघोर अंतर्विरोध नजर आता है. अब सपा को लेकर ऐसे कई सवाल खड़े होने लगे हैं. मुलायम सिंह यादव का अखिलेश सरकार के खिलाफ सवाल खड़ा करना ही दिखाता है कि वह अखिलेश सरकार के कामकाज को लेकर संतुष्ट नहीं है. सपा प्रमुख जानते हैं कि अगर अखिलेश सरकार सही तरीके से काम नहीं की तो सपा को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

-रामेश्वर सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

चुनाव से मुद्दे गायब

जब तोप मुकाबिल हो-बहस से असल मुद्दा गायब है (02 फरवरी-08 फरवरी 2015) जानकारी परक संपादकीय है. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि बहस असल से मुद्दा गायब है और उन्होंने अपने संपादकीय में कही है कि किरण बेदी और अरबिंद केजरीवाल की गहरी दोस्ती में भी एक प्रतिद्धंद्धिता छिपी हुई थी. दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यही दिखाई दे रहा है. इस चुनाव में व्यक्तित्व की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई थी कि मुद्दों के बजाय दोनों ही एक दूसरे पर वार करने में ज्यादा समय बिता रहे थे. दिल्ली विधानसभा चुनाव ही नहीं अब यह लोकसभा चुनाव हो या किसी राज्य का विधानसभा चुनाव उसमें मुद्दों के बजाय एक दूसरे पर हमले होने लगते हैं. शायद राजनीति में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की एक रवायत चल पड़ी है. इसी के चलते राजनेता कीचड़ उछालते-उछालते वह कब कीचड़ में चला जाता है, उसे पता ही नहीं चल पाता. इसलिए राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को चाहिए कि वह व्यक्तित्व के बजाय मुद्दे पर चुनाव लड़ें.

-अंकित शुक्ला, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.

प्रभावित करता समाचार पत्र

चौथी दुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित सभी खबरें एक से बढ़कर एक होती हैं. चौथी दुनिया के (02 फरवरी-08 फरवरी 2015) अंक में प्रकाशित कवर स्टोरी-दिल्ली विधानसभा चुनाव, मद्दे की नहीं व्यक्तित्व की लड़ाई है. पढ़ा. जो तथ्यों पर आधारित स्टोरी है. बिल्कुल सही है कि अब चुनाव से मुद्दे गायब हो चुके हैं, केवल व्यक्तित्व की लड़ाई हो रही है. यही लोकसभा चुनाव में भी हुआ और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ. इस अंक में जब तोप मुकाबिल हो-बहस से असल मुद्दा गायब है, भाजपा परिवर्तन के दौर से गुर रही है और भाग्य की राजनीति समेत सभी खबरें बेहद प्रभावित करेन वाली हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र में सप्ताह भर की पूरी खबरें पढ़ने को मिल जाती है. चौथी दुनिया समाचार पत्र को अपना यह सिलसिला ऐसे ही जारी रखना चाहिए.

-पूनम यादव, समस्तीपुर, बिहार.

कहानी

बहरूपिया गधा

एक नगर में धोबी था. उसके पास एक गधा था, जिस पर वह कपड़े लादकर नदी तट पर ले जाता और धुले कपड़े लादकर लौटता. एक दिन नदी किनारे जब धोबी ने कपड़े सूखने के लिए बिछा रखे थे तो आंधी आई. कपड़े इधर-उधर हवा में उड़ गए. अपने कपड़े ढूंढता हुआ वह सरकंडो के बीच घुसा. वहां उसे एक मरा बाघ नजर आया. धोबी कपड़े लेकर लौटा और गट्ठर गधे पर लादने लगा गधा लड़खड़ाया. धोबी ने देखा कि उसका गधा इतना कमजोर हो गया है कि एक दो दिन बाद बिल्कुल ही बैठ जाएगा. वह सोचने लगा अगर मैं उस बाघ की खाल उतारकर ले आऊं और रात को इस गधे को वह खाल ओढ़ाकर खेतों की ओर भेजूं तो लोग इसे बाघ समझकर डरेंगे. कोई निकट नहीं फटकेगा. गधा खेत चर लिया करेगा. धोबी ने ऐसा ही किया. शाम को लौटते समय वह खाल को कपडों के बीच छिपाकर घर ले आया. रात को जब सब सो गए तो उसने बाघ की खाल गधे को ओढाई. गधा दूर से देखने पर बाघ जैसा ही नजर आने लगा. फिर उसने गधे को खेतों की ओर खदेड़ दिया. गधे ने एक खेत में जाकर फसल खाना शुरु किया. रात को खेतों की रखवाली करने वालों ने खेत में बाघ देखा तो वे डरकर भाग गए. गधे ने भरपेट फसल खाई और रात अंधेरे में ही घर लौट आया. हर रात धोबी उसे खाल ओढ़ाकर छोड़ देता. गधे को बाघ समझकर सब अपने घरों में दुबककर बैठे रहते. फसलें चर-चरकर गधा मोटा होने लगा. धोबी भी खुश हो गया.

एक दिन भरपेट खाने के बाद गधे की तबीयत मस्त होने लगी. वह भी लगा लोट लगाने. बाघ की खाल तो एक ओर गिर गई. गधे के लोट लगाने के समय पौधों के रौंदे जाने और चटकने की आवाज फैली. एक रखवाला चुपचाप बाहर निकला. खेत में झांका तो उसे एक ओर गिरी बाघ की खाल नजर आई और खेत से बाहर आता एक गधा दिखाई दिया. वह चिल्लाया अरे, यह तो गधा है. उसकी आवाज औरों ने भी सुनी. क्रोध से भरे रखवालों ने उसे वहीं ढ़ेर कर दिया. उसकी सारी पोल खुल चुकी थी. धोबी को भी वह नगर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा. ■

शिक्षा-पहनावा बदलकर दूसरों को कुछ ही दिन धोखा दिया जा सकता हैं. अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

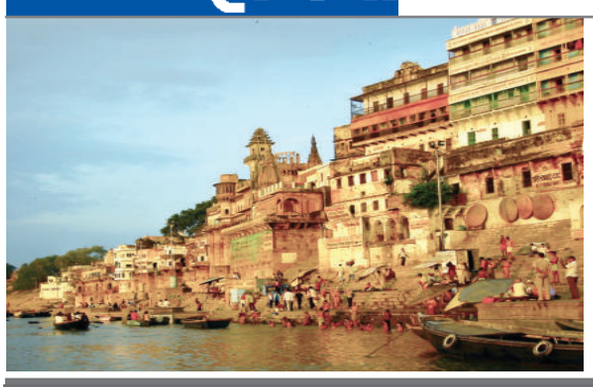

दु:ख कम होने के बाद लंबू ने, जो मुंबई में किसी अख़बार में नौकरी खोजने गया था और बैरंग लौटा था, अपने मुंबई प्रवास की कहानी सुनाई. उसने बताया कि वह नौकरी के सिलसिले में जिस बनारसी दोस्त के कमरे पर ठहरा था, वह एक पुराने यूपी वाले भइया का मकान था. दोस्त एक हिंदी अख़बार में मुलाजिम था और उसके लिए भी कोशिशें कर रहा था. एक अख़बार में उसके लिए बात कर उसने साक्षात्कार की व्यवस्था की थी, लेकिन वह वर्तमान राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाया था.

साहित्य को समेटता विशेषांक

अनंत विजय

हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में साहित्य विशेषांक निकालने की परंपरा रही है. कोलकाता से उत्सव के मौक़े पर जनसत्ता का साहित्य विशेषांक और नागपुर से प्रकाशित लोकमत का साहित्य विशेषांक के अलावा कई साहित्यिक पत्रिकाओं के विशेषांक निकलते रहे हैं. किसी जमाने में इंडिया टुडे सालाना साहित्य विशेषांक निकालता था. बाद में हिंदी के वरिष्ठ कवि विष्णु नागर शुक्रवार साप्ताहिक के संपादक बने, तो उन्होंने भी साहित्य विशेषांक निकाले थे, लेकिन जनसत्ता और लोकमत को छोड़कर लगभग सभी साहित्य विशेषांकों का प्रकाशन स्थगित हो चुका है. भारतीय ज्ञानपीठ की प्रतिष्ठित पत्रिका नया ज्ञानोदय भी कई साहित्य विशेषांक निकाल चुका है.

नया ज्ञानोदय की कमान संभालने के बाद हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक लीलाधर मंडलोई के संपादन में नया ज्ञानोदय की साहित्य वार्षिकी 2015 हाल ही में बाज़ार में आई है. क़रीब तीन सौ पृष्ठों के इस विशेषांक में निराला से लेकर सविता भार्गव तक की रचनाएं शामिल हैं. इस विशेषांक को उन्नीस हिस्सों में विभक्त किया गया है. अगर कविता के तीन खंडों को एक मान लें, तो सत्रह होते हैं. पुरखों के कोठार से खंड में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर रायकृष्ण दास, राम विलास शर्मा और हरिशंकर परसाईं. संपादक लीलाधर मंडलोई का मानना है कि ये लेखक हमारे इतिहास के कलंदर हैं. इनका अपना संघर्ष था, वीतराग था इनका. संपादक ने पाठकों को भरोसा दिया है कि नया ज्ञानोदय की पुरखों के कोठार से रचनाएं निकाल कर नए पाठकों के सामने प्रस्तुत करने की पहल जारी रहेगी. लेखक मनोज मोहन ने बेहद ही गंभीर मसले पर विचारोत्तेजक बहस आयोजित की है.

इस परिचर्चा का विषय है, उदारवाद में साहित्य–संस्कृति का वर्तमान और सहभागी हैं, अशोक वाजपेयी, कृष्ण कुमार, प्रेमपाल शर्मा, विष्णु नागर, मनीषा कुलश्रेष्ठ एवं चित्रकार अशोक भौमिक. उदारवाद के साहित्य एवं संस्कृति पर पड़ने वाले असर को लेकर तमाम लेखक और बुद्धिजीवी चिंतित नज़र आते हैं, लेकिन अशोक वाजपेयी बेहद साफ़गोई से कहते हैं, वैचारिक आंदोलन के न होने का अर्थ विचार का न होना नहीं है. वाजपेयी के मुताबिक, यह सांस्कृतिक शून्यता है, पर बाहर से किन्हीं शक्तियों ने नहीं लाद दी है. हमने स्वयं उसकी रचना में उसकी भूमिका निभाई है. उससे उबरना तब शुरू होगा, जब हम आत्माभियोग के भाव से अपनी हिस्सेदारी स्वीकार करें. ऐसे स्वीकार से नया प्रतिरोध, नए रूपाकार उभर सकते हैं. लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ का मानना है कि नव–उदारवाद के पीछे विचारहीन पीढ़ी की पीढ़ी छद्म ज्ञान का मुखौटा ओढ़े खड़ी है. ऐसी ही कई दिलचस्प टिप्पणियां इस परिचर्चा में हैं, जो पाठकों को एक नई दिशा की तरफ़ सोचने के लिए मजबूर कर सकती हैं.

इस अंक में वरिष्ठ पत्रकार दिनकर कुमार ने असमिया के मशहूर गायक एवं संगीतकार भूपेन हजारिका की संक्षिप्त जीवनी लिखी है. यह हिंदी के पाठकों को भूपेन की ज़िंदगी से रूबरू कराती है. इस विशेषांक में एक और नई पहल, कह सकते हैं, शुरू हुई है कि हिंदी की अलग–अलग विधाओं की किताबों के लेखक–पाठक सर्वेक्षण प्रकाशित हैं. उपन्यासों में काशी नाथ सिंह के उपसंहार, ज्ञान चतुर्वेदी के हम न मरब और भगवान दास मोरवाल के नरक मसीहा को क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला है. इसी तरह केदार नाथ सिंह, अशोक वाजपेयी और लीलाधर जगूड़ी के संग्रह को कविता की सूची में स्थान मिला है. अगर यह परंपरा कायम रह सकती है, तो हिंदी में बेस्ट सेलर की तरह की एक अवधारणा का विकास हो सकेगा. भीतर नैन बिसाल में नामवर सिंह और शम्सुर्रहमान फारुकी के दो लेख प्रकाशित हैं. भारतीय संस्कृति हमेशा से बहुलता की पक्षधर रही है. इस देश में कई भाषाएं, कई जातियां और कई धर्म हैं. इसके अलावा यहां कई उपजातियां एवं संस्कृतियां एक साथ सदियों से रहती और विकसित होती आई हैं. कई लोगों का मानना है कि भारत की यह बहुलतावादी संस्कृति आज ख़तरे में है. नामवर जी ने इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया है.

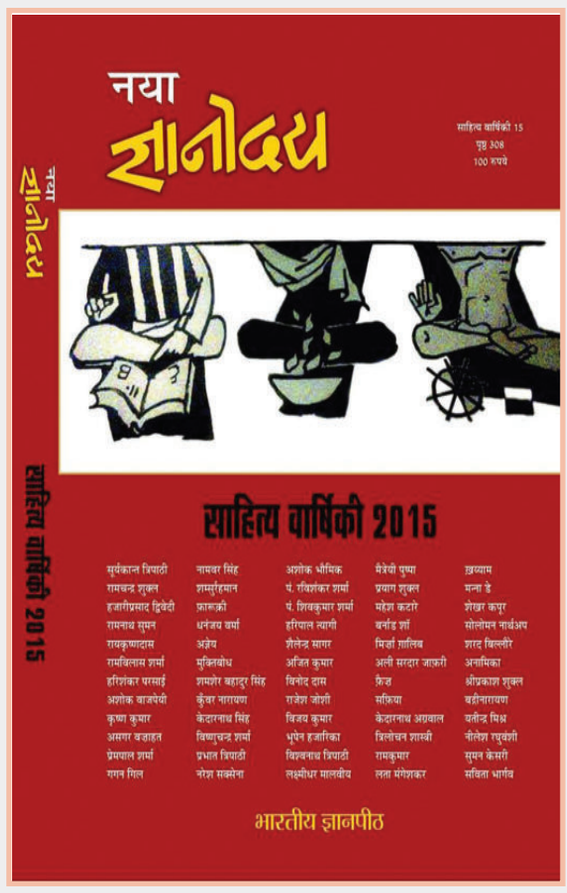

नामवर सिंह ने कहा कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, उस दौर में ख़तरा स्वयं संस्कृति पर है और आप जानते हैं कि संस्कृति एकवचन शब्द नहीं है, संस्कृतियां होती हैं और इसलिए संस्कृति हमेशा बहुवचन होती है. सभ्यताएं दो-चार होंगी, लेकिन संस्कृतियां सैकड़ों होती हैं. इसलिए ऐसे दौर में, जहां संस्कृति की बहुलता को संकट हो और तमाम संस्कृतियों की बहुलता पर पटेला चलाते हुए समतल करने का प्रयास किया जा रहा हो, उस सांस्कृतिक बहुलता को नष्ट होते हुए देखकर स्वभावतय: चिंता होती है. इसके अलावा गालिब पर मीर की शायरी के प्रभाव को परखते हुए शम्सुर्रहमान फारुकी का बेहद विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित है.

नामवर सिंह ने कहा कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, उस दौर में ख़तरा स्वयं संस्कृति पर है और आप जानते हैं कि संस्कृति एकवचन शब्द नहीं है, संस्कृतियां होती हैं और इसलिए संस्कृति हमेशा बहुवचन होती है. सभ्यताएं दो–चार होंगी, लेकिन संस्कृतियां सैकड़ों होती हैं. इसलिए ऐसे दौर में, जहां संस्कृति की बहुलता को संकट हो और तमाम संस्कृतियों की बहुलता पर पटेला चलाते हुए समतल करने का प्रयास किया जा रहा हो, उस सांस्कृतिक बहुलता को नष्ट होते हुए देखकर स्वभावतय: चिंता होती है. इसके अलावा गालिब पर मीर की शायरी के प्रभाव को परखते हुए शम्सुर्रहमान फारुकी का बेहद विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित है. पत्र लेखन किसी जमाने में साहित्य की एक विधा के रूप में स्थापित था, लेकिन तकनीक के विकास ने साहित्य की इस विधा को लगभग ख़त्म–सा कर दिया है. पहले साहित्यकारों के बीच पत्रों में गंभीर विमर्श हुआ करते थे. अब उसकी जगह फेसबुक आदि ने ले ली है. लेकिन, फेसबुक आदि पर वह आत्मीयता नहीं महसूस की जा सकती है, जो पत्रों से महसूस होती थी. वर्चुअल दुनिया में आत्मीयता की बात करना ही बेमानी है. इस अंक में कई महत्वपूर्ण शख्सियतों के बीच पत्र व्यवहार प्रकाशित है. जवाहर लाल नेहरू और बर्नाड शॉ, मिर्जा गालिब के कई पत्र, अली सरदार जाफरी के बेगम सुल्ताना के नाम खत, फैज का अपनी पत्नी के नाम खत के अलावा मुक्तिबोध, केदार नाथ अग्रवाल और हरिशंकर परसाईं के भी कई दिलचस्प पत्र संकलित हैं.

अपने एक पत्र में मुक्तिबोध ने लिखा है, उम्र ज्यों–ज्यों बढ़ती जाती है, सफेद होती है, त्यों–त्यों ख़तरों से डरती है. मुक्तिबोध ने तब लिखा था, आज की कविता उलझी परिस्थितियों की ओर या उसके भीतर पाई जाने वाली ग्रंथिल मन:स्थितियों की कविता है. इसलिए शायद उसमें से उलझाव हटाना होगा. जैसे सड़क साफ़ होती है, वैसी ही वह हो. चक्करदार गलियों में चलने वालों को भी चक्कर नहीं आने चाहिए और मकान मिल जाना चाहिए. उन्होंने अपने पत्र में कविता के शिल्प में असावधानी की ओर भी इशारा किया था. कुल मिलाकर अगर हम देखें, तो भारतीय ज्ञानपीठ के सत्तर साल पूरे होने के मौक़े पर नया ज्ञानोदय की इस साहित्य वार्षिकी में पाठकों के लिए ढेर सारी पठनीय और सहेजने योग्य सामग्री है. इस आयोजन के लिए संपादक लीलाधर मंडलोई साधुवाद के पात्र हैं. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

विमल चंद्र पांडेय

लोकल

वे दोनों शीतला मंदिर से थोड़ा आगे निकले और सीढ़ियों पर बैठ गए. मोटे ने अपना हैंडीकैम निकाला और दूर नहा रहीं युवतियों पर फोकस करने लगा. तीसरा विश्वनाथ गली में रहता था और एक सांध्यकालीन अख़बार में पत्रकार था. उसका घर घाट के किनारे था. घाट के निवासी यानी घटियारे लोग घाट के सब राज़ जानते थे और इस सहारे वे धर्म के भी सभी राज जानने का दावा करते थे. वह काफी लंबा था और दूर से ही नज़र आ जाता था. थोड़ी देर में वह दोनों के बताए स्थान पर पहुंचा और पहुंच कर उनके पास बैठ गया.

माल है? उसे देखते ही मोटे ने जिज्ञासा व्यक्त की.

हां, उसने संक्षिप्त जवाब दिया और हाफ जैकेट की भीतरी जेब से एक पीली पन्नी निकाली, जो बारात में नमकीन खिलाने के काम में आती थी और जिसे दबाकर बंद किया जाता था. उसने पन्नी में से कुछ सूखे–निचुड़े पौधों के टुकड़े निकाले और उनकी सफ़ाई करने लगा.

देखें महकें जरा, चश्मे वाले ने चेहरा आगे किया और तीसरे ने हथेली में रखी चीज़ एक बार चश्मे वाले की नाक के सामने से घुमा दी.

तगड़ा है, चश्मे वाले ने महक न पाने के बावजूद खुद के अनुभवी गंजेड़ी होने का दावा पेश करने के लिए कहा.

मोटे ने उसे एक बार देखा और फिर रिकॉर्डिंग में लग गया.

सूरज उग रहा है, उससे जूम करके फिर नीचे आते हैं, जहां सब लोग नहा रहे हैं, मोटे ने कैमरे के व्यूफाइंडर में देखते हुए कहा, पता चलेगा कि सुबह से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, मोटे ने अपना पत्रकारिता ज्ञान दिखाना चाहा.

अरे,, सूरज–फूरज से क्या मतलब है? भीड़ तो रहबे करेगी नहान का दिन है तो. कोई दमदार स्टोरी चाहिए. दिमाग काम नहीं कर रहा है. कुछ बताओ बे, अलग–सी स्टोरी आज के लिए नहान में से.., चश्मे वाले ने लंबू की ओर देखा.

खाली करो इसको, लंबू ने चश्मे वाले को एक सिगरेट निकाल कर देते हुए कहा. चश्मे वाला सिगरेट को हल्के–हल्के मसल कर उसके अंदर की तंबाकू निकालने लगा.

लंबू ने जेब से एक पतला पारदर्शी कागज़ निकाला और मसले हुए पौधों में से छोटे गोल आकार के बीज निकाल कर फेंकने लगा. फिर उसमें थोड़ी–सी सिगरेट की निकली हुई तंबाकू मिलाई और उस मसाले को और साफ़ और महीन करने में जुट गया.

हम लोग त बढ़िया स्टोरी बना ही लेंगे, लेकिन ई सेटेलाइट वाले तो किसी काम के नहीं हैं. अभिजीतवा वहीं दसास्वमेधे घाट से दस मिनट का फुटेज लेकर निकल गया. कहा इतने में काम हो जाएगा, मोटे ने संतुष्टि की भावना ज़ाहिर करते हुए कहा.

इनको पूछता कौन है? हम लोग लोकल चैनल के हैं, तो यहां का स्नान कैसा रहा, ये देखने के लिए लोग हमारी ख़बर देखेंगे, न कि कोई सेटेलाइट चैनल, जिस पर सरवा दिल्ली में लूट, दिल्ली में बलात्कार चल रहा होगा, चश्मे वाले ने अधिक जानकारी और समझ होने का सुबूत दिया. थोड़ी देर के लिए फिर खामोशी छा गई. घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी और बीच–बीच में कुछ विदेशी भी घाटों की शोभा अपने कैमरे में कैद करते आगे बढ़ रहे थे. चश्मे वाले के फोन पर एक मिस्डकॉल आई और उसने फोन मिलाया. यह अपडेट देने के बाद कि मौसम में कोई खास ठंड नहीं है और नाश्ता वह सही समय पर कर लेगा, उसने फोन काट दिया. उसके फोन काटने पर मोटे को कुछ याद आया और उसने कैमरा बंद कर दिया.

एयरसेल रोमिंग फ्री करने वाली है पूरे इंडिया में, उसने कहकर बाकी दोनों के चेहरे देखे. चश्मे वाले के चेहरे पर उत्साह दिखा.

सही में? कौन बताया?

अख़बार में निकला था एक दिन. एकाध महीने में हो जाए शायद, उसने विश्वास के साथ कहा.

लंबू ने बात बीच में लपक ली, अपने ही देश में रोमिंग का क्या मतलब? पूरे देश में लोकल लगना चाहिए. ये क्या कि यूपी में हैं, तो लोकल और जबलपुर गए, तो रोमिंग?

चश्मे वाले ने महक न पाने के बावजूद खुद के अनुभवी गंजेड़ी होने का दावा पेश करने के लिए कहा. मोटे ने उसे एक बार देखा और फिर रिकॉर्डिंग में लग गया. सूरज उग रहा है, उससे जूम करके फिर नीचे आते हैं, जहां सब लोग नहा रहे हैं, मोटे ने कैमरे के व्यूफाइंडर में देखते हुए कहा, पता चलेगा कि सुबह से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, मोटे ने अपना पत्रकारिता ज्ञान दिखाना चाहा. अरे,, सूरज-फूरज से क्या मतलब है? भीड़ तो रहबे करेगी नहान का दिन है तो. कोई दमदार स्टोरी चाहिए.

हां, और क्या. एक कंपनी कर देगी, तो सब कर देंगी धीरे–धीरे, मोटे ने सहमति दी.

सही बात है, चश्मे वाले ने चश्मा उतार कर टी–शर्ट की किनारी से उसे साफ़ किया और बोला,तब...?

बंबई कब जा रहे हो माल चीरने? मोटे ने लंबे से मुंह उठाकर पूछा. मुंबई के नाम पर तीसरे के मुंह से एक हल्की कराह निकली, जिसे किसी ने सुना नहीं.

कितना देंगे सब सेलरी–वेलरी? अबकी चश्मे वाले ने पूछा. लंबू ने सिगरेट की डिबिया का ढक्कन फाड़कर थोड़े हिस्से से उस सिगरेट का फिल्टर बनाया, जो उसने उस पारदर्शी कागज़ को मोड़कर बनाया था. उसके बाद उसने स्वनिर्मित सिगरेट को अपने होंठों से लगाई और जलाकर एक लंबा कश खींचा.

मुंबई में हमको काम करना ही नहीं है, उसने इत्मीनान से धुआं उगलते हुए कहा. दोनों उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगे.

काहे बे, का हो गया? मोटे ने सहानुभूति भरे शब्दों में पूछा.

गुरु, मुंबई में लोग सही नहीं हैं, लंबू ने फ़ैसला सुनाया और सिगरेट चश्मे वाले की तरफ़ बढ़ा दी.

मोटा लड़का एवं चश्मे वाला लड़का थोड़ा और पास खिसक आए, ताकि लंबू के दु:ख में शामिल हो सकें. लंबू का दु:ख उसके आसपास बिखरा था और उसने सुल्फे के साथ अपना दु:ख तंबाकू में मिलाकर यह सिगरेट बनाई थी. सिगरेट के साथ दु:ख धीरे–धीरे धुएं में समाकर नष्ट हो रहा था. दोनों मित्रों की मदद से उस दु:ख को समाप्त करने का काम तेज़ी से हो रहा था और थोड़ी ही देर में काफी हद तक कम नज़र आने लगा.

दु:ख कम होने के बाद लंबू ने, जो मुंबई में किसी अख़बार में नौकरी खोजने गया था और बैरंग लौटा था, अपने मुंबई प्रवास की कहानी सुनाई. उसने बताया कि वह नौकरी के सिलसिले में जिस बनारसी दोस्त के कमरे पर ठहरा था, वह एक पुराने यूपी वाले भइया का मकान था. दोस्त एक हिंदी अख़बार में मुलाजिम था और उसके लिए भी कोशिशें कर रहा था. एक अख़बार में उसके लिए बात कर उसने साक्षात्कार की व्यवस्था की थी, लेकिन वह वर्तमान राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाया था.

अरे, हम लोग लोकल के राजा हैं. यहां आओ, तो बताएं कि लोकल पॉलिटिक्स में क्या दम है. हमसे पूछो कि अजय राय इस बार किस पार्टी से लड़ेंगे, तो बताएं. पूछो तो चिरईगांव में कितने प्रतिशत ओट पड़ेगा, वहू बता दें. चले हैं यूपीए–फूपिए, कॉमनवेल्थ के बारे में पूछने...■

क्रमश:

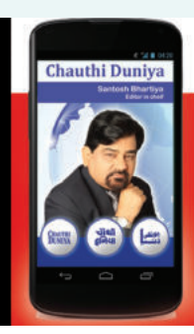

feedback@chauthiduniya.com

90 किमी प्रति घंटे का माइलेज देने वाली बाइक

बजाज ने एंट्री लेवल में अपनी पॉपुलर बाइक प्लेटिना का नया वर्जन लॉन्च किया है, जिसे बजाज प्लेटिना 100 ईएस (Platina 100 ES) नाम दिया गया है. इसमें 102 सीसी डीटीएसआई इंजन लगा है जो 8.2 बीएचपी का पावर और 12.75 एनएम का टॉर्क देने में सक्षम है. कंपनी का दावा है कि नई बजाज प्लेटिना ईएस 96.9 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज देती है. 100 ईएस में नई हैंडलाइट, पेंट स्कीम और नए डेकल आकर्षक ग्राफिक्स के साथ दिए गए हैं. इसके अलावा ग्रेब रेल और सीट में भी बदलाव किया गया है. अलॉय व्हील और रीयर सस्पेंसन पहले वाले मॉडल की तरह ही है, लेकिन साइड इंडिकेटर नए कलर में आए हैं. नई बजाज प्लेटिना 100 ईएस में इंजन भी पहले के मुकाबले ज्यादा पावर वाला दिया गया है. नई बजाज प्लेटिना 100 ईएस की कीमत लगभग 44,507 रुपये रखी गई है. ■

लैपटॉप और पीसी यूजर्स के लिए फ्री एंटी-वायरस

अगर आप अपने कम्प्यूटर को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए इस एंटी–वायरस से प्रोटेक्ट करना चाहिए. इसके लिए कई एंटी–वायरस मौजूद हैं, जो आपके कम्प्यूटर को पूरी सुरक्षा देते हैं, लेकिन इनके दाम हजारों में होते हैं. वहीं, कम्प्यूटर को स्कैन करना भी जरूरी है और पैसे बचाना भी. ऐसे में, हम आपको 6 एंटी वायरस लेकर आए हैं, जिससे आप अपने कम्प्यूटर को फ्री में पूरी सुरक्षा दे सकते हैं. इन्हें इन्स्टॉल और यूज करना भी बेहद आसान है. यह एंटी–वायरस इन्स्टॉल करने में बेहद आसान है. यह आपके कम्प्यूटर के परफॉर्मेंस पर बिना असर डाले पहले स्कैन में ही थ्रेड को पकड़ लेता है और आपको मालवेयर से अपडेट करता रहता है. यह विंडो 8.7, विस्ता और एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है. यह फ्री एंटी–वायरस कमर्शियल एन्वायरनमेंट के लिए नहीं है. अवास्ट एंटी वायरस में कई ऐसे फीचर्स हैं जो यूजर्स के काफी काम आ सकते हैं. इनमें से सॉफ्टवेयर अपडेटर यूजर्स को हमेशा प्रोग्राम को अपडेट करने के बारे में नोटिफाई करता रहेगा. इसके अलावा, ब्राउजर क्लीनअप और ग्रिम फाइटर जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं.

यह फ्री एंटी–वायरस सभी तरह के वायरस अटैक से आपको बचा सकता है. साथ ही, आपके डेटा को भी सुरक्षित रखता है. यह एंटी–वायरस एक टूलबार भी प्रोवाइड करता है, जिसमें एंटी–फिशिंग टूल, ऐड ब्लॉकर और सोशल नेटवर्किंग प्रोटेक्शन किट होती है. वैसे, इसका इंटरफेस समझने में थोड़ा मुश्किल है. अवीरा(avira) ने कुछ समय पहले avira Protection Cloud (PC) बनाया है, जो पीसी को पूरी तरह सिक्योर करता है. यह एंटी–वायरस आपके पीसी को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस को ब्लॉक कर देता है. हैकर्स से पीसी को हाइड करता है. सोशल साइट से होने वाले हार्म को स्कैन करता है. साथ ही, सभी प्रोग्राम्स को मॉनिटर भी करता है. वहीं, इसके फ्री वर्जन में एडवांस रियल टाइम एंटी–वायरस, कस्टमर सपोर्ट, पीसी ट्यून–अप और ब्राउजर प्रोटेक्शन नहीं है.

इस एंटीवायरस की मदद से फाइरवॉल प्रोटेक्शन और कुछ हद तक पीसी प्रोटेक्शन मिल सकती है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर पर पूरी तरह से भरोसा करना शायद ठीक ना हो.

यह एंटी–वायरस अच्छे फीचर्स के साथ आपको मिलता है, जैसे एंटी–वायरस इंजन, ई–मेल स्कैनर, थेफ्ट प्रोटेक्शन और लिंक स्कैनर. ये सभी फीचर्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन सेफ रखते हैं. वीजी ने हाल ही में वीजी ज़ेन टूल AVG Zen Tool रिलीज किया है. कंपनी का दावा है कि यह डेस्कटॉप और मोबाइल, दोनों को वायरस से पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा. कोई भी एंटी–वायरस आपको 100 प्रतिशत प्रोटेक्शन नहीं दे पाता, ऐसे में Emsisoft Emergency Kit परफेक्ट साबित हो सकता है. यह आपके पीसी को पहले से इन्स्टॉल एंटी–वायरस के साथ प्रोटेक्ट करेगा. इस एंटी–वायरस की खास बात है कि इसे पीसी में इन्स्टॉल नहीं करना पड़ता. यह पीसी को डायरेक्ट स्कैन करता है.

मालवेयर हटाने के लिए ये सॉफ्टवेयर डुअल स्कैनर का इस्तेमाल करता है. ये डिवाइस यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स (पेन ड्राइव और बाकी यूएसबी डिवाइसेस) के लिए बेहतर स्कैनिंग सॉफ्टवेयर बन सकता है. ■

एचटीसी ने ऑक्टा कोर फोन लॉन्च किया

एचटीसी ने एक नया और सस्ता स्मार्टफोन 526जी+ पेश किया है जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर से लैस है. यह एंड्रॉयड किटकैट पर आधारित है और डुअल सिम फोन है. इसका स्क्रीन 4.7 इंच का है जो 960 गुणा 540 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. यह एंड्रॉयड किटकैट पर आधारित है. इसका प्रोसेसर 1.7 जीएचजेड ऑक्टा कोर है. इसका रैम 1जीबी है और इसका इंटरनल स्टोरेज माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 8जीबी या 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इसका रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल है और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. इसमे अन्य फीटर 3जी, वाई–फाई, जीपीएस, ब्लूटुथ 4.0 जैसी सुविधा उपलब्ध है. इसकी बैटरी 2000 एमएएच की है. इसकी कीमत 10,400 रुपये(16जीबी), 11,400 रुपये(32जीबी) है. ■

आईबॉल का कई फीचर्स वाला नया फोन

आईबॉल ने नया ऐंडी 5क्यू कोबाल्ट सोलस स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. इस स्लिम और हल्के फोन में ऑक्टा–कोर प्रोसेसर के साथ–साथ कई और अच्छे स्पेसिफिकेशन्स हैं. इसमें 1.4 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा–कोर कॉरटेक्स–7 प्रोसेसर है. इस फोन में 2 जीबी रैम है. यह एक ड्यूल सिम फोन है जिसमें ऐंड्रॉयड 4.4 किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 16 जीबी इंटरनल मेमोरी है जो माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 32 जीबी तक बढ़ायी जा सकती है. इस फोन का डिस्प्ले ओजीसी टच के साथ–साथ 5 इंच की है जो 1280 गुणा 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है. इस स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल ऑटो–फोकस रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है. इसमें ग्लास फिनिश वाला बैक पैनल है जो इसे प्रीमियम लुक देता है. यह प्राइमरी कैमरा लाइव फोटो ऑप्शन, फेस ब्यूटी, पैनोरमा मोड, फेस डिटेक्शन, स्माइल शॉट और वी कैप्चर मोड्स को सपोर्ट करता है. इस फोन की बैटरी 2250 एमएएच की है. इसकी कीमत 11,999 रुपये है. ■

टाटा मोटर्स की नई एसयूवी

टाटा मोटर्स एक ऐसा कॉम्पैक्ट एसयूवी पेश करने जा रही है जो लग्जरी का दूसरा नाम होगा. इसकी छत और इसके व्हील इसके खास आकर्षण होंगे. इसको एक्स104 के नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन कंपनी अभी इसको कोई नाम नहीं दिया है. कंपनी ने इसे स्लीक लुक देने की कोशिश की है ताकि यह सभी को पसंद आए. इसके लिए रियर स्पेस को घटा दिया गया है. एक्स104 दरअसल इवोक के मिनी संस्करण जैसा दिखता है. ध्यान रहे कि इवोक रेंज रोवर का शानदार एसयूवी है जिसे विदेशों में बेचा जाता है और इसका स्वामित्व भी टाटा मोटर्स के पास है. यह एसयूवी उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी जिस पर टाटा की नई कारें बोल्ट और जेस्ट हैं और कुछ चीजें उनसे भी ली गई हैं. इसके व्हील को 17 इंच का बनाया गया है ताकि यह बड़ा दिखे. इस एसयूवी में टाटा का नया 1.5 लीटर डीजल मोटर लगाया जाएगा जिसके बारे में काफी बातें हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि 110 बीएचपी की शक्ति प्रदान करेगा. इसमें छह गियर होंगे ताकि यह ज्यादा पॉवर हैंडल कर सके. कंपनी ने पूरी कोशिश की है कि इसकी माइलेज फोर्ड के एसयूवी ईकोस्पोर्ट से ज्यादा हो. इसमें पेट्रोल इंजन का भी विकल्प होगा. टाटा ने इसके लिए 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी बनाया है. इसे एल्युमिनियम से बनाया गया है और इसलिए यह हल्का है. ■

इसको एक्स104 के नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन कंपनी अभी इसको कोई नाम नहीं दिया है.कंपनी ने इसे स्लीक लुक देने की कोशिश की है ताकि यह सभी को पसंद आए. इसके लिए रियर स्पेस को घटा दिया गया है. एक्स104 दरअसल इवोक के मिनी संस्करण जैसा दिखता है.

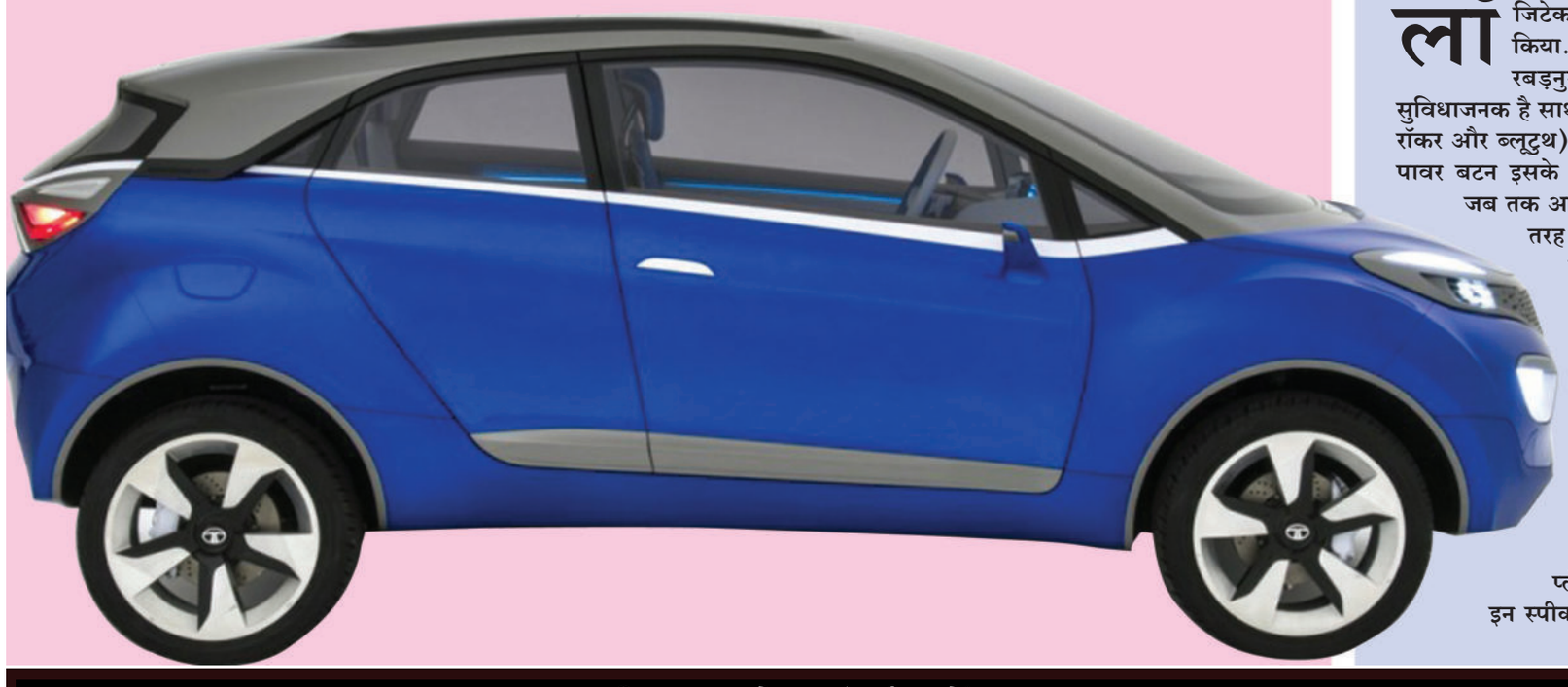

कम कीमत में बेहतर वायरलेस स्पीकर

लॉजिटेक ने हाल ही में एक्स 100 मॉडल के साथ एक्स300 मोबाइल वायरलेस स्पीकर लांच किया. 360 ग्राम के वजन वाले इस डिवाइस का माप 2.7एक्स 5.9एक्स 2.8 इंच है. इसकी रबड़नुमा बॉडी पकड़ने में काफी सुविधाजनक है साथ ही इसमें लगे तीन बटन (वॉल्यूम रॉकर और ब्लूटुथ)ऑपरेट करने में काफी आसान है. पावर बटन इसके पीछे की ओर छुपा हुआ है और जब तक आप इसे प्रेस नहीं करते यह बटन की तरह दिखेगा भी नहीं. इसमें लगा एलइडी इंडीकेटर आपको अलर्ट करता है– जब पेयरिंग हो तो ब्लू ब्लिंक और चार्ज की जरूरत हुई तो रेड ब्लिंक. पावर बटन के पास ही 3.5 मिमी का स्टैंडर्ड पोर्ट के साथ चार्जिंग के लिए माइक्रोयूएसबी पोर्ट लगा है. यदि इसके परफार्मेंस को देखें तो बड़े साइज के रूम या मिनी हॉल के लिए इसकी आवाज काफी अच्छी साबित होगी. चाहे वह टू स्टेप्स टू हेल्स निरो एलबम हो या कोई वायलिन पीस इस डिवाइस के साउंड में किसी तरह का क्रैक या घरघराहट नहीं आएगी. इसका आउटपुट काफी बेहतर है. अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो यह आपको एक सिंगल चार्ज के बाद 5 घंटे तक नॉन स्टॉप प्लेबैक का आनंद मुहैया कराएगा. इसमें 30 फीट का वायरलेस रेंज भी है और बिल्ट इन स्पीकर इनकेस भी यदि आप कॉल्स लेना चाहें. इसकी कीमत 5,995 रपये है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

पेस अब तक 99 पुरुष और 24 महिला खिलाड़ियों के साथ जोड़ियां बना चुके हैं. महेश भूपति अब तक के उनके सबसे सफल साथी रहे हैं. साल 1996 में अटलांटा ओलंपिक में एकल कांस्य पदक जीतना उनके जीवन का सबसे अहम या कहें सर्वश्रेष्ठ पल है. लेकिन उन्होंने अपने हार न मानने वाले जज्बे से पूरी पीढ़ी को अपना कायल बना लिया. पेस अपने 24 साल लंबे प्रोफेशनल टेनिस करियर में कुल 31 बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के फाइनल में पहुंचे, जिसमें से 15 बार वह विजेता बनने में कामयाब हुए, जबकि 16 बार वह उपविजेता रहे. वह मिक्स डबल्स स्पर्धाओं में 15 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं जिसमें 7 बार वह विजयी हुए और 8 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.

उम्र की सीमाओं से परे लिएंडर पेस

पेस नवरातिलोवा के साथ साल 2003-2005 के बीच चार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें से 2003 में विंबल्डन और ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने में यह जोड़ी सफल हुई थी. उसी अनुभव के आधार पर नवरातिलोवा ने हिंगिस को पेस के साथ जोड़ी बनाने की सलाह दी होगी. खिताबी जीत के बाद हिंगिस ने पेस की तारीफ की और कहा कि मार्टीना (नवरातिलोवा), लिएंडर को मुझे देने कि लिए शुक्रिया. मुझे लगता है कि हर मैच के साथ हम मजबूत होते गए. मनोबल, टीम वर्क, एक दूसरे के सुझाव हमारे काम आए. हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं. शायद यही हर मैच में अहम कड़ी थी.

नवीन चौहान

साल 2015 की शुरूआत मेंचेन्नई ओपन के युगल स्पर्धा के फाइनल में हारने के बाद टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने कहा था कि, मैं सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के जज्बे से प्रेरित होता हूं. मैं रोजाना अपने जीवन के हर पहलू में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करने से प्रेरित होता हूं. एक बेटे के रूप में, देशभक्त के रूप में, पिता के रूप में मैं सबसे बेहतर करने की कोशिश करता हूं. मैं इस भावना से आगे बढ़ता हूं कि हर दिन बेहतर हो सकता है, वह भी तब, जब मैं छह महीने बाद 42 साल का होने वाला हूं. मैं अपने खेल में हर दिन सुधार करना चाहता हूं. जीवन में मुश्किल हालात हमेशा मौजूद रहते हैं, ऐसे में अहम यह है कि जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान लगाया जाए. अड़चनें आपके नियंत्रण से बाहर हैं लेकिन आप उसे उनका किस तरह सामना करते हैं यह महत्वपूर्ण है, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप उनका कैसे सामना करते हैं यह मायने रखता है. नाराज़ होने, हताश होने का क्या फायदा, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला. इस तरह की हर बात का जवाब अंत में मेरा रैकेट देता है. इसलिए निराश होने का कोई कारण नहीं है. इस बात को कहे पंद्रह दिन भी नहीं गुजर थे कि लिएंडर पेस ने मार्टीना हिंगिस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीत लिया, और अपनी बात को सही साबित किया.

41 वर्षीय लिएंडर के करियर का यह 15 वां ग्रैंड स्लैम खिताब है. उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतना अद्भुत है. गत 24 सालों से वह टेनिस कोर्ट पर खिताबी जीत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. ढ़ाई दशक बाद भी खेल के प्रति उनके ज़ज्बे में कोई बदलाव नहीं आया है. दिन-ब-दिन उनकी जीत की भूख बढ़ती जा रही है. साल 2013 में यूएस ओपन जीतने के बाद पेस ने कहा था कि उम्र तो महज़ एक आकड़ा है जिस पर मैं सिर्फ मुस्कुराता हूं. मेरा सफर अभी थमा नहीं है. इस बार जीत के उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र का असर न तो उनके खेल पर पड़ा है, न ही जज्बे पर. यह बात इससे साबित होती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन में इन दोनों की जोड़ी एक भी सेट नहीं हारी.

साल 2013 में यूएस ओपन का युगल खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बनने वाले पेस ने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्सड् डबल्स का खिताब जीतकर अपने रिकॉर्ड को और बेहतर कर दिया. पेस-हिंगिस की जोड़ी ने मेलबर्न में खेले गए फाइनल मुक़ाबले में क्रिस्टीना और डेनियल नेस्टर की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से मात दी. 41 वर्षीय लिएंडर केकरियर का यह 15 वां ग्रैंड स्लैम खिताब है. उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतना अद्भुत है. गत 24 सालों से वह टेनिस कोर्ट पर खिताबी जीत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. ढ़ाई दशक बाद भी खेल के प्रति उनके ज़ज्बे में कोई बदलाव नहीं आया है और न ही उनके जीत के जुनून में कमी आई है. दिन-ब-दिन उनकी जीत की भूख बढ़ती जा रही है. साल 2013 में यूएस ओपन जीतने के बाद पेस ने कहा था कि उम्र तो महज़ एक आकड़ा है जिस पर मैं सिर्फ मुस्कुराता हूं. मेरा सफर अभी थमा नहीं है. इस बार जीत के उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र का असर न तो उनके खेल पर पड़ा है, न ही जज्बे पर. यह बात इससे साबित होती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन में इन दोनों की जोड़ी एक भी सेट नहीं हारी. पहले दौर का एक सेट ही टाई ब्रेकर तक गया. इसके बाद दोनों की जोड़ी लगातार आगे बढ़ती गई और खिताब हासिल कर लिया.

पेस ने 1991 पेशेवर टेनिस खेलना शुरू किया था. उस वक्त वह विंबल्डन और यूएस ओपन का जूनियर खिताब जीत चुके थे और जूनियर रैंकिंग में पहले नंबर पर थे.पहले ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा. उन्होंने पेशेवर करियर का पहला ग्रैंडस्लैम खिताब साल 1999 में महेश भूपति के साथ फ्रेंच ओपन के रूप में जीता था. इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. हालांकि, इससे पहले पेस ओलंपिक में एकल कांस्य पदक जीतकर अपनी काबीलियत साबित कर चुके थे. एकल स्पर्धाओं में वह सफल नहीं हुए. इसलिए उन्होंने युगल मुकाबलों की तरफ रुख किया और हम वतन महेश भूपति के साथ युगल स्पर्धाओं में भाग लेना शुरू किया. इन दोनों की जोड़ी बेहद सफल रही. दोनों की जोड़ी को दुनिया भर में इंडियन एक्सप्रेस के नाम जाना जाने लगा. इस जोड़ी ने 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते. इंडियन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने यानी कि दोनों के अलग हो जाने के बाद भी पेस के खेल में बदलाव नहीं आया. वह लगातार जीत हासिल करते रहे. पेस अब तक 99 पुरुष और 24 महिला खिलाड़ियों के साथ जोड़ियां बना चुके हैं. महेश भूपति अब तक के उनके सबसे सफल साथी रहे हैं. साल 1996 में अटलांटा ओलंपिक में एकल कांस्य पदक जीतना उनके जीवन का सबसे अहम या कहें सर्वश्रेष्ठ पल है. लेकिन उन्होंने अपने हार न मानने वाले जज्बे से पूरी पीढ़ी को अपना कायल बना लिया. पेस अपने 24 साल लंबे प्रोफेशनल टेनिस करियर में कुल 31 बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के फाइनल में पहुंचे, जिसमें से 15 बार वह विजेता बनने में कामयाब हुए, जबकि 16 बार वह उपविजेता रहे. वह मिक्स डबल्स स्पर्धाओं में 15 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं जिसमें 7 बार वह विजयी हुए और 8 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. यह पेस का सातवां मिक्स डबल्स और करियर का तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स खिताब है. पेस करियर में तीन बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, तीन बार विंबल्डन और एक बार यूएस ओपन मिक्सड डबल्स खिताब जीत चुके हैं. मिक्स डबल्स खिताब का करियर स्लैम पूरा करने के लिए केवल फ्रेंच ओपन जीतना बाकी है. यदि वह ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो यह उपलब्धि उनके करियर में चार चांद लगा देगी. पुरुष युगल का करियर ग्रैंड स्लैम वह साल 2012 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतकर पूरा कर चुके हैं. उन्होंने करियर में एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, तीन फ्रेंच ओपन, एक विंबल्डन और तीन यूएस ओपन युगल खिताब जीते हैं.

पेस-हिंगिस की जोड़ी को प्रतियोगिता में सातवीं वरीयता दी गई थी. लेकिन यह जोड़ी विजयी बनकर निकली. पेस पिछले कुछ समय से पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन्होंने इसका असर अपने खेल पर पड़ने नहीं दिया. वह कुछ समय खेल के मैदान से दूर रहे लेकिन जब वह कोर्ट पर वापस लौटे तो धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा कर लिया. ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले चेन्नई ओपन में वह दक्षिण अफ्रीका के रावेन क्लासेन के साथ उपविजेता रहे थे. बढ़ती उम्र का असर उनके खेल पर कतई नज़र नहीं आ रहा है.

उम्र के इस पड़ाव पर इस तरह की उपलब्धि केवल शारीरिक सुदृढ़ता केसाथ-साथ मानसिक दृढ़ता भी जरूरी होती है. बढ़ती उम्र के साथ खिलाड़ियों को थका हुआ मान लिया जाता है. लेकिन पेस अपने अनुभव का फायदा उठा रहे हैं. उन्हें 20 साल से टेनिस कोर्ट पर जलवा बिखेर रही हिंगिस का भी बराबर सहयोग मिला. पेस ने अपनी नई पार्टनर मार्टीना हिंगिस की जमकर तारीफ की और कहा कि हिंगिस के साथ खिताब जीतना एक दिलचस्प लम्हा है. मार्टीना के साथ खेलना अद्भुत है. मैं उनके खेल से काफी कुछ सीखने में सफल रहा हूं. हिंगिस पेस की 24 वीं मिक्स डबल्स पार्टनर हैं. मार्टीना हिंगिस ने दो साल पहले दूसरी बार संन्यास से वापसी की थी तब उन्होंने तय किया था कि वह एकल मुकाबले नहीं खेलेंगी. वह सारा ध्यान युगल मुक़ाबलों में लगाएंगी. इसके लिए उन्हें ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो उनका खिताब जीतने में मददगार हो. ऐसे में उन्होंने पेस को अपना पार्टनर चुना. हिंगिस को पार्टनर के रूप में पेस का नाम मार्टीना नवरातिलोवा ने सुझाया था. पेस नवरातिलोवा के साथ साल 2003-2005 के बीच चार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें से 2003 में विंबल्डन और ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने में यह जोड़ी सफल हुई थी. उसी अनुभव के आधार पर नवरातिलोवा ने हिंगिस को पेस के साथ जोड़ी बनाने की सलाह दी होगी. खिताबी जीत के बाद हिंगिस ने पेस की तारीफ की और कहा कि मार्टीना (नवरातिलोवा), लिएंडर को मुझे देने कि लिए शुक्रिया. मुझे लगता है कि हर मैच के साथ हम मजबूत होते गए. मनोबल, टीम वर्क, एक दूसरे के सुझाव हमारे काम आए. हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं. शायद यही हर मैच में अहम कड़ी थी. उनकी बातों से तो यही जाहिर होता है कि पेस को खुद पर जितना भरोसा है उससे ज्यादा भरोसा उनके साथी या प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को है. पेस के साथ पहली बार जोड़ी बनाकर ऑस्ट्रेलिन ओपन के फाइनल में जगह बनाने के बाद हिंगिस ने कहा था कि वह मानती हैं कि उन्हें और पेस को देर से जोड़ी नहीं बनानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि मैंने पेस से कहा था कि हमें 10 साल पहले जोड़ी बना लेनी चाहिए थी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत पाते.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिएंडर पेस भारत के सबसे कामयाब टेनिस खिलाड़ी हैं. वह अपने खेल से देश की झोली उम्र के चालीसवें पड़ाव पर आकर भी भरते जा रहे हैं.पेस भारतीय खेलों की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, उन्होंने दुनिया भर में टेनिस में भारत को पहचान दिलाई. भले ही वह पेशेवर टेनिस के एकल मुक़ाबलों में सफल न हो सके हों, लेकिन युगल मुकाबलों की बदौलत वह भारतीय खिलाड़ियों दर्शकों से विजेता की श्रेणी में ले आए. वह पेशेवर टेनिस के साथ-साथ ओलंपिक, एशियाई खेलों और एटीपी टूर्नामेंट में देश का नेतृत्व बड़ी मेहनत से करते हैं. देश की युवा पीढ़ी आज उनके नक्शे कदम पर चल रही है. इस वजह से देश में टेनिस का भविष्य सुरक्षित नज़र आ रहा है.■

navinchauhan2003@gmail.com

बॉलीवुड ख़बरे

हार्वर्ड में पीके

आमिर खान की फिल्म पीके ने बॉक्स ऑफिस ही नहीं, बल्कि दुनिया में धाक जमा रही है. इस फिल्म ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल हार्वर्ड में भी डंका बजा दिया है. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को पीके पर लेक्चर देने के लिए निमंत्रण भेजा है. आमिर ने हार्वर्ड का न्योता स्वीकार कर लिया है. हालांकि अभी लेक्चर की तारीख सुनिश्चत नहीं हुई है. आमिर हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के साथ पीके में उनके रोल और तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने केवल भारत में 340 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. फिल्म विवाद की वजह से भी सुर्खियों में आई थी.■

विक्की डोनर के लिये पहली पसंद नही थे आयुष्मान खुराना

आयुष्मान ने अपने इन अनुभवों को अपनी किताब क्रैकिंग द कोड में साझा किया है. आयुष्मान ने लिखा है कि इमरान खान और सोनम कपूर की आई हेट लव स्टोरी में जब उन्हें सहायक भूमिका नहीं मिली तो उनका दिल टूट गया था.

आयुष्मान खुराना का कहना है कि सुपरहिट फिल्म विक्की डोनर के लिये वह पहली पसंद नहीं थे. आयुष्मान खुराना ने वर्ष 2012 में प्रर्दशित फिल्म विक्की डोनर से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत की थी. आयुष्मान का कहना है कि वह विक्की डोनर के लिये पहली पसंद नहीं थे और तब वह बॉलीवुड में मौके की तलाश में थे. आयुष्मान ने अपने इन अनुभवों को अपनी किताब क्रैकिंग द कोड में साझा किया है. आयुष्मान ने लिखा है कि इमरान खान और सोनम कपूर की आई हेट लव स्टोरी में जब उन्हें सहायक भूमिका नहीं मिली तो उनका दिल टूट गया था. आयुष्मान ने कहा कि विक्की डोनर के लिये वह पहली पसंद नही थे. आयुष्मान ने कहा विवेक ओबेराय विक्की डोनर को प्रोडयूस करना और उसमें अभिनय करना चाहते थे, उन्हें लगभग साइन भी कर लिया गया था लेकिन किसी वजह से फिल्म के निर्माता रोनी स्क्रूवाला का मन बदल गया. इसके बाद शरमन जोशी को ऑफर दिया गया, लेकिन उनके इंकार के बाद यह फिल्म मुझे मिली थी.■

रणबीर इस दौर के सबसे काबिल अभिनेताः रणधीर कपूर

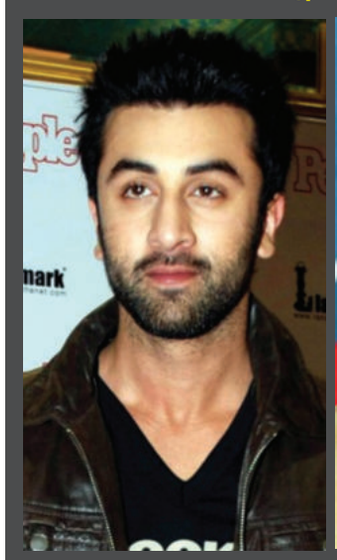

गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता रणधीर कपूर का कहना है कि उनके भतीजे रणबीर कपूर आज के दौर के सबसे काबिल अभिनेता हैं. रणबीर उनके छोटे भाई ऋषि के पुत्र हैं. रणधीर ने कहा कि रणबीर एक काबिल अभिनेता हैं और मौजूदा पीढ़ी के मेरे सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक हैं. उन्होंने कहा कि रणबीर बेहद गंभीर कलाकार हैं, वह अच्छा काम कर रहा है और अच्छी फिल्मों का चयन कर रहा है. रणबीर की हालिया रिलीज हुई फिल्म रॉय है. इस फिल्म में उनके अभिनय की तारीफ हो रही है. इस फिल्म में वह एक अलग लुक में नज़र आए हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

फिर नज़र आएगी शाहरुख–काजोल की जोड़ी

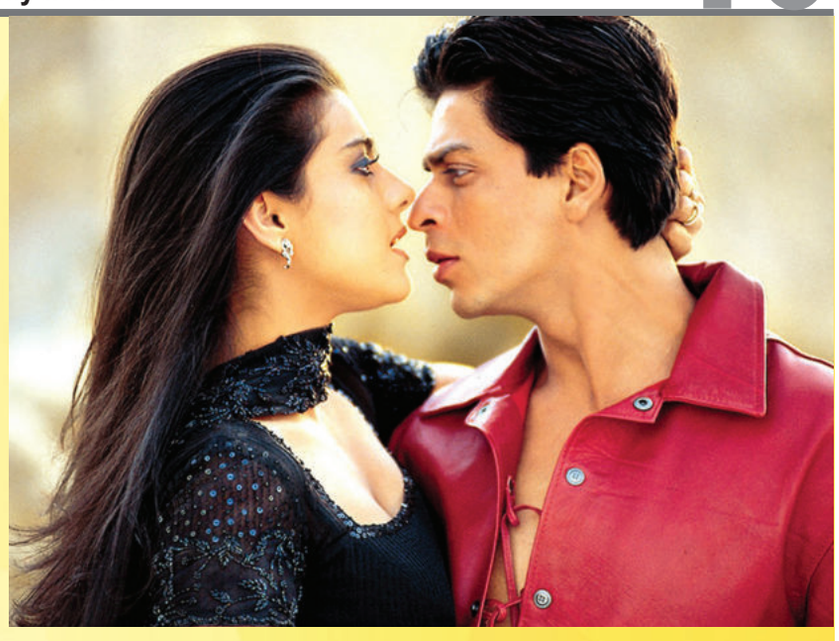

बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में से एक शाहरुख और काजोल की जोड़ी एक बार फिर नज़र आने वाली है. इस बार दोनों एक साथ रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में नज़र आयेंगे. हालांकि रोहित ने इस फिल्म के बारे में चुप्पी साध रखी है. शाहरुख काजोल की जोड़ी अबतक फिल्म बाज़ीगर, करण–अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी, कभी गम जैसी सुपर हिट फिल्मों में नज़र आ चुकी है. शाहरुख–काजोल की जोड़ी बॉलीवुड में सफलता की गारंटी मानी जाती है. रोहित ने इस फिल्म के बारे में अगले महीने खुलासा करने की बात कही है. रोहित ने इन दोनों को फिल्म में लिए जाने के सवाल पर कहा कि इस समय मुझे लगता है कि मुझे छोड़कर सभी लोग मेरी फिल्म के लिए कलाकार चुनने में जुटे हैं और अपनी राय दे रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं और मज़े ले रहा हूं.■

कंगना के घर पहुंचीं रेखा

कंगना को फिल्म क्वीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था.

अभिनेत्री कंगना रानावत उस वक्त हैरान हो गईं, जब रात के तीन बजे किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया. कंगना ने जब दरवाजा खोला तो उनके सामने रेखा खड़ी थीं. उन्हें सामने खड़ा देख कंगना स्तब्ध रह गईं. लेकिन जब रेखा ने उन्हें देर रात घर आने का कारण बताया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. दरअसल रेखा उस वक्त फिल्म फेयर समारोह से लौटीं थीं. उस समारोह में कंगना को फिल्म क्वीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था. कंगना उस समारोह में उपस्थित नहीं थीं, इस वजह से उनकी जगह पुरस्कार लेने स्टेज पर रेखा पहुंचीं. इसके बाद वह ब्लैक लेडी को कंगना को सुपुर्द करने पहुंच गईं. ट्रॉफी लेने के बाद कंगना ने कहा कि पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यह पुरस्कार मिलेगा. इसलिए मैं अवार्ड फंक्शन में नहीं गईं थीं. लेकिन उन्हें घर पर भी यह अवार्ड रेखा जी के हाथों से मिला इस लिए वह बहुत खुश हैं.■

अमृता राव ने शादी रचाई

अभिनेत्री अमृता राव विवाह बंधन में बंध गईं हैं, अमृता ने आरजे अनमोल को अपना जीवन साथी चुना है. अनमोल रेडियो की दुनिया का जाना–माना नाम हैं. फिलहाल वह एक स्पोर्ट्स चैनल के लिए शो करते हैं. अमृता पिछले दो सालों से सिल्वर स्क्रीन पर नज़र नहीं आई हैं. वह आखिरी बार फिल्मों में साल 2013 में फिल्म सत्याग्रह और सिंह साब ग्रेट में नज़र आई थीं. कुछ समय पहले अमृता एक इवेंट में अंगूठी पहने पहुंची थीं, इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि उन्होंने सगाई कर ली है. इस बात को और हवा तब मिल गई जब वह मुंबई के सांताक्रूज स्थित एक नर्सिंग होम में देखी गईं, उस वक्त अनमोल वहां भर्ती थे. इसके बाद उन्होंने मुंबई में एक निजि समारोह में अनमोल से शादी कर ली. अपने रिश्तों को हमेशा मीडिया की नज़रों से दूर रखने वाली अमृता शादी के बाद अनमोल के साथ मुंबई के वकोला स्थित अपने घर में रह रही हैं. यह घर अनमोल के घर के करीब है जहां उनका परिवार रहता है. इससे पहले अमृता वर्सोवा में अपने परिवार के साथ रहतीं थीं. अब अमृता वकोला में ही प्रोफेशनल मीटिंग करती हैं. टीवी शो बेइंतहां में उनकी बहन प्रीतिका राव के आने के बाद अमृता भी छोटे परदे की ओर रुख कर सकती हैं. फिलहाल उनके पास बॉलीवुड में कोई काम नहीं है.■

अपने रिश्तों को हमेशा मीडिया की नज़रों से दूर रखने वाली अमृता शादी के बाद अनमोल के साथ मुंबई के वकोला स्थित अपने घर में रह रही हैं. यह घर अनमोल के घर के करीब है जहां उनका परिवार रहता है.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

16 फरवरी–22 फरवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

शकुनी कराएंगे महाभारत

नीतीश खेमे की ओर से हो रहे हमलों से जीतन राम मांझी को बचाने के लिए जो सबसे पहला और मजबूत घेरा तैयार किया गया है उसमें शकुनी चौधरी, शिवानंद तिवारी, नरेंद्र सिंह, वृषण पटेल, महाचंद्र सिंह और जगन्नाथ मिश्रा शामिल हैं. यही कोर टीम है जो सीएम पर हो रहे हमलों से बचाव और आगे की रणनीति की दिशा और दशा तय कर रही है. सीएम उनके करीबी संपर्क में रहते हैं और समय-समय पर उनसे उपयोगी परामर्श भी करते हैं. सीएम की राजनीतिक सुरक्षा के दूसरे घेरे में ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, राहुल शर्मा, अजीत सिंह के अलावा अन्य वैसे मंत्री और विधायक हैं जो नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से बेहद नाराज हैं.

सरोज सिंह

सूबे बिहार में इस साल होने वाले चुनावी महाभारत के लिए रणभूमि को सजाने का काम शुरू हो गया है. महाभारत के इस युद्ध में कौन सा योद्धा किधर होगा और किसकी क्या भूमिका होगी, अभी तो इससे पर्दा उठना बाकी है पर सूबे के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस बार के यद्ध में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की भूमिका काफी अहम होगी. युद्ध में हार और जीत को तय करने में जीतनराम मांझी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं. अब इस लड़ाई में कौन धर्म के मार्ग पर होगा और कौन अधर्म के, राजनीति में और खासकर चुनावी राजनीति में इसका निर्धारण करना बेहद मुश्किल है. जो जीतेगा वही धर्म के मार्ग पर कहलाएगा चाहे उस खेमे की व्यूह रचना शकुनी ने ही क्यों न की हो. इसलिए इतिहास को गवाह बनाकर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले बिहार के रोज बदल रहे सियासी समीकरण को बारीकी से समझना जरूरी है. यह समझना जरूरी है कि बयानों के जो तीर धुंआधार चल रहे हैं, उन्हें असली में चलाने वाला कौन है और उसे किस लक्ष्य को भेदना है. यह भी समझना जरूरी है कि बिहार के चुनावी महाभारत के लिए जो ताना-बाना बुना जा रहा है, उसके असली सूत्रधार कौन हैं और उनकी मंशा क्या है? ऐसे सवालों का जवाब तो तभी मिलेगा जब बिहार का चुनावी महाभारत खत्म हो जाएगा पर आइए इससे पहले कि यह युद्ध शुरू हो इसकी तैयारियों की गंभीरता को समझने की कोशिश करते हैं.

अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि सूबे बिहार में महाभारत की शुरुआत तो सबसे पहले जदयू से ही शुरू होने वाली है. चंद रोज़ पहले जदयू के बड़े नेताओं के बीच मनभेद और मतभेद की जो बात सूत्रों के हवाले से कही जाती थी आज वही बात जदयू के बड़े नेता और मंत्री कैमरे के सामने कह रहे हैं. कैबिनेट की बैठक में रगड़ा हो रहा है. कुछ मंत्रियों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है तो कुछ मंत्री जीतन राम मांझी को हटाने पर आमादा हैं. ललन सिंह और पी के शाही जैसे मंत्री अफसरों के तबादले पर मुख्यमंत्री से कैफियत पूछ रहे हैं. मुख्यसचिव को पत्र लिखकर जानकारी मांग रहे हैं.

जदयू प्रवक्ता नीरज सिंह मुख्यमंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें किनके घर जाना चाहिए और किनके घर नहीं जाना चाहिए. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों को समझाने और उन्हें मनाने की पहल करनी चाहिए. साफ है कि नीतीश समर्थक जीतन राम मांझी को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं. मतलब यह कि अपनी तरफ से उन्होंने युद्ध का आग़ाज़ कर दिया है. लेकिन जीतन राम मांझी कहां मानने वाले हैं. सीएम के समर्थक मंत्री और नेता उनकी ढाल बनकर आगे आ गए हैं. वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी कहते हैं कि इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है. जो लोग इतिहास से अज्ञान हैं वही लोग बचकाना बयान देते हैं. शकुनी चौधरी कहते हैं कि यह साल ही महाभारत का है और शकुनी को छोड़कर महाभारत कौन करा सकता है. शकुनी चौधरी अपनी राजनीतिक लाइन साफ करते हुए कहते हैं कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया और लालू प्रसाद ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया इसलिए मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार केवल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को ही है. इसलिए छोट-मोटे नेताओं के बयानों को बहुत

गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. रही बात आगे की राजनीति की तो नीतीश कुमार को भी पता है कि उन्होंने खुद गांडीव जीतन राम मांझी के हाथों में सौंपा है इसलिए उन्हें बिहार में होने वाले चुनावी महाभारत में जीतन राम मांझी के सारथी की भूमिका निभानी चाहिए और लालू प्रसाद को उनके ध्वज पर विराजमान होना चाहिए. यही आदर्श स्थिति है और चुनावी महाभारत जीतने का मूलमंत्र है. अगर युद्ध के मैदान में तस्वीर इससे रत्ती भर भी अलग दिखाई पड़ी तो पराजय को तय मानिए. इतिहास के पन्नों को पलटते हुए शकुनी चौधरी कहते हैं कि बिहार में लगभग पचास सालों तक अगड़ी जातियों के नेताओं ने राज किया. इसके बाद लगभग पच्चीस सालों तक लालू और नीतीश कुमार के रूप में पिछड़ी जाति के नेताओं ने राज किया. अब एक महादलित के हाथ में कमान आई है तो पता नहीं कुछ नेताओं के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे कम से कम पांच साल तक जीतन राम मांझी को मौका दीजिए ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति को कुछ राहत मिल सके. शकुनी चौधरी के अनुसार हर नेता यह नारा देता है कि अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति को आगे लाना है और जब अब यह मौका आया तो लोग जीतन राम मांझी के पैर खींचने में लग गए हैं. शकुनी चौधरी कहते हैं कि भाजपा एक बड़ी ताकत के तौर पर बिहार में उभर रही है इसलिए अगर नरेंद्र मोदी का विजय रथ बिहार में रोकना है तो सभी को जीतन राम मांझी के हाथों को मजबूत करना चाहिए. काबिलेगौर बात यह है कि जीतन राम मांझी के पक्ष में तीर चलाने वाले योद्धाओं में शकुनी चौधरी अकेले वीर नहीं हैं. जैसे-जैसे मांझी मजबूत हो रहे हैं इनके गांडीव के पीछे वीरों की एक लंबी कतार दिखाई पड़ने लगी है.

मंत्री नरेंद्र सिंह और वृषण पटेल जीतन राम मांझी के लिए खुलकर तीर चला रहे हैं. नरेंद्र सिंह कहते हैं कि सीएम को हटाने या कमजोर करने से गलत संदेश जाएगा और इसका नुकसान पार्टी को चुनाव में हो सकता है. जानकार सूत्र बताते हैं कि नीतीश खेमे की ओर से हो रहे हमले से जीतन राम मांझी को बचाने के लिए जो सबसे पहला और मजबूत घेरा तैयार किया गया है उसमें शकुनी चौधरी, शिवानंद तिवारी, नरेंद्र सिंह, वृषण पटेल और जगन्नाथ मिश्रा शामिल हैं. यही कोर टीम है जो सीएम पर हो रहे हमले से बचाव और आगे की रणनीति की दिशा और दशा तय कर रही है. सीएम से उनके करीबी संपर्क में रहते हैं और समय-समय पर उनसे उपयोगी परामर्श भी करते हैं. सीएम की राजनीतिक सुरक्षा के दूसरे घेरे में ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, राहुल शर्मा, अजीत सिंह के अलावा अन्य वैसे मंत्री और विधायक हैं जो नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से बेहद नाराज हैं. सूत्रों पर भरोसा करें तो यह कहा जा सकता है कि अगर कुछ मंत्रियों ने जीतन राम मांझी को कटघरे में खड़ा करने का काम बंद नहीं किया जो उन्हें मंत्रिपरिषद से बर्खास्त भी किया जा सकता है. इसमें ललन सिंह, पी के शाही और श्रवण कुमार का नाम सबसे पहली पायदान पर है. शकुनी चौधरी बिहार के चुनावी महाभारत की जो व्यूहरचना रच रहे हैं उसमें जीतन राम मांझी को कई राजनीतिक हथियारों से लैश किया जा रहा है. महाभारत के शंखनाद के पहले जीतन राम मांझी को इतना मजबूत कर देने की कोशिश है कि वह जिधर भी रहें जीत उधर ही हो. पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने जैसे हथियार भी इस युद्ध में आजमाए जा सकते हैं.शकुनी चौधरी कहते हैं कि उनका नाम ही जीतन राम मांझी है मतलब जिधर रहेंगे जीत उसी की होगी.

इधर नीतीश खेमा भी जवाबी कार्रवाई में जुट गया है. जीतन राम मांझी की काट क्या हो इस पर मंथन जारी है. पटना में होने वाले राजनीतिक सम्मेलन में ताकत दिखाने की तैयारी जोर-शोर से जारी है. नीतीश कुमार खुद इस सम्मेलन की तैयारी में दिलचस्पी ले रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अब शकुनी चौधरी की सलाह पर सारथी की भूमिका में रहते हैं या फिर खुद गांडीव उठाकर महाभारत की लड़ाई में कूदेंगे.■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

गुमरा रोड स्थित आचार्य श्री सुदर्शन लायंस सेंट्रल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया. लायंस क्लब सीतामढ़ी प्रियदर्शिनी एवं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की स्थानीय शाखा के तत्वावधान में आयोजित शिविर का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष इंदुप्रभा देवी व सीएस डॉ. एके गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया. शिविर में अनंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़ौदा से आये डॉ. कौशल भानुशाली द्वारा असाध्य रोगों समेत शरीर का अन्य जांच मात्र 999 रुपये में किया गया. कार्यक्रम में डॉ. रेणु चटर्जी, शानू शिल्पी, चंदन सिंह, पॉली चौधरी, डॉ. विभा ठाकुर, विजय सर्राफ, बीके वंदना बहन, महिमा बहन, इंद्रेष भाई, शिव स्नेही भाई, रवींद्र भाई व महेश भाई समेत अन्य थे. संचालन डॉ. राज कुमार गुप्ता ने की.

– बिम्मी कुमारी

घायल मुखिया से की मुलाकात

जदयू नेता सह राज्यसभा सांसद डॉ. आरसीपी सिंह ने सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा के घायल मुखिया संजय कुमार से एक निजी क्लीनिक में मुलाकात की. संजय को अपराधियों ने 13 जनवरी को अहले सुबह गोली मार कर घायल कर दिया था. शहर स्थित डॉ. वरुण के क्लीनिक में मुखिया से मुलाकात के बाद जदयू नेता ने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया. मौके पर जदयू नेता नागेंद्र प्रसाद सिंह, राणा रंधीर सिंह चौहान, राजेश चौधरी, किरण गुप्ता, आरती प्रधान, प्रो. अमर सिंह, सुंदेर पटेल व नवल किशोर समेत दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे.

– विकास कुमार

मिस बिहार नेहा का सम्मान

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के गाढ़ा गांव की बेटी नेहा सिंह मिस बिहार चुनी गयी है. गांव के विद्या सागर एकेडमी में आयोजित एक समारोह में स्थानीय जदयू विधायक गुड्डी देवी ने नेहा को शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया. स्कूल के 22 वें वार्षिकोत्सव समारोह का उद्घाटन विधायक गुड्डी देवी, जदयू नेता राजेश चौधरी व प्राचार्य शैलेश कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. कार्यक्रम के मौके पर मिस बिहार नेहा ने गणेश वंदना व नृत्य प्रस्तुत कर लोगों की वाह वाही बटोरी. प्राचार्य ने स्कूल प्रबंधन की ओर से मिस बिहार को एक टैबलेट कंप्यूटर व 31 हजार नगद देकर सम्मानित किया. मौके पर मुखिया कुमारी किरण देवी, सुधीर झा, शशि शेखर सिंह, मनोज कुमार, अमर कुमार, राम प्रवेश महतो, राजू ठाकुर, सुनील किशोर झा, अरुण सिंह व मुखिया पति युगल किशोर समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे.

– विभा सिन्हा

महानिर्वाण महोत्सव का समापन

इलाहाबाद में माघ मेला के धर्मसम्राट करपात्री जी महाराज के 33वें महानिर्वाण महोत्सव का समापन समारोह मनाया गया. इस समापन समारोह की अध्यक्षता हरिराम महाविद्यालय प्रयाग के प्राचार्य राम कृष्ण त्रिपाठी जी ने की. वहीं संचालन सरकेश्वर चेतन जी ने की. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री करपात्री धाम,वाराणसी के ब्रह्मचारी अभिषेक जी महाराज, स्वामी सहजानंद सरस्वती सामाजिक न्याय मंच के अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह, अमित राय उर्फ गांधी जी, गीता प्रेस के ट्रस्टी राधेश्याम खेमका, अतुल मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा, व्यास नंदन व्यास, देव स्वरूप, डॉ. गिरीश दत्त पांडे, एवं कृष्ण कुमार खेमका ने समारोह को संबोधित किया. इस अवसर पर ब्रह्मचारी अभिषेक जी महाराज ने कहा कि धर्मसम्राट करपात्री जी महाराज धर्मपुरुष थे. वहीं स्वामी सहजानंद सरस्वती सामाजिक न्याय मंच के अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने कहा कि भारत सरकार धर्मसम्राट के नाम पर एक्सप्रेस ट्रेन चलाये एवं वेद शोध संस्थान का गठन करना चाहिए.

– भारती

सामाजिक चेतना कार्यक्रम आयोजित

पूर्वी चम्पारण जिले के उत्तर माध्यमिक विद्यालय कुण्डवाचैनपुर के प्रांगण में एसएसबी द्वारा सामाजिक चेतना अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर एसएसबी के कमांडेंट, एस.पी. सिंह ने एसएसबी के जवानों द्वारा भारत–नेपाल सीमा पर किये जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिवहर सांसद रमा देवी एवं ढाका विधायक पवन जायसवाल ने भी एसएसबी जवानों के द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक चेतना अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा की. मौके पर निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया तथा विकलांगों के बीच ट्राईसाइकिल बांटी गयी. शिविर में चिकित्सक डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. निशिकांत ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें संबंधित रोग की दवाइयां दी. कार्यक्रम में सिकरहना एसडीओ स्वप्निल, प्रमुख विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, अंचल निरीक्षक अवध किशोर झा, कमांडेंट आर.के. सिंह, सहायक सेना नायक वी.के. राय, सब इंस्पेक्टर मुकेश दरवल, सी.के. पटेल, थानाध्यक्ष पंकज कुमार, प्रधानाध्यापक नजमुल होदा, हेमेन्द्र सिंह, जिला पार्षद सुरेन्द्र प्रसाद, भाजपा नेता वसीम आलम, डॉ. सुनिल कुमार सिन्हा, पप्पू चौधरी, रामनाथ सिंह, हरिशंकर साह, अरुण कुमार पाण्डेय, शिवमंगल मिश्रा, सत्यदेव प्रसाद आदि उपस्थित थे.

– इन्तेजारुल हक

गया

बिहार विधान सभा चुनाव

बोधगया सीट पर भाजपा-लोजपा में होगा टकराव

बिहार में भाजपा के साथ लोजपा और रालोसपा का गठबंधन होने के नाते अधिकांश नेताओं की चाहत पर पानी फिर सकता है. क्योंकि तकनीकी समस्या यह है कि कई विधान सभा क्षेत्रों में भाजपा व लोजपा नेता की चाहत टिकट लेने की है.

सुनील सौरभ

बिहार विधान सभा चुनाव का वर्ष 2015 आते ही बिहार में चुनावी राजनीति का रंग हर किसी नेता पर पड़ने लगा है. बिहार में भाजपा का गठबंधन लोजपा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से है. स्वाभाविक है राजनीतिक दल होने के नाते लोजपा और रालोसपा का भी हर जिले में अपना संगठन है. संगठन से जुड़े नेताओं की चाहत होती है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी टिकट लेकर बिहार बिधानसभा की दहलीज पर पहुंच जायें. लेकिन गठबंधन की राजनीति में शीर्ष नेताओं को छोड़कर दूसरे व तीसरे दर्जे के दलीय कार्यक्रताओं तथा नेताओं को टिकट की गारंटी बड़ी मुश्किल होती है. बिहार में भाजपा के साथ लोजपा और रालोसपा का गठबंधन होने के नाते अधिकांश ऐसे नेताओं की चाहत पर पानी फिर सकता है. क्योंकि तकनीकी समस्या यह है कि कई विधान सभा क्षेत्रों में भाजपा व लोजपा नेता की चाहत टिकट लेने की है.

कहीं पर तो भाजपा के विधायक है, वहां से लोजपा की मजबूत दावेदारी की जा रही है. ऐसा ही है बोधगया सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र. यहां से फिलहाल भाजपा के श्याम देव पासवान विधायक है. राजद से अपनी राजनीति शुरू कर वे पिछले दो विधान सभा चुनावों से भाजपा से विधायक हैं लेकिन भाजपा के गया जिले के कुछ नेताओं ने अपने नाम को नहीं छापने की शर्त पर कहा कि श्यामदेव पासवान भाजपा की राजनीति में आज भी अलग–थलग रहते हैं. इनकी मानसिकता आज भी राजद वाली है. हालांकि श्यामदेव पासवान समर्थक इस आरोप को गलत बताते हैं. ऐसे मे पूर्व सांसद स्व. राजेश कुमार के पुत्र लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक कुमार सर्वजीत ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि गठबंधन के तहत बोधगया से उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं.इस घोषणा का खास महत्व इसलिए है कि कुमार सर्वजीत ने यह बात लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान की उपस्थिति में कहीं. 27 जनवरी 2015 को पूर्व सांसद स्व राजेश कुमार की दसवीं पुण्य तिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व जन वितरण मंत्री व लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम विलास पासवान , केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री रामकृपाल यादव, औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, पूर्व मंत्री व गया शहर के विधायक डॉ. प्रेम कुमार, रालोसपा के विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह, टिकारी के विधायक अनिल कुमार समेत अनेक पूर्व विधायक की उपस्थिति में कुमार सर्वजीत ने कहा कि मेरे पिता जी स्व. राजेश कुमार 1977 से बोधगया से राजनीति की शुरुआत कर विधायक व गया के सांसद बने. लेकिन 2005 के चुनाव में वे इमामगंज से विधान सभा चुनाव लड़ रहे थे कि उनकी हत्या कर दी गयी. ऐसे मे गया जिले के अन्य किसी भी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा. इसलिए मुझे बोधगया से ही विधान सभा चुनाव लड़ने का आशीर्वाद दें. चूंकि बोधगया, सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र से भाजपा के कब्जे में है. इसलिए राम विलास पासवान ने भी कुमार सर्वजीत को बोधगया से टिकट दिलाने का जिम्मा पाटलीपुत्र के भाजपा सांसद और केन्द्रीय पेयजल व स्वच्छता राज्यमंत्री रामकृपाल यादव, औरगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह तथा गया शहर के विद्यायक पूर्व मंत्री डॉ. प्रेम कुमार को दिया.

इस मामले पर सभी नेताओं ने कहा कि कुमार सर्वजीत को सहयोग मिलना चाहिए. अब सवाल है कि भाजपा अपनी बोधगया सीट लोजपा के लिए छोड़ेगी? या फिर बगल के बाराचट्टी विधान सभा सुरक्षित सीट से लोजपा–भाजपा की अदला–बदली होगी? या फिर लोजपा बोधगया सुरक्षित सीट के लिए भाजपा से टकराव करेगी ? यह सभी सवाल फिलहाल अटकलों वाली है. बिहार विधान सभा चुनाव की घोषणा के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पायेगा. लेकिन इतना तय है कि पूर्व सांसद स्व. राजेश कुमार के पुत्र पूर्व विधायक व लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव कुमार सर्वजीत बोधगया सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र से ही चुनाव में अपनी किस्मत आजमा कर लोगों की सेवा करने को कटिबद्ध हैं.■

दस साल में नहीं हो सकी पूर्व सांसद के हत्यारों की खोज

27 जनवरी 2015 को बोधगया मे राजेश कुमार की दसवीं पुण्य तिथि पर अयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय जल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्या राजनीतिक साजिश के तहत हुई थी और हत्या के साजिश कर्ता की पहुंच और पकड़ बिहार सरकार तक है. ऐसे में वर्तमान सरकार से सीबीआई जांच की मांग बेईमानी है. क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा नही कर सकती है. अभी हत्यारे सता के संरक्षण में हैं.

सुनील सौरभ

अस्सी के दशक की शुरुआत से जब राजनीति का अपराधीकरण होने लगा तब गौतमबुद्ध की ज्ञानभूमि, भगवान महावीर की जन्म और कर्मस्थली , सम्राट अशोक की भूमि तथा गांधी –जे0पी0 की कर्म भूमि बिहार की राजनीति अजीबोगरीब स्थिति में हो गयी. 1972 में समस्तीपुर में तत्कालीन रेल मंत्री ललित नरायाण मिश्र की हत्या ने बिहार की राजनीति को गलत ट्रैक पर जाने का अभास लोगों को करा दिया. तबसे अबतक बिहार में दर्जनों बड़े नेताओं तथा सैकड़ों राजनीतिक कार्यक्रताओं की हत्याएं हो चुकी है. कुछ मामले मे कोर्ट के फैसले आ चुके तो कुछ का अनुसंधान कार्य ही पूरा नहीं हो सका. ऐसे ही राजनीतिक साजिश के तहत गया के पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्या के दस साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनके हत्यारों की खोज आज तक पूरी नही हो सकी है. 22 जनवरी 2005 की रात गया जिले के डुमरिया प्रखण्ड के मैगरा बाजार में राजेश कुमार की तब हत्या कर दी गयी थी, जब वह चुनाव प्रचार से वापस लौट रहे थे. इसमें इनके तीन सहयोगी भी मारे गये थे. राजेश कुमार इमामगंज विधान सभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी थे. पूर्व सांसद के इस मर्डर केस (डुमरिया थाना कांड संख्या .01/05) में पिछले दस वर्षो के दौरान दर्जन भर से अधिक अनुसंधान अधिकारी (आईओं) बदले जा चुके हैं, लेकिन इस हत्या कांड की जांच पूरी नही हो सकी है. घटना के समय इस हत्या कांड के अनुसंधान का जिम्मा डुमरिया थाना के तत्कालीन थानेदार रविन्द्र राम को सौंपा गया था, उनके स्थानान्तरण के बाद इस मामले का अनुसंधान नये थानेदार को मिला. इस प्रकार थानेदार के बदलने के साथ अनुसंधान अधिकारी भी बदलते रहें, आज फिलहाल इस मामले के अनुसंधान का जिम्मा वर्तमान थानेदार ओमप्रकाश के जिम्में में है. दस वर्ष गुजर जाने के बाद भी इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का अनुसंधान पूरा नहीं हो सका.

पुलिस का मानना है कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवाद से जुड़े नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया था. लेकिन पूर्व सांसद स्व. राजेश कुमार के पुत्र और पूर्व विधायक कुमार सर्वजीत का कहना है कि यह हत्या राजनीतिक कारणों से की गयी थी. राजनीतिक हत्या के खुलासे के लिए वर्ष 2005 मे ही बिहार के 29 विधायकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने राज्य के तत्कालीन राज्यपाल से इस हत्या कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी. इसके बाद संप्रग की केन्द्र सरकार के तीन–तीन गृह मंत्रियों से भी यह मांग की गई, मगर राज्य सरकार ने इस मामले की सीवीआई जांच नही करायी. पटना उच्चन्यायलय ने भी वर्ष 2008 मे इस मामले की जांच में तेजी लाने का आदेश दिया था, मगर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना की. तत्कालीन डीआईजी (मगध प्रक्षेत्र) अरविंद पाण्डेय तथा उनके बाद गया के तत्कालीन एसपी परेश सक्सेना ने इस कांड मे दिलचस्पी ली थी. परेश सक्सेना ने तो स्वयं इस कांड की सुपरविजन रिपोर्ट जारी कर दी थी. लेकिन इसके बाद ही उनका तबादला हो गया. डीआईजी अरविंद पाण्डेय का भी तबादला इस मामले में दिलचस्पी लेने के कारण हो गया था. लेकिन पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्या के दस वर्ष बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक बयान ने कई के होश बिगाड़ दिये हैं. 27 जनवरी 2015 को बोधगया मे राजेश कुमार की दसवीं पुण्य तिथि पर अयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय जल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्या राजनीतिक साजिश के तहत हुई थी और हत्या के साजिश कर्ता की पहुंच और पकड़ बिहार सरकार तक है. ऐसे में वर्तमान सरकार से सीवीआई जांच की मांग बेईमानी है. क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार सीवीआई जांच की अनुशंसा नही कर सकती है. अभी हत्यारे सता के संरक्षण में हैं. लेकिन जल्द ही बिहार में सरकार बदलेगी, सीबीआई जांच होगी और हत्यारों पर कानूनी शिकंजा कसेगा. इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति मे खलबली मच गयी है. पूर्व सांसद के शहादत दिवस कार्यक्रम में लोजपा सुप्रीमो और केन्द्रीय खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, सांसद सुशील कुमार सिंह, सांसद छेदी पासवान, पूर्व मंत्री व विधायक डॉ. प्रेम कुमार, जदयू के बागी विधायक डॉ अनिल कुमार , विधान पार्षद डॉ. संजीव श्याम सिंह, पूर्व विधायक अवधेश कुमार सिंह, सुरेश पासवान, डॉ. बिनोद कुमार यादवेन्दु, रामस्वरुप पासवान शामिल थे और अधिकांश नेताओं ने राजेश कुमार की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की.■

feedback@chauthiduniya.com

महिला नेता

हम किसी से कम नहीं

राधिका

जया मिश्रा

नीलम सिंह

परवीन अमानुल्लाह

सुषमा साहू

भाजपा की नेता सुषमा साहू ने भी अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया है. अगर बात इनके निजी जीवन की की जाए तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है. अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लेडीज वार्ड की पार्षद के रूप में की थी. और जब तक ये पार्षद रहीं तब तक लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी रहीं. जब वॉर्ड पार्षद का दोबारा चुनाव हुआ तो इनके खिलाफ लॉबी बनाई गई जिसकी वजह से इन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद सुष्मा साहु ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और युवा मोर्चा की सेक्रेटरी बनीं.

विश्व के समस्त और यथेष्ठ विकास के लिए महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जुड़ा रहना परम आवश्यक होता है. नारी की स्थिति समाज में जितनी महत्वपूर्ण, सुदृढ़, सम्मानजनक और सक्रिय होगी उतना हीं समाज उन्नत समृद्ध और मजबूत होगा. इस क्रम में बिहार की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है. बिहार की महिलाएं जनकल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं. और इस दिशा में महिलाएं काम करती हुईं भी दिखी हैं. वर्तमान में कई ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीतिक रूप से जन कल्याण कर रही हैं. हर कोई अपने आप में हीं एक मिसाल साबित हुईं हैं. कुछ ऐसी ही महिलाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया है.

वैसे तो पटना में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने खुद अपने दम पर एक उंचाई हासिल की है. इसी दौर में पहला नाम बिहार प्रदेश कांग्रेस की महासचिव जया मिश्रा का है. वो बिहार की बड़ी महिला नेताओं में से एक हैं. उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया है वो अपने दम पर और अपने कठिन परिश्रम से किया है. देखा जाए तो उनकी कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है. इसके बावजूद भी इन्होंने अपने अथक प्रयास और मेहनत से सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है. इनके राजनितिक करियर की शुरुआत जेएनयू की स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुई थी. फिर वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता बनी. और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आज बिहार प्रदेश कांग्रेस की महासचिव हैं. इतना हीं नहीं, इन सब के अलावा इनका रुझान समाज सेवा में भी है. ये महिलाओं की प्रगति के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने का जज्बा रखती हैं. और इसी वजह से ये एक महिला उद्योग संघ से भी जुड़ी हुईं हैं. इसके साथ–साथ बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन की सलाहकार हैं जो पूरे बिहार में बच्चों को मुफ्त में ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देते हैं. राजनीति के साथ– साथ इनकी पढ़ाई में भी काफी रुची रही है.

इसी क्रम में दूसरा नाम लोजपा की नीलम सिंह का है. अपनी मेहनत और लगन के चलते आज इनका नाम बिहार की बड़ी महिला नेताओं में लिया जाता है. इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनता दल यूनाइटेड से की, जहां इन्हें मुजफ्फरपुर महिला सेल का जिला अध्यक्ष बनाया गया. इसी दौरान जब रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा का गठन हुआ, तब नीलम सिंह जेडीयू छोड़ लोजपा से जुड़ गईं. और साथ हीं लोजपा की युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हुईं. 2 नवंबर 2014 को नीलम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत किया गया. इन सब के अलावा इन्हें काफी साहित्यिक पुरस्कार भी मिले हैं. और साथ हीं इनका समाज सेवा में भी बड़ा योगदान रहता है.

इसके अलावा इन दौर में तीसरा नाम आप की बड़ी नेता परवीन अमानुल्लाह का भी है. इन्होंने हमेशा से जनसेवा के लिए अतिरिक्त कोशिशे की हैं और कैबिनेट मंत्री बनने वाली देश की पहली आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं. भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सैयद शाहबुद्दीन की बेटी परवीन अमानुल्लाह ने मिरांडा हाउस दिल्ली से बॉटनी की पढ़ाई की है. इनकी शादी आईएस अधिकारी अफ़ज़ल अमानुल्लाह से हुई है. अपनी जिंदगी में रोजमर्रा की दिक्कतों का इन्होंने कोई खास सामना नहीं किया था. लेकिन फिर भी परवीन अमानुल्लाह का सामाजिक कार्यो के प्रति विशेष रुझान हमेशा से बना रहा और वे लोगों के बीच काम करती रहीं.वो शुरू से ही जुझारू रुझान की रहीं हैं. नीतीश कुमार द्वारा उन्हें जेडीयू में शामिल करने और विधान सभा चुनाव में साहेबपुर कमाल से चुनाव लड़वाने से पहले तक वो राजनितिक पाले की दूसरी ओर हुआ करती थीं, विपक्ष के किसी नेता के रूप में नहीं बल्कि ज़बरदस्त आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में.

इन नामों में एक नाम जेडीयू विधायक रजिया खातून का भी है. ये तब राजनीति में आई जब इनके पति ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था. हालांकि 2005 में हुए चुनाव में रजिया खातून 900 वोटों से हार गई थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल 2010 के नवंबर के चुनाव में जीत भी गईं. इसके अलावा इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कई प्रशंसनीय काम भी किए हैं.

भाजपा की नेता सुषमा साहू ने भी अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया है. अगर बात इनके निजी जीवन की की जाए तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है. अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लेडीज वार्ड की पार्षद के रूप में की थी. और जब तक ये पार्षद रहीं तब तक लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी रहीं. जब वॉर्ड पार्षद का चुनाव हुआ तो इनके खिलाफ लॉबी बनाई गई जिसकी वजह से इन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद सुष्मा साहु ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और युवा मोर्चा की सेक्रेटरी बनीं. फिर सेक्रेटरी से इन्हें युवा मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया. ये बीजेपी युवा मोर्चा के लिए काम करने वाली पहली महिला नेता रहीं. फिर इन्होने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा. और आज ये भाजपा महिला मोर्चा की अधयक्ष है और साथ हीं पूरे बिहार की जेनेरल सेक्रेटरी भी हैं. तो ये हैं बिहार की कुछ ऐसी महिला नेता जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा था जिसकी वजह से आज ये जिंदगी के एक ऊंचें मुकाम पर खड़ी हैं. जहां इन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और इज्जत भी करते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

अन्य ख़बरें

सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

गोगरी अनमंडल क्षेत्र के संत मेरिस इंग्लिश स्कूल श्रीरामपुर ठुट्डी में पांचवे वार्षिकोत्सव के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान छात्र व छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया. बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पेश कर लोगों का दिल जीत लिया. वहीं फिल्मी गीतों पर भी जमकर डांस कर लोगों को मुग्ध कर दिया. कार्यक्रम को सफल बनाने में सिंधु, राजेश बाबू, लीजी सौम्या, सालू, प्रमोद कुमार, मंटू, सुमन, अविनाश, बेनू, सोनू, राजेश आदि लगे रहे. उत्कृष्ट प्रतिभागियों को आगत अतिथिओं के माध्यम से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन डीईओ डॉ. ब्रजकिशोर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस मौके पर उपस्थित डीपीओ अनील कुमार सिंह, एसडीपीओ संजय कुमार झा, बीडीओ डॉ. कुन्दन कुमार, बीइओ अखिलेश कुमार यादव, सीओ शैलेन्द्र कुमार, मुखिया अवध किशोर यादव, मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार चौधरी, कांग्रेस नेता मदन मोहन चौधरी, इज्जवल कुमार, पियुश हजारी सहित अन्य लोगों ने विद्यालय के व्यवस्था की प्रशंसा की. विद्यालय के प्राचार्य जाय जोसेफ और डायरेक्टर बीजू मैथ्यू ने आगत अतिथियों का स्वागत किया.

जदयू व्यक्ति विषेष पार्टी

टाउन हॉल खगड़िया में रालोसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केन्द्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू व्यक्ति विशेष की पार्टी बन कर रह गई है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पिछड़े हुए राज्यों को शिक्षा सहित तकनीक को बढावा दे रही है और बिहार सरकार जवाहर नवोदय विद्यालय तथा प्राइमरी स्कूलों को जमीन उपलब्ध नहीं कराते हुए छात्र व छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित राशि को बिहार सरकार विकास योजना में खर्च नहीं कर पा रही है. कुछ विभाग में खर्च करती भी है तो इसमें भ्रष्टाचार में डूबा रहता है. केन्द्र सरकार की राशि को बिहार सरकार मनरेगा में पानी की तरह खर्च कर रही है लेकिन धरातल पर काम नही दिखता है. उन्होंने रालोसपा कार्यकर्ता को केन्द्र सरकार की योजना की अधिक से अधिक प्रचार करने की जरूरत बताया ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार को भारी बहुमत मिल सके. इस मौके पर अंगद कुशवाहा, पंकज कुशवाहा, बलराम कुमार, साकेत कुमार , पूर्व प्रमुख पति बबलू कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे.

मेले में प्रशासन रहा सजग

गोगरी अनुमंडल स्थित उत्तरी वाहिनी गंगा घाट पर माघी पूर्णिमा के अवसर पर अहले सुबह घाट पहुंचकर एसडीओ संतोष कुमार, एसडीपीओ संजय कुमार झा सहित अन्य अधिकारियों के पहुंचकर कैंप कर दिया. दोपहर तक वे लोग अपने अधीनस्थों के साथों के साथ गंगा घाट पर लोगों को आने जाने में कतारबद्ध कर रहे थे. एसडीओ ने बताया कि यहां पर गोगरी बीडीओ रंजीत कुमार, सीओ सुनील कुमार, परबत्ता बीडीओ डॉ. कुन्दन, सीओ शैलेन्द्र कुमार, थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार के साथ जमे हुये थे. लोगों के कतारबद्ध भीड़ को चचरी पुल पार कराने मे सभी अधिकारियों के पसीने इतर रहे थें कुछ अधिकारी गंगा के उपधारा के समीप कुछ मुख्य धारा के समीप लगे हुए थे. वहीं उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर दूर दराज से आये लोगों के द्वार इस बार की व्यवस्था देखकर प्रशासन की प्रशंसा करते देखे गये.■

– गीता कुमार

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

पुल निर्माण से पहले ही राजनीति शुरू

जयमंगल पांडेय

बिहार घाट पर गंगा नदी में पुल बनाने के मुद्दे पर भाजपा की राजनीति इतनी गहराई कि भाजपा के वर्तमान तथा पूर्व विधायकों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की जंग शुरू हो गयी. बक्सर जिले के ब्रहम्पुर अंचल के नैनीजोर गांव में भाजपा के पूर्व विधायक डॉ. स्वामी नाथ तिवारी अपने समर्थकों के साथ बिहार घाट पर पीपा पुल बनाने सहित 32 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, वहीं पर ग्रामीणों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद ऐसा विरोध हुआ कि ब्रहम्पुर की भाजपा विधायिका दिलमणी देवी को वहां से चलीं गईं. वास्तव में बक्सर तथा बलियां (यूपी) को सीधे जोड़ने वाले नैनीजोर गांव में गंगा नदी पर पुल निर्माण की मांग लम्बे अर्से से हो रही है. ब्रहम्पुर की भाजपा विधायक दिलमणी देवी के पहल पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 मई 2012 को पुल निर्माण कराने की घोषणा की थी. इसके बाद दिसम्बर 2012 में ही 16 करोड़, 72 लाख रुपये की योजना स्वीकृति के बाद भी मामला कानूनी पेंच में फंस गया. दो साल के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और विधायिका द्वारा सार्थक पहल भी नहीं की गई कि आखिर माजरा क्या है? फिर तो ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ने के बाद ब्रहम्पुर के पूर्व भाजपा विधायक डॉ. स्वामी नाथ तिवारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गये. पूर्व विधायक की इस मुहिम पर राजनीतिक लाभ हानि का गणित शुरू हो गया. चूंकि नैनीजोर पूर्व विधायक का गांव है तो वर्तमान विधायिका का मायके भी है. दो पंचायतों वाला नैनीजोर गांव भाजपाई राजनीति का प्रमुख केन्द्र भी है. लिहाजा राजनीति गरमाई और दो दिनों तक अलग रहने के बाद विधायिका दिलमणी देवी तीसरे दिन समर्थन देने पहुंची. विधायिका के प्रतिनिधि बने उनके पुत्र संतोष मिश्रा ने ग्रामीणों के प्रति इस तरह आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे पूर्व विधायक के समर्थक ग्रामीण भड़क उठे. ग्रामीणों ने भारी हंगामा तथा नोकझोंक कर माईक भी छिन लिया. हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात वापस ले ली. खुलेआम विरोध से असहज स्थिति होने के बाद आखिरकार विधायक को वहां से भागना पड़ा. 26 जनवरी से शुरू हुई भूख हड़ताल पांच दिनों तक चली. पर फिर विधायक वहां नहीं गयीं. हद तो यह है कि निर्माण कार्य से विलंब का कारण आज तक किसी को ज्ञात नहीं था. भाजपा के सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने जब इस मामले में पहल की तो पता चला कि पुल निर्माण का मामला हाईकोर्ट पटना में लंबित है. सांसद ने जिलाधिकारी तथा विधि विभाग से वार्ता कर पूर्व विधायक के आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया. फिर हड़ताल को तोड़वाने के लिए झारखण्ड के पूर्व डीजीपी तथा पलामू के सांसद बीडी राम नैनीजोर गांव में आये और जिला प्रशासन के वरिय अधिकारियों द्वारा लिखित वायदे के बाद अनशन समाप्त हुआ. भाजपा के पलामू सांसद बीडी राय का पैतृक गांव नैनीजोर ही है. भाजपा के दो सांसदो के समर्थन से पूर्व विधायक ने प्रमुख मुद्दे को अंजाम तक पहुंचा कर ब्रहम्पुर विधान सभा क्षेत्र में पार्टी की एक नई लकीर खींच दी, जिससे अपनी ही पार्टी के विधायक हासिये पर चली गयी. वैसे ही विधायक के प्रतिनिधि के कार्यकलापों से कार्यकर्ता तथा आम जनता खासे नाराज है. यही कारण है कि जनसमस्या पर कार्यकर्ता पूर्व विधायक के साल गोलबंद हो गये. पार्टी में यहां पहले से गुटबंदी चरम पर है और चुनावी वर्ष में बढ़ती गुटबाजी को लेकर आपसी खींचतान बढ़ती जा रही है. दूसरी ओर जिले में जनता की समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक डॉ. तिवारी की बढ़ी हुई सक्रियता को लेकर पार्टी के अंदर तथा बाहर कई तरह के कयास लगाये जा रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन

पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया नगर पंचायत के पुरानी बाजार में महावीर मंदिर में बजरंगबली का प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों के साथ स्थापित की गयी. साहित्य आचार्य पंडित चन्द्रिका तिवारी ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना करायी. इस मौके पर ई. सुजय कुमार, शुभम कुमार, राजन कुमार गुप्ता, अवध कुमार, राज कुमार सर्राफ, विजय जायसवाल, गुलटेन कुशवाहा, चन्द्रशेखर सिंह, रवि कुमार, मुन्ना कुमार, अभय श्रीवास्तव, सुबोध चौधरी, शम्भू महतो समेत बड़ी संख्या में महिलाएं श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे. इस अवसर पर अनुमान आराधना का भी आयोजन किया.

– इंतेजारुल हक़

कार्यषाला आयोजित

पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा बीआसी के प्रांगण में प्रखण्ड शिक्षक संघ द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया. समारोह को संबोधित करते हुए संघ के महासचिव केशव कुमार ने वेतनमान की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रखने का आह्वान किया और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा. इस अवसर पर महासचिव केशव कुमार, संघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव ने कहा बीईओ उपेन्द्र प्रसाद ने डीपीई इतीर्ण षिक्षको के बीच संवर्द्धन कोर्स का प्रमाण पत्र का वितरण किया. कार्यक्रम की अध्यक्ष संघ के प्रखण्ड अध्यक्ष मोहम्मद तुफैल ने जबकि संचालन नागेन्द्र पाण्डेय ने किया. कार्यशाला को सम्बोधित करने वालों में श्रीनिवास प्रसाद,सचिदानन्द ठाकुर,संतोष सिंह,धनंजय सिंह,समेत सभी शिक्षक मौजूद थे.

बुद्ध मार्ग है विश्व शांति का रास्ता

भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही दुनिया में शांति–अहिंसा कायम किया जा सकता है. यह बात लाओस के धर्मगुरु डॉ. फमाहा चंदाफोन चक्कावारो ने कही. उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कई देशों मे हिंसा की बड़ी घटना हो रही है, जिससे मानव समाज को बड़ी क्षति उठानी पड़ रही है. हिंसा के मार्ग पर चलनेवाले लोगों को भगवान बुद्ध के बताये मार्ग पर चलने के प्रेरित करने की जरूरत है. जिससे दुनिया में शांति अहिंसा कायम हो सके. डॉ.फमाहा ने कहा कि भागवान बुद्ध आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है. इनके मध्यम मार्ग को अपनाकर हर व्यक्ति शांति–अहिंसा के सहारे अपना, समाज, देश तथा दुनिया को विकास के रास्ते पर ला सकता है. उन्होनें कहा कि बौद्धों के आस्था के महान केन्द्र बोधगया में विदेशी पर्यटकों के लिए और अधिक से अधिक सुविधा दिये जाने की जरुरत है. जिससे कि बड़ी संख्या मे विदेशी पर्यटक भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि को नमन कर शांति–अहिंसा का प्रकाश फैला सके.

– सौरभ

जयंती पर कविता पाठ

साहित्यकार उपेन्द्रनाथ 'अश्क' की जयंती द्विजदेनी पुस्तकालय फॉरबिसगंज के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर मनाई गयी. रामलाल उच्च विद्यालय हरिपुर डाक में शायर नैयर शमशाद की अध्यक्षता में मनायी गयी इस जयंती समारोह में साहित्यप्रेमियों एवं स्कूली छात्र–छात्राओं ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया. बाल साहित्यकार हेमंत यादव 'शशि', डॉ. अनुज प्रभात, मो. नैयर शमशाद एवं हर्ष नारायण दास ने 'अश्क' के बारे में बताया कि वे स्वतंत्र लेखन के अलावा अध्यापन पत्रकारिता रंगमंच से भी जुड़े थे. उनका जन्म पंजाब में हुआ था. इस अवसर पर वक्ताओं ने इनकी कृति गर्म राख, नवरत्न, औरत की फितरत, जुदाई की शाम का गीत पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला. मौके पर छात्रा अखतरी खातुन ने 'परदा क्या है', 'आंचल क्या है' एवं नाजरीन बेगम ने 'वहीं रहेंगे अल्हाह, वहीं रहेंगे राम' तथा हर्षिता ने 'निर्मल नीर गंगा का' कविता का पाठ किया. तथा कविता सुहानी, रुचि, रोजी, शालिनी, आकृति, मुर्शीदा, राकेश, वसीम, शुभम, नवल, वेदिका, प्रगति साजिया ने एक से बढ़कर मधुर एवं दर्द भरे गीत पेश कर श्रोताओं का मन मोह लिया. कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन संस्था के संस्थापक संचालक विनोद कुमार तिवारी ने किया.

– अजातशत्रु अग्रवाल

झारखंड ने भागलपुर को हराया

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के सर्किल नम्बर 1 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मेला में महिला फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया. मैच का मुख्य मुकाबला झारखंड तथा भागलपुर के टीम के बीच खेला गया. जिसमें झारखंड की टीम ने भागलपुर को 2–1 से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया. मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि एसपी धुरत सायली सबला राम ने किया. मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि यहां हर वर्ष खेल का आयोजन किया जाता है. खेल से आपसी प्रेम बढ़ता है. खेल में हार व जीत तो लगी ही रहती है. एक हारता है तो दूसरा जीतता है लेकिन सच्चा खिलाड़ी वहीं होता है जो अपने हार से कुछ सीख लेता है. मौके पर गोगरी एसडीपीओ संजय कुमार झा, पसराहा थानाध्यक्ष राजेश कुमार यादव, पौरा ओपी अध्यक्ष सुनील कुमार सहनी, मड़ैया ओपी अध्यक्ष मनीष कुमार, मेला अध्यक्ष सुबोध कुमार, राजेश कुमार, जदयू प्रदेश महासचिव गजेन्द्र कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता विपीन कुमार यादव, जयचन्द्र सिंह, नवीन कुमार सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे.

सड़क का शिलान्यास

गोगरी अनुमंडल के देवरी पंचायत अन्तर्गत अररिया गांव के आईओ सड़क में सुनील यादव के घर से रामरूप यादव के घर तक पीसीसी सड़क का शिलान्यास विधायक रामानंद प्रसाद सिंह ने किया. यह सड़क मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत बनाया जायेगा. इस मौके पर विधायक ने बताया कि सड़क कि लम्बाई 250 मीटर एवं चौडाई 10 मीटर है. यह सड़क पर 3 लाख 87 हजार 600 रूपये लागत से बनेगा. इन्होंनें कहा इस सड़क के निर्माण से लोगों की परेशानी कम हो जायेगा. इस अवसर पर जदयू नेता डा0 संजीव सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष नंदलाल मंडल, ध्रूव कुमार शर्मा, जयकृष्ण यादव, राजाराम यादव, सुनील यादव, नंदमोहन कुमार, अनील कुमार, कुन्दन कुमार, विधानचन्द्र कुमार, प्रियदर्शी चितरंजन सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे.■

– गीता कुमार

> नीलामी विभाग के हवाले से बताया गया कि दुकानदार राजेंद्र प्रसाद, अहमदी खातून, अरुण कुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, विदेश्वर प्रसाद गुप्ता, डॉ बीएन वसू, रघुनाथ, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ओम प्रकाश खेतान, विनोद कुमार सिन्हा, लक्ष्मी साह, अजीत कुमार वर्मा, उपेंद्र राय, अरविंद कुमार श्रीवास्तव, राम करण महतो, राम औतार साह, अशोक कुमार गुप्ता व दया शंकर प्रसाद समेत कुल 40 दुकानदार शामिल है, जिन पर करीब 2 करोड़ से अधिक किराया मद का बकाया है.

सीतामढ़ी

ख़ास महाल की ज़मीन पर कब्जे की होड़

सीतामढ़ी जिले में भी वैसे तो सरकारी फरमान के आलोक में विकास कार्यों का कार्यान्वयन होता रहता है. परंतु कुछ ऐसे भी मामले है जिन पर प्रशासनिक निर्देश और सरकारी आदेशों का कोई मतलब नहीं रह गया है. मामला शहर में सरकारी जमीन के अतिक्रमण का हो अथवा नासी नाला की जमीन के अतिक्रमण का. सरकारी आदेश व प्रशासनिक निर्देशों के बाद भी इससे संबंधित फाइलें सालों से विभागीय कार्यालयों में धूल फांक रही हैं. इस पर नजर डालने का वक्त जिले के आलाधिकारियों के पास नहीं रह गया है. फिलहाल सीतामढ़ी में खास महाल की जमीन सरकारी व प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ती जा रही है. सरकारी जमीन के लीज के निर्धारित समय सीमा पार कर जाने के बाद भी न तो इस जमीन पर सरकार की नजर जा रही है और न ही जिला प्रशासन लीजधारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने में सफल हो पा रहा है. कारण कि खास महाल की कीमती जमीन पर कद्दावर लोगों का कब्जा है.

वाल्मीकि कुमार

भ्रष्टाचार के सफाये और कानून का राज स्थापित करने को लेकर सरकारी स्तर पर चाहे जितनी भी डींगे हांक ली जाएं, परंतु जमीनी सच्चाई से इसका कोई लेना-देना नहीं रह गया है. अगर सरकार प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को छोड़ दिया जाये तो सरकार के प्रशासनिक तंत्र की उपलब्धि को तलाश पाना आसान नहीं है. वर्तमान में प्रशासनिक महकमे की नजर केवल वैसे ही स्थान पर जाकर अटकती नजर आ रही है, जहां से कुछ 'आसार' की गुंजाइश होती है. सड़क, नाला, पुल-पुलिया के निर्माण के अलावा इनकी नजर व्यवस्था के दूसरे कोने तक पहुंच ही नहीं पा रही है. कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर वादे तो किये जाते हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों में दबी फाइलों से धूल हटाने का प्रयास शायद ही किया जाता है. नतीजा है कि कोई भी एक काम सही तरीका से ससमय हो पाना मुश्किल बना है.

सीतामढ़ी जिले में भी वैसे तो सरकारी फरमान के आलोक में विकास कार्यों का कार्यान्वयन होता रहता है. परंतु कुछ ऐसे भी मामले हैं जिन पर प्रशासनिक निर्देश और सरकारी आदेशों का कोई मतलब नहीं रह गया है. मामला शहर में सरकारी जमीन के अतिक्रमण का हो अथवा नासी नाला की जमीन के अतिक्रमण का. सरकारी आदेश व प्रशासनिक निर्देशों के बाद भी इससे संबंधित फाइलें सालों से विभागीय कार्यालयों में धूल फांक रही हैं. इस पर नजर डालने का वक्त जिले के आलाधिकारियों के पास नहीं रह गया है. फिलहाल सीतामढ़ी में खास महाल की जमीन सरकारी व प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ती जा रही है. सरकारी जमीन के लीजधारी के निर्धारित समय सीमा पार कर जाने के बाद भी न तो इस जमीन पर सरकार की नजर जा रही है और न ही जिला प्रशासन लीजधारी के मनमानी पर अंकुश लगाने में सफल हो पा रही है. कारण कि खास महाल की कीमती जमीन पर कद्दावर लोगों का कब्जा है. मकान निर्माण के लिए दी गयी जमीन हो अथवा दुकान की. सभी जगह हाल समान है. नतीजा है कि लीजधारी मालामाल तो सरकारी राजस्व का गोलमाल व्यापक स्तर पर किया जा रहा है. इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में किस्त दर किस्त खबरें प्रकाशित होती रही हैं, लेकिन मामला जांच से आगे नही बढ़ पा रहा है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन साढ़े चार दशक पूर्व लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी इस मामले में जिला प्रशासन लीजधारियों की औकात के सामने बौना साबित हो रहा है.

बताया जाता है कि सीतामढ़ी में जिला मुख्यालय डुमरा एवं सीतामढ़ी शहर में खास महाल की पर्याप्त जमीन है. हाल के साल में डीएम डॉ. प्रतिमा के निर्देश पर खास महाल के प्रभारी अधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता संदीप कुमार ने डुमरा में खास महाल के आवासीय क्षेत्र का सर्वेक्षण शुरू कराया था. डुमरा शंकर चौक के निकट स्थित काली मंदिर से लेकर बागमती परिसदन तक खास महाल का क्षेत्र फैला है. खबरों के मुताबिक तकरीबन एक दशक पूर्व डुमरा अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी व अंचल अमीन द्वारा खास महाल के आवासीय क्षेत्र की सर्वेक्षण सूची जिला प्रशासन को सौंपी गई थी. जिसमें कुल 108 लीजधारियों का नाम शामिल था. जिनकी लीज की अवधि अब समाप्त हो चुकी है. सूची के अनुसार अधिकांश लीजधारियों ने अपने आवासीय क्षेत्र की जमीन को किराये पर लगा दिया है. साथ ही 11 लोगों ने लीज की जमीन का अतिक्रमण भी किया है. जबकि कई लोग लीज की जमीन पर मकान का निर्माण कर किराया भी कमा रहे हैं. खबरों में प्रकाशित सूची के अनुसार 01 नवंबर 1939 से 19 मार्च 1969 तक कुल 29 लीजधारियों की लीज की अवधि निर्धारित थी. 28 दिसंबर 1940 से 19 दिसंबर 1970 तक 5, 1 अप्रैल 1937 से 31 मार्च 1967 तक 48, 19 अक्टूबर 58 से 18 अक्टूबर 88 तक 8 लीजधारी, वर्ष 1941 से 1971, 1944 से 1974, 1938 से 1968, 1967 से 1997, 1953 से 1983 एवं 1955 से 1985 की अवधि तक विभिन्न लीजधारियों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है. लीज की अवधि 30 साल निर्धारित की गयी थी. बताया गया है कि इनमें अधिकांश लीजधारियों का देहांत हो चुका है, परंतु उक्त जमीन पर लीजधारियों के परिजनों का दखल है. इनमें कई राजनीतिक हस्ती व अन्य कद्दावर लोग शामिल है. खास महाल के प्रभारी वरीय उप समाहर्ता संदीप कुमार ने पत्रकारों को बताया था कि खास महाल आवासीय क्षेत्र की भूमि को किराये पर देना अवैध है. लीजधारियों से लीज की जमीन का मूल कागजात मांगा जा रहा है.

अब एक नजर सीतामढ़ी शहर में मौजूद खास महाल की जमीन पर भी डाली जाये. नगर के बाटा गली के समीप से लेकर किरण चौक व अस्पताल रोड में कुछ दूरी तक खास महाल की जमीन है. बताया जाता है कि श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज परिसर में पड़ने वाली खास महाल की इस जमीन पर कुल 133 दुकाने हैं. इनमें अधिकांश लीजधारी दुकानदारों द्वारा सालों से किराये का भुगतान नहीं किया गया है. पिछले कुछ सालों में तकरीबन दो दर्जन से अधिक लीजधारी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए दुकान ट्रांसफर और पार्टनर बनाने के नाम पर दुकान की जमीन को लाखों में बेच चुके है. जबकि इक्त दुकानों का किराया अब भी खास महाल का बकाया है. इस गोरखधंधे में खास महाल कार्यालय के कर्मियों की संलिप्तता से इंकार नही किया जा सकता है. कारण कि ट्रांसफर की प्रक्रिया कार्यालय की सहमति के बिना संभव नहीं हो सकती है. बताया जाता है कि पिछले साल 22 जुलाई को जिला नीलामी अधिकारी गोपाल शरण ने किराया भुगतान नहीं करने वाले कॉलेज परिसर स्थित 40 दुकानदारों को नोटिस जारी किया था. इन दुकानदारों पर 2 करोड़ से अधिक किराया बकाया था. इस क्रम में यह भी खुलासा हुआ कि जिन दुकानदारों के नाम जमीन की बंदोबस्ती की गयी थी, वह दुकानदार अपनी दुकान लाखों में गैर कानूनी तरीके से बेच दिया है. जबकि खास महाल के नियम के मुताबिक जिस दुकानदार के नाम बंदोबस्ती है, वह न तो ट्रांसफर कर सकता है और न ही बेच सकता है. पूर्व के सालों में कुछ दुकानदारों ने किराया बढ़ोतरी को लेकर उच्च न्यायालय में मुकदमा भी किया. वर्ष 2008 में 15 दुकानदारों ने खास महाल विभाग के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा किया था. जिसमें कोर्ट का फैसला दुकानदारो के पक्ष में हुआ था. इस मामले में प्रथम आदेश 7 सितंबर 2009 एवं दूसरा आदेश 15 नवंबर 2011 को आया था. जिसमें दुकानदारों को पुराने दर से बकाया का भुगतान करने का आदेश हुआ था. आदेश के आलोक में जब दुकानदार खास महाल कार्यालय पहुंचे तो उन्हें चक्कर लगाने की विवषता बनी रही. कारण विभागीय कर्मियों द्वारा लंबी कागजी प्रक्रिया बताया गया. नीलामी विभाग के हवाले से बताया गया कि दुकानदार राजेंद्र प्रसाद, अहमदी खातून, अरुण कुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, विदेश्वर प्रसाद गुप्ता, डॉ बीएन वसू, रघुनाथ, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ओम प्रकाश खेतान, विनोद कुमार सिन्हा, लक्ष्मी साह, अजीत कुमार वर्मा, उपेंद्र राय, अरविंद कुमार श्रीवास्तव, राम करण महतो, राम औतार साह, अशोक कुमार गुप्ता व दया शंकर प्रसाद समेत कुल 40 दुकानदार शामिल है, जिन पर करीब 2 करोड़ से अधिक किराया मद का बकाया है.

खास महाल की जमीन पर चल रही माफियागीरी पर अब राजनीतिक दल के नेताओं ने चुप्पी तोड़ दी है. पूर्व सांसद नवल किशोर राय का कहना है कि खास महाल की नीति जर्जर हो चुकी है. सरकार को नयी नीति बनानी चाहिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके. खास महाल को मूल अवधारणा को लेकर चलने की आवश्यकता है. नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि खास महाल की जमीन पर नाम बदलने की विभागीय छूट के बहाने हो रही लूट पर रोक आवश्यक है. खास महाल के जमीन की समीक्षा आवश्यक है. जिला प्रशासन को दुकानदारों की बात को सुन कर सार्थक रास्ता निकालना चाहिए. अगर कोई अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो उसके बगल वाले दुकानदार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, अगर नहीं तो नये लोगों को उक्त स्थान पर मौका दिया जाना चाहिए. चल रही कथित खरीद-बिक्री पर रोक आवश्यक है. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला का कहना है कि अधिकांश लीजधारी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

आवासीय लीज की जमीन को व्यवसायिक बना कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इस मामले में राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने चुप्पी साधी है. भाकपा जिला सचिव जय प्रकाश राय का कहना है कि खास महाल के जमीन की वर्तमान स्थिति के लिए जिला प्रशासन दोषी है. खास महाल की जमीन की बंदोबस्ती नये बाजार दर पर की जानी चाहिए. सरकारी फंड से गरीबों के लिए कॉलोनी का निर्माण कराया जाना चाहिए. धनवानों के हाथों से अविलंब खास महाल की जमीन वापस नहीं लिये जाने पर जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है. लोजपा नेता सबीह अहमद का कहना है कि खास महाल की जमीन में व्यापक स्तर पर हेरा-फेरी की जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार व जिला प्रशासन समान रूप से दोषी हैं. पुराने लीजधारी की लीज की अवधि समाप्त होने की स्थिति में नयी दर पर नये लोगों को मौका दिया जाना चाहिए. जिला जदयू उपाध्यक्ष सज्जन कुमार सुंदरका का कहना है कि खास महाल की जमीन का गलत तरीके से उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए. पूर्व के लीजधारियों की जांच कर खास महाल की जमीन पर गरीबों के लिए कॉलोनी का निर्माण कराया जाना चाहिए.

चर्चा है कि पूर्व में कुछ आलाधिकारियों ने खास महाल के गोरखधंधे पर विराम लगाने की दिशा में पहल की थी. परंतु खास महाल की जमीन के कद्दावर कब्जाधारियों के सामने इनकी कुछ चलती, इससे पूर्व उनका स्थानांतरण हो गया. नेता, अधिवक्ता समेत अन्य रसूखदारों के ओहदे में दबने के कारण प्रशासनिक महकमे इस मामले में अब तक कुछ नहीं कर सका है. अगर यही आलम रहा तो खास महाल की नौबत पुराने जमींदारों के समान रह जाएगी, जो जमींदार तो कहलाते हैं मगर जमीन का स्वामित्व दुर्लभ होता है. रही सरकारी राजस्व की बात तो इसके लिए जिला प्रशासन कितना सजग होता है यह आने वाला समय ही बतायेगा. फिलहाल खास महाल की जमीन की व्यापक स्तर पर की जा रही फर्जी बिक्री व ट्रांसफर की चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाने की आवश्यकता है.■

आवासीय लीज की जमीन को व्यवसायिक बना कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इस मामले में राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने चुप्पी साधी है. भाकपा जिला सचिव जय प्रकाश राय का कहना है कि खास महाल की जमीन की वर्तमान स्थिति के लिए जिला प्रशासन दोषी है. खास महाल की जमीन की बंदोबस्ती नये बाजार दर पर की जानी चाहिए. सरकारी फंड से गरीबों के लिए कॉलोनी का निर्माण कराया जाना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

16 फरवरी–22 फरवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

आजम को मुलायम सिंह यादव का भव्य जन्मदिन मनाने का तोहफा

कौड़ियों के भाव मिली सरकारी ज़मीन और इमारत

वैष्णवी वंदना

मौलाना जौहर अली शोध संस्थान की जमीन जौहर अली ट्रस्ट को दे दिए जाने के कारण समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान फिर विवाद में हैं. लेकिन इस विवादास्पद मसले में आजम खान के साथ-साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर भी बदनामी के छींटे पड़ रहे हैं. प्रदेश के लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा के समक्ष यह प्रकरण पेश हुआ है और इसकी जांच की औपचारिकताएं भी शुरू हो गई हैं. जौहर अली विश्वविद्यालय के कुलपति और मंत्री जैसे लाभ के दो-दो पदों पर एक साथ काम करने का विवाद अभी चल ही रहा था कि यह नया विवाद सामने गया है. तीन फरवरी को सपा सुप्रीमो ने आजम खान को अपने आवास पर बुलाकर इस बारे में विस्तार से सलाह मशविरा किया और विवाद से बाहर निकलने की रणनीति पर बातचीत की. जौहर अली ट्रस्ट को जमीन दिए जाने के मामले के साथ ही इलाहाबाद में एक शैक्षिक संस्था के लिए आवंटित सरकारी जमीन को धार्मिक संस्था यीशू दरबार ट्रस्ट को दे दिए जाने का मामला भी गरमा गया है.

दोनों मामलों के उजागर होने के बाद समाजसेवी डॉ. नूतन ठाकुर और उनके आईपीएस पति अमिताभ ठाकुर ने इसे कानून की दहलीज तक पहुंचाने का काम किया. डॉ. नूतन ठाकुर ने प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आजम खान द्वारा मौलाना जौहर अली शोध संस्थान रामपुर की बेशकीमती भूमि और भवन को अपनी ही निजी संस्था मौलाना जौहर अली ट्रस्ट को दिए जाने के खिलाफ लोकायुक्त जस्टिस एन के मल्होत्रा के समक्ष परिवाद दायर किया है. जौहर अली शोध संस्थान राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के तहत है, लिहाजा उसकी जमीन सरकारी जमीन है और उसे बिना किसी नियम, शर्त और प्रक्रिया के ट्रस्ट को दे दिया जाना पूरी तरह गैर कानूनी है. लोकायुक्त की अदालत में दाखिल शिकायत में कहा गया है कि निजी संस्था या लोगों को सरकारी भूमि दिए जाने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौरभ गांगुली, सुभाष घई और कुशाभाई ठाकरे ट्रस्ट मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए आजम खान ने रामपुर शहर में करीब 1500 वर्गगज जमीन और उस पर 9.83 करोड़ में बने सरकारी भवन को अपनी निजी संस्था के नाम मात्र सौ रुपये की वार्षिक लीज पर तीस साल के लिए दे दिया. आजम खान का यह फैसला पद का सीधा-सीधा दुरुपयोग है. यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि तत्कालीन प्रमुख सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने शोध संस्थान की सरकारी भूमि और भवन को विभागीय मंत्री की निजी संस्था को दिए जाने का विरोध किया था. इसका नतीजा यह निकला कि प्रमुख सचिव को ही उनके विभाग से हटा दिया गया और सरकारी मशीनरी पर दबाव डाल कर यह गैरकानूनी फैसला करा लिया गया. लोकायुक्त से इस मामले की जांच कराते हुए विवादास्पद आवंटन को निरस्त करने और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है. विडंबना यह है कि जौहर अली ट्रस्ट को महज सौ रुपये की लीज पर 30 साल के लिए सरकारी जमीन दे दिए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाई है. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से यह फैसला हुआ था. मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद केवल राज्य सरकार और आजम खान के ट्रस्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होना बाकी था. खुद सपाई ही कहते हैं कि 21 और 22 नवम्बर को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का रामपुर में भव्य जन्मदिन समारोह मनाने के एवज में आजम खान के ट्रस्ट को अली जौहर संस्थान रिटर्न गिफ्ट में दे दिया गया. आजम खान को प्रति-उपहार देने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये 20 नवंबर को ही यह फैसला सुरक्षित कर दिया था. लीज की अवधि, रेंट और करार के मसौदे तय होने बाकी रह गए थे. लीज रेंट तय करने के लिए फाइल राजस्व विभाग के पास भेजी गई थी. लेकिन राजस्व विभाग ने इस पर कोई राय नहीं दी थी. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के अफसरों ने मोगैम्बो को खुश करने के लिए लीज रेंट सौ रुपये सालाना तय कर दी. फिर आजम खान ने इसी लीज रेंट पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुहर भी लगवा ली.

उल्लेखनीय है कि आजम खान का ड्रीम प्रॉजेक्ट मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है. यूनिवर्सिटी बनने के बाद सरकार ने उसे अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित करा लिया था. लेकिन तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर और उनके बाद आए बीएल जोशी ने उसे रोक लिया. बाद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी इसे अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया. पर राज्यपाल तैयार नहीं हुए थे. राजभवन का कहना था कि इस बिल को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है. बाद में महज कुछ दिन के लिए प्रभारी राज्यपाल बने अजीज कुरैशी ने जौहर विश्वविद्यालय को यह दर्जा दे दिया. कुरैशी अपना एजेंडा पूरा कर वापस चले गए. यूनिवर्सिटी के साथ दूसरा विवाद आजम खान के आजीवन कुलपति रहने को लेकर हुआ. हाईकोर्ट ने भी कुछ महीने पहले ही सरकार से यह सवाल पूछा था कि मंत्री रहते हुए आजम खान किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर कैसे रह सकते हैं. यूनिवर्सिटी को जमीन दिए जाने, लीज रेंट माफ किए जाने और सरकारी मदद दिए जाने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. मौलाना मुहम्मद अली जौहर शोध संस्थान के जरिये आजम खान अपने ट्रस्ट का साम्राज्य बढ़ाने में लगे हैं. इस संस्थान के मिलने से ट्रस्ट को करोड़ों की बेशकीमती जमीन व इमारत मिल जाएगी. आजम खान इस शोध संस्थान का अपने ट्रस्ट में विलय इसलिए भी चाहते थे कि शोध संस्थान की बेशकीमती जमीन उनकी कोठी से ही सटी हुई है. दूसरी तरफ सरकार द्वारा दी गई जमीन को इलाहाबाद की धार्मिक यीशु दरबार ट्रस्ट को देने का मामला भी गरमा गया है. आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद के सैम हिग्गिनबॉटम इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज को सरकार द्वारा दी गई जमीन एक धार्मिक संस्था यीशु दरबार ट्रस्ट को दिए जाने पर आपत्ति जताई है. शैक्षणिक संस्था ने कानून को ताक पर रख कर सरकारी जमीन ट्रस्ट को दे दी. अमिताभ ठाकुर ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि 23 मई 1914 को ब्रिटिश भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा नॉर्थ इंडिया मिशन ऑफ अमेरिकन प्रेस्बीटेरियन चर्च इन द यूएसए के बीच हुए समझौते के अनुसार संयुक्त प्रांत सरकार ने 53.275 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में कृषि विभाग बनाने के लिए दिया था जो बाद में एग्रीकल्चर इंस्टिट्यूट बना. इस समझौते में स्पष्ट रूप से अंकित था कि यह भूमि बिना सरकार की अनुमति के किसी भी अन्य प्रयोग के लिए हस्तांतरित नहीं की जाएगी. इसके बावजूद हिग्गिनबॉटम एग्रीकल्चर इंस्टिट्यूट ने एक डीड के माध्यम से 26 बीघा जमीन यीशु दरबार ट्रस्ट को दे दी. ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य गॉस्पेल और धार्मिक कार्य फैलाना है. श्री ठाकुर ने इस भूमि हस्तांतरण को 23 मई 1914 के करार के विरुद्ध बताते हुए प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री से मामले की जांच करा कर पूर्णतया धार्मिक कार्यों हेतु किए गए इस हस्तांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया है. उल्लेखनीय है कि यीशु दरबार ट्रस्ट पर धर्मांतरण की गतिविधियों में शरीक रहने के आरोप लगते रहे हैं. अवैध रूप से सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरित करने तथा संस्थान के परिसर में जबरन धर्मांतरण कराने के आरोपों की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई थी. इसके पहले भी कई बार यीशु दरबार में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए छात्र समुदाय विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सरकारी जमीन देने पर राज्यपाल नाराज

मौलाना अली जौहर शोध संस्थान की सरकारी जमीन आजम खान की निजी संस्था को दिए जाने के प्रकरण पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राम नाईक बेहद नाराज हैं. राज्यपाल ने कहा कि वे इस गंभीर मसले पर खुद राज्य सरकार से बात करेंगे. आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को महज सौ रुपये की सालाना लीज पर जमीन देने के मसले की जानकारी मिलने के बाद राज्यपाल ने कहा कि वे खुद सरकार से जानकारी लेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे. राज्यपाल ने कहा कि इस तरह सरकारी जमीन दिए जाने पर ऑडिटर जनरल जांच करते हैं. जिस ट्रस्ट को जमीन दी गई है, वह सक्षम है या नहीं? इसकी रिपोर्ट भी ऑडिटर जनरल ही विधानसभा के सामने रखते हैं. विधानसभा की जिम्मेदारी है कि इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करे. राज्यपाल बोले, मैं खुद इस मामले की जानकारी ले रहा हूं कि किन परिस्थितियों में यह जमीन मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दी गई. राज्य सरकार यह लीज 30 वर्षों के लिए देने जा रही है. इसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूर किया है. अब केवल राज्य सरकार और आजम खान के ट्रस्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होना ही बाकी है.

विडंबना यह है कि जौहर अली ट्रस्ट को महज सौ रुपये की लीज पर 30 साल के लिए सरकारी जमीन दे दिए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाई है. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से यह फैसला हुआ था. मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद केवल राज्य सरकार और आजम खान के ट्रस्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होना बाकी था. खुद सपाई ही कहते हैं कि 21 और 22 नवम्बर को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का रामपुर में भव्य जन्मदिन समारोह मनाने के एवज में आजम खान के ट्रस्ट को अली जौहर संस्थान रिटर्न गिफ्ट में दे दिया गया.

पहले से आजम की जमीनों पर नज़र रही है

आजम खान के ट्रस्ट को सरकारी जमीने दिए जाने के मसले में अब कई और परते खुल कर सामने आ रही हैं. अपने निजी ट्रस्ट के साम्राज्यवादी विस्तार के लिए इर्द-गिर्द की जमीनों पर आजम खान की लोलुप निगाह पहले से रही है. रामपुर किले के अंदर स्थित मॉडल मांटेसरी स्कूल के भवन को ही पट्टे पर ट्रस्ट के नाम कर देने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को अर्सा पहले पत्र लिखा था. ट्रस्ट के लिए वे शासन से दो और सरकारी इमारतें हासिल करना चाहते थे. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने सरकार से रामपुर की दो और इमारतों को ट्रस्ट को पट्टे पर देने की मांग की थी. इसके लिए भी वह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिख चुके हैं. इनमें से एक रामपुर के मजार चुप शामिया मोहल्ले में स्थित ओरियंटल कॉलेज की इमारत भी है. आजम खान इस इमारत को नाजायज कब्जे का शिकार बताते-बताते खुद ही कब्जा करने की कोशिशों में लग गए. आजम खान तर्क यह देते थे कि वे यहां रामपुर के बच्चों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) से मान्यताप्राप्त स्कूल खोलना चाहते हैं.

सपा विधायक को उम्रकैद

चरखारी सीट पर फिर होगा उपचुनाव

ओम नारायण तिवारी

उमा भारती के झांसी से सांसद बनने के बाद उनके पुराने विधानसभा क्षेत्र चरखारी में आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं. बुन्देलखण्ड के महोबा जिले के चरखारी विधानसभा क्षेत्र में सितम्बर 2014 में उप-चुनाव में मोदी लहर के बावजूद समाजवादी पार्टी के कप्तान सिंह राजपूत विधायक चुने गए थे. सपा ने भाजपा से सीट छीन ली थी. लेकिन राजनीतिक परिवर्तन का दौर यहीं नहीं थमा है. 13 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में सपा विधायक कप्तान सिंह को उरई (जालौन) न्यायालय ने पांच जनवरी 2015 को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कप्तान को विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी है. अब एक और उपचुनाव होगा. चरखारी में उपजी इस रिक्तता में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है यह बुन्देलखण्ड की भावी राजनीति के लिए निर्णायक हो सकता है.

1948 में देसी रियासतों के खात्मे के बाद चरखारी रियासत का विंध्य प्रदेश में विलय कर

बसपा नेताओं को जेल

कप्तान सिंह की आपराधिक संलिप्तता के न्यायिक फैसले की स्याही अभी सूखने भी नहीं पाई थी कि चरखारी के पूर्व बसपा विधायक उदय प्रकाश और महोबा के बसपा जिलाध्यक्ष हरगोविन्द कुशवाहा को भ्रष्टाचार के लिए सात-सात वर्ष की कैद का न्यायिक फैसला सामने आया है. दोनों को फर्जी तरीके से डा0 भीमराव अम्बेडकर तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलकर 11 फरवरी 1995 को शासन को पांच लाख रुपये का चूना लगाने का दोषी पाया गया है. 1998 में महोबा के तत्कालीन कलेक्टर उमेश सिन्हा ने यह फर्जीवाड़ा पकड़ा था. मामले की सुनवाई पूरी होने पर महोबा न्यायालय ने 19 जनवरी 2015 को दोनों को सजा सुनाई है. पूर्व विधायक उदय प्रकाश ने खादी से पहले खाकी में दाग लगाया था. पुलिस महकमे में सिपाही पद से 1988 में बर्खास्त उदय प्रकाश ने बसपा के दिल्ली कार्यालय में शरण ली. कांशीराम से निकटता गांठी और 1993 में चरखारी से बसपा विधायक बन गया. 1994 में भानवती कांड में उदय प्रकाश खलनायक बनकर उभरे. भानवती को न्याय के लिए भाजपा के दबंग पूर्व विधायक बादशाह सिंह का मोर्चा संभालना बसपा की बैसाखी पर टिकी मुलायम सरकार को रास नहीं आया. बादशाह पर पुलिसिया दमन के खिलाफ उमा भारती और कलराज मिश्र आदि भाजपा दिग्गजों को हमीरपुर आकर संघर्ष करना पड़ा था. तब सरकारी संरक्षण में उदय प्रकाश का कुछ नहीं बिगड़ा था. लेकिन अब सजा मिल चुकी है. उनके साथी कुशवाहा को बसपा के महोबा जिलाध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया है. ■

दिया गया था. विंध्य प्रदेश का गठन बुन्देलखण्ड के शासकों ने मिलकर किया था. बाद में विंध्य प्रदेश को खत्म कर चरखारी रियासत की चार तहसीलों का मध्य प्रदेश में विलय हो गया था और चरखारी तहसील को उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनाया गया. चरखारी की जनता इसके पक्ष में नहीं थी. लेकिन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शासकों के भरपूर विकास और भविष्य में हमीरपुर से अलग कर जिले का दर्जा देने के आश्वासनों से बात बन गई थी. चरखारी के रूप में उत्तर प्रदेश को एक बेहतरीन पर्यटन स्थल हाथ लगा. लेकिन चरखारी के हिस्से सिर्फ उपेक्षा आई है. 1962 में चरखारी पहली बार आरक्षित विधानसभा क्षेत्र बना और 1967 व 1969 में अनारक्षित रहने के बाद 1974 से 2007 तक पुनः अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहा है. इस लंबे दौर में चुने गए माननीय सीमित प्रभाव के चलते चरखारी की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे. इस बीच 1995 में तत्कालीन मुलायम सरकार ने महोबा को जिला बना दिया और हमीरपुर के विभाजन पर चरखारी को जिला बनाने की पूर्ववर्ती शासकों की वचनबद्धता धरी रह गईं. चरखारी अब हमीरपुर के बजाय महोबा जिले का तहसील मुख्यालय है.

लेकिन 2012 में चरखारी के एक बार फिर अनारक्षित होने पर बतौर भाजपा प्रत्याशी उमा भारती का विधायक निर्वाचित होना बिजली कौंधने जैसा था जिसकी रोशनी में चरखारी को खोया वैभव लौटता नजर आया था. इसका ठोस आधार था. अटल सरकार में केन्द्रीय मंत्री रहते खजुराहो-महोबा रेल लाइन और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में सड़क आदि क्षेत्रों में उमा के उल्लेखनीय काम लोगों के सामने थे. यह जानते हुए कि उमा उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आने वालीं हैं फिरभी लोगों ने हाथों हाथ लिया. उमा ने 66,888 मत प्राप्त कर सपा के कप्तान सिंह राजपूत को 22,265 मतों से शिकस्त दी. चरखारी को पर्यटन नक्शे में उभारने का भरोसा देने में उमा भी पीछे नहीं रहीं. उन्होंने उद्योग जगत को भरोसे में लेने के संकेत दिए थे. लगा था कि उमा की सरपरस्ती में चरखारी के विकास को नया आयाम मिलेगा. लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उमा ने वाया उत्तर प्रदेश दिल्ली की राह पकड़ ली. उमा भारती झांसी से सांसद चुने जाने के बाद मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गई हैं. सितम्बर 2014 में विधानसभा के उपचुनाव में सपा ने भाजपा से सीट छीन ली. समाजवादी पार्टी के कप्तान सिंह ने 95,008 मत बटोरे और 50,800 मतों के अन्तर से धमाकेदार जीत दर्ज की. लेकिन चार माह बाद ही सपा विधायक कप्तन सिंह के सितारे अचानक गर्दिश में आ गये. जालौन जिले के मूल निवासी कप्तान सिंह चुनाव लड़ते वक्त हत्याभियुक्त थे. 20 अप्रैल, 2002 को कानपुर से पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर उरई आए जालौन जिले के रेढ़र थाने के डीहा गांव निवासी श्यामाचरण के बेटे किशनजी डीहा की रेलवे स्टेशन से कचहरी जाते समय टाउनहाल के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कप्तान सिंह के बड़े भाई लक्ष्मण और साथियों समेत हत्याभियुक्त नामित हुए थे. उरई (जालौन) के विशेष जज डकैती संजय कुमार ने कप्तान और उनके भाई लक्ष्मण राजपूत को हत्या का दोषी मानते हुए पांच जनवरी 2015 को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों जेल में हैं. चुनाव आयोग ने सजा की तिथि से विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी है. उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 22 जनवरी को चरखारी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है. अब एक और उपचुनाव होगा. 2012 से 2015 में यह तीसरा चुनाव होगा. उपचुनाव की घोषणा से पहले ही राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है. उम्मीदवारी को लेकर जुगत-जुगाड़ का दौर शुरू हो गया है. सवाल है कि चरखारी के चुनावी दंगल में क्या इस बार भी दागी ताल ठोकेंगे? विधायक को सजा से सपा की छवि खराब हुई है. सपाई सजायाफ्ता विधायक की पत्नी उर्मिला राजपूत को पार्टी प्रत्याशी बनाने की मांग कर रहे हैं. उर्मिला भी जनता की अदालत में जाना चाहती हैं. बसपा की छवि भी अपनों के कारनामों से मलिन हुई है. भाजपा इसका फायदा उठाना चाहेगी. लोधी बहुल चरखारी सीट हारने की कसक उमा भारती को अभी भी सालती है. अपनी खोई प्रतिष्ठा को बुन्देलखण्ड के इस अंचल में पुनः स्थापित करने के लिए उमा पूरा जोर लगाएंगी. चरखारी सीट भाजपा की झोली में आने से उमा भारती के लिए पार्टी के उत्तर प्रदेश मिशन 2017 में निर्णायक जिम्मेदारी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

राज की नीति से भटक गई है राजनीति : डॉ. चिन्मय पंड्या

संत, युगपुरुष, दृष्टा, सुधारक और युग निर्माण योजना आन्दोलन के प्रणेता आचार्य श्रीराम शर्मा के अखिल विश्व गायत्री परिवार के अनन्य सदस्य व भविष्य के मुखिया डॉ. चिन्मय पंड्या पहली बार लखनऊ आए. शिक्षा से चिकित्सक और स्वभाव से संत डॉ. चिन्मय पंड्या हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हैं. युग निर्माण और गायत्री शक्ति की वैश्विक स्थापना के आंदोलन में रत गायत्री परिवार के अभिभावक डॉ. प्रणव पंड्या के पुत्र डॉ. चिन्मय से चौथी दुनिया के एडिटर इनवेस्टिगेशन प्रभात रंजन दीन की देश-समाज के कई मसलों पर विस्तार से बातचीत हुई. प्रस्तुत है उसके प्रमुख अंश...

प्रश्न : डॉ. पंड्या, आप एक तरफ कहते हैं कि जीवन में क्रांति तभी आ सकती है, जब व्यक्ति समय के साथ खुद को ढ़ाले, समय के साथ चले, समय की गति को पकड़े, समय के साथ होने वाले बदलाव के साथ खुद को समायोजित करे. ...फिर आप जीवन-प्रबंधन पर विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग जैसी तकनीक ने व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर दिया है. अब लोगों को एक-दूसरे की चिंता नहीं. एक-दूसरे से संवाद नहीं. परिवार में ही लोग एक-दूसरे से अलग हो गए हैं. ऐसा कहते हुए आप समय की इस आधुनिक गति से कहीं नाराज भी दिखते हैं. यह आपके विचारों का विरोधाभास है, या इसके बीच से आप कुछ अलग बात कहना चाहते हैं?

उत्तर: सम्बन्ध इसलिए बने थे कि हम उसमें आत्मीयता का विकास कर सकें और अपने आपको समाज की इकाई मान सकें. व्यक्ति अल्टिमेटली समाज की इकाई है और परिवार उसके बीच में माध्यम का कार्य करता है. जैसे-जैसे तकनीक का विकास हुआ है, वैसे-वैसे आदमी अपने निजी सम्बन्धों को, जो महत्वपूर्ण सम्बन्ध थे उसे भुलाता जा रहा है. हम फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट करने में तो लगातार लगे रहते हैं लेकिन अपने परिवार के सदस्यों की उपेक्षा करते रहते हैं, पत्नी बच्चे और माता पिता के साथ बात करने को तैयार नहीं रहते हैं. लेकिन दोष विज्ञान और तकनीक का नहीं है. दोष हमारे अपने दृष्टिकोण का है. दिक्कत यह नहीं है कि विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ. दिक्तत अपने माइंडसेट का है. दिक्कत यह है कि हमारा अपना नजरिया क्या है. गुरुदेव कहते हैं कि हमें नैसर्गिक रूप से प्रेम की भावना, कर्तव्य की भावना, दायित्व की भावना उपहार की तरह मिली है, आप चाहें तो उसका परिवार-समाज-राष्ट्र के लिए सार्थक इस्तेमाल करें और चाहें तो उसका इस्तेमाल न करें. हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है. समाज का विकास हो यह तो हर कोई चाहता है. लौकिक प्रगति हो, यह तो हर कोई चाहता है, लेकिन यह विकास आंतरिक उन्नति के मूल्य पर नहीं हो. कि आदमी खो जाए, परिवार टूट जाए, समाज बिखर जाए... तब हमने हासिल कर भी लिया तो उसका अर्थ क्या है.

प्रश्न: जो मौजूदा दौर है उसमें आपकी यह चिंता जायज है. आदमी के आंतरिक विकास, उसकी आंतरिक समृद्धि की आपकी जो चिंता है, इसका क्या कोई प्रायोगिक कॉन्सेप्ट है आपके पास? क्योंकि विज्ञान और तकनीक का विकास अभी और आगे बढ़ेगा. ग्लोबलाइज़ेशन का जो दौर है, वह और आगे बढ़ेगा, तीखा होगा, वह नई नस्लों को अपने आकर्षण के घेरे में और भी कसेगा. यह सोशल साइट्स जैसी चीजें और भी आधुनिकता और विविधता के साथ आएंगी. विज्ञान का विकास तो केवल सुविधाओं के क्षेत्र में हुआ है. आदमी को आदमी बनाने में विज्ञान का विकास नहीं हुआ है. यह वैज्ञानिक या तकनीकी सुविधाएं, व्यक्ति को इंसानियत से और दूर ले जाएंगी. विज्ञान अपनी गति से चलता रहे और मनुष्य अपनी इंसानियत के साथ विकसित होता रहे, इसे प्रगाढ़ करने के लिए और बहुत ही प्राकृतिक तरीके से भाव भरने के लिए, युग निर्माण के तहत क्या कोई योजना है?

उत्तर: गुरुदेव की योजना तो निश्चित रूप से थी. गुरुदेव से उस समय के एक वरिष्ठ संपादक ने कहा था कि आपके विचार इतने क्रांतिकारी हैं कि उसे जन-जन तक पहुंचना चाहिए. इस पर गुरुदेव ने उनसे कहा कि हमलोग उपदेश देने वाली संस्था नहीं हैं, हम लोग शिक्षा देने वाली संस्था हैं. लोगों के परिवर्तन के लिए हम आक्रामक अभियान चलाने के पक्षधर नहीं हैं. हम स्व-परिवर्तन के हिमायती हैं. हम परिवर्तित होंगे तो समाज के समक्ष हम खुद ब खुद उदाहरण की तरह प्रस्तुत होंगे, हमारा आदर्श जीवन ही विज्ञापन की तरह काम करेगा और वही अभियान की तरह समाज पर कारगर असर भी डालेगा. यह प्रमाणित और प्रामाणिक प्रयोग है जो गुरुदेव के चिंतन से प्रतिपादित हुआ. गुरुदेव के चिंतन को, समाजसेवा के उनके चिंतन को, समाज के प्रति जागरूकता के उनके चिंतन को हम अपने जीवन में उतारें, यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए. कार्यक्रम तो हर व्यक्ति या संगठन अच्छी सोच के साथ ही करता है. चोर भी अपने बच्चे को सिखाता है कि चोरी मत करो. भारत में शिक्षाओं की कमी नहीं है, उसमें एक और शिक्षा को प्रवेश कराने की जरूरत नहीं. शिक्षा की कमी नहीं है, आचरण की कमी है. भारत में यह हो रहा है कि शिक्षा की बात तो कही जा रही है, लेकिन उसे व्यवहार में उतारा नहीं जा रहा है. समाज में जो भ्रम है, जो भ्रांति है, जो विरोधाभास है, जो द्वंद्व है, जो तकलीफ है, उसकी मुख्य वजह यही है कि शिक्षा और व्यवहार में साम्यता नहीं दिख रही. जो बातें स्वयं के जीवन में नहीं होती, उसे ही वह समाज के समक्ष प्रस्तुत करता रहता है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो एक ही सूत्र वाक्य है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा. आदमी अपने को बदलने का प्रयास करे, बाकी लोगों को सुधारने की बात छोड़ दे. हर व्यक्ति सूरज हो जाए यह जरूरी नहीं, पर हर व्यक्ति दीपक हो जाए यह संभव है. सामर्थ्य के अनुसार हम अच्छा प्रयास करें, वही दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा. इसे ही दूसरे शब्दों में कहें तो अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता है. इसे चाहे हम समाज की दृष्टि से देखें या राष्ट्र की दृष्टि से देखें. हम गंगा नदी के प्रदूषण का मसला ही उठाएं, हमें यह भूल जाना चाहिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, संस्थाएं क्या कर रही हैं, हम केवल यह याद रखें कि हम क्या कर रहे हैं जब हम गंगाजी के पास जाते हैं. हर व्यक्ति अपना-अपना दायित्व उठा ले तो यही समग्र रूप से राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना के रूप में अभिव्यक्त होने लगता है. हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझने लगे. आदमी अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है. कर्तव्य की बात करने को आज कोई राजी नहीं हो रहा. सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप से महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जबतक व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, तबतक समाज का निर्माण संभव नहीं है. दायित्वबोध मूल मंत्र है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए.

प्रश्न: आप गुरुदेव का संदर्भ सामने रखते हुए कहते हैं कि हम उपदेशक नहीं हैं. फिर दायित्वबोध, व्यक्ति के निर्माण और सद्प्रयास की आवश्यकता की बात भी कहते हैं. अगर आप उपदेश या सीख के खिलाफ हैं तो व्यक्ति को उसके दायित्वों की तरफ मुखातिब करने का मोटिवेशन कैसे आए? जो आपसे बहुत दूर है, जो आपके कर्मों को देख पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सुन पाने की स्थिति में है तो उस तक आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, जब आपने व्यक्ति निर्माण और युग निर्माण का दायित्व उठाया है?

उत्तर: मैं प्रीच करने को मना नहीं करता. मैं कहता हूं कि आचरण में लाए बिना प्रीच करना, उपदेश देना उचित नहीं है. मेरे कहने का उद्देश्य यही था. चोर भी कहता है कि चोरी न करो. चोरी न करो यह अपने आप में गलत स्टेटमेंट नहीं है. लेकिन स्टेटमेंट कहां से निकल कर आ रहा है, यह उस तथ्य की प्रामाणिकता, उसकी पवित्रता और इसके प्रभाव को पारिभाषित करता है. यदि वह चीज आचरण से निकल कर आती है तो उसका प्रभाव दूसरा पड़ता है. ऐसा नहीं है कि लोगों को शिक्षा या उपदेश की आवश्यकता नहीं है, पर उससे कई गुणा ज्यादा उसे सही आचरण की आवश्यकता है. कोई गांव का भी व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा या कम समझ वाला भी व्यक्ति है पर वह आचरण को तुरंत भांप लेता है. आपकी भावनाएं अगर शुद्ध हैं, पवित्र हैं तो उसे समझने में लोगों को दिक्कत नहीं होती, वहां भाषा की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती.

प्रश्न: आपके कृत्य समाज पर कौन सा प्रभावकारी असर डाल रहे हैं? डॉ. चिन्मय पंड्या का ही उदाहरण लें, उनकी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है, उनके जो सार्थक कर्म हैं, उनका जो योग-ध्यान है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, उसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है? स्वामी विवेकानंद के सत्कर्मों का प्रसंग

> **“आतंकवाद के लिए हम धर्म को रेस्पॉन्सिबल नहीं मानते. धर्म तो दोनों ही स्थितियों में, करने वाले के लिए भी बहाना बन जाता है और इल्जाम लगाने वाले के लिए भी बहाना बन जाता है. जो इल्जाम लगाना चाहता है, वह मूल समस्या पर उंगली नहीं रखना चाहता इसीलिए वह धर्म को जिम्मेवार ठहरा देता है और जो आतंक फैलाने में लगे हैं, वे भी धर्म को संकीर्ण दायरे में रख कर देखते हैं और ऐसा करते हैं. धर्म हमलोगों की संस्कृति में बड़ा व्यापक अर्थ रखता है, धार्येति इति धर्मः, यानी, धारण करने योग्य गुण ही धर्म है. हम लोग धर्म को इसी रूप में जानते हैं. तो ये जो संकीर्णता है, इस तरह का चिंतन है, वह अज्ञानता से ही निकल कर आता है. सच तो यह है कि आप अपने ही धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद का जितना ही अध्ययन करते जाएं, जितना आप अध्ययन करते हैं, आप अपनी गहराई में जितना ही उतरते जाते हैं, आप सार्वभौमिकता और शाश्वतता पर उतना ही अधिक यकीन करने लगते हैं.”**

लें. देश में ऐसे महापुरुषों की कमी नहीं, चाहे जिसका नाम लें. युग निर्माण आंदोलन के प्रणेता गुरुदेव आचार्य श्रीराम शर्मा का ही उदाहरण हम सामने रखें और पूछें कि समाज पर क्या असर पड़ा? ऐसे व्यक्तित्वों से भरे-पूरे देश और समृद्ध संस्कृति के बावजूद भारतीय समाज का इतना स्खलन क्यों हुआ?

उत्तर: ऐसा जरूर देखने में आता है. समाज में बुराई तो आच्छादित दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज में अच्छाई नहीं है. बुरे लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है. ऐसे लोग ज्यादा दिखते भी हैं. लेकिन ऐसे लोग भी समाज में दिखते हैं जो हमारे लिए प्रेरणास्रोत का काम करते हैं. जहां समाज में नकारात्मकता दिखाई पड़ती है, वहीं आशा की किरणें भी दिखाई पड़ती हैं. ऐसे लोग भी दिखते हैं जो कष्टसाध्य परिस्थितियों के बावजूद समाज को अच्छा चिंतन देने के लिए तैयार हैं. हमारा उद्देश्य भी यही है और इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हमलोग सही सोच को सही आचरण में डालते हुए सही कानों तक पहुंचाने का जतन कर रहे हैं. हो सकता है कि एक लाख लोग सुन रहे हों, वो सारे के सारे उसी क्षण में परिवर्तित न हों, पर एक के मन में भी सही बीज का रोपण हो गया तो खाद पानी और धूप मिलने पर पूरी सक्षमता से वह पौधे के रूप में और एक दिन वृक्ष के रूप में खड़ा हो पाएगा. तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि उर्वर भूमि देखकर हम बीज डालते चलें. उस चिंतन को मन में डालने का प्रयत्न करते हैं कि जब कभी सही निर्णय लेने का वक्त आए तो मन में कोई संशय नहीं रहे और हम सही निर्णय ले पाएं. हम विश्वविद्यालयों में भी जाते हैं और छात्रों को उद्बोधन देते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक घंटे के उद्बोधन में सारे के सारे विवेकानंद या गुरुदेव ही होकर निकलेंगे, बल्कि हमारा उद्देश्य यह रहता है कि उनके जीवन में सही सोच आ जाए ताकि जब भी उनके जीवन में ऐसा अवसर मिले कि वे व्यापक समुदाय के जीवन को प्रभावित करने की स्थिति में हों तो वे सही निर्णय ले पाएं. हमारा उद्देश्य यही है कि हम नई नस्लों के मन में ऐसे संस्कार निरूपित करें कि देश या समाज का भविष्य संभालने का अवसर आने पर उनकी अंतरात्मा उन्हें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करे.

प्रश्न: विश्व स्तर पर आतंकवाद फैल रहा है और ज्यादा घातक हो रहा है. भारतवर्ष भी इससे आक्रांत है. इस रोग के अभी और फैलने का अंदेशा है. आतंकवाद भी कुसंस्कार और स्खलन का ही एक पहलू है. गायत्री परिवार के प्रतिनिधि मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ कई कार्यक्रम साझा करते रहे हैं. युग निर्माण की धारा में धर्म नहीं, बल्कि केंद्र में मानव है, ऐसे में क्या आप की तरफ से मुस्लिम धर्मगुरुओं का यह विचार बनाने की पहल होगी कि वे अपने फोरम से आतंकवाद को हतोत्साहित करें, उसे पुरजोरी से खारिज करें?

उत्तर: आतंकवाद के लिए हम धर्म को रेस्पॉन्सिबल नहीं मानते. धर्म तो दोनों ही स्थितियों में, करने वाले के लिए भी बहाना बन जाता है और इल्जाम लगाने वाले के लिए भी बहाना बन जाता है. जो इल्जाम लगाना चाहता है, वह मूल समस्या पर उंगली नहीं रखना चाहता इसीलिए वह धर्म को जिम्मेवार ठहरा देता है और जो आतंक फैलाने में लगे हैं, वे भी धर्म को संकीर्ण दायरे में रख कर देखते हैं और ऐसा करते हैं. धर्म हमलोगों की संस्कृति में बड़ा व्यापक अर्थ रखता है, धार्येति इति धर्मः, यानी, धारण करने योग्य गुण ही धर्म है. हम लोग धर्म को इसी रूप में जानते हैं. तो ये जो संकीर्णता है, इस तरह का चिंतन है, वह अज्ञानता से ही निकल कर आता है. सच तो यह है कि आप अपने ही धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद का जितना ही अध्ययन करते जाएं, जितना आप अध्ययन करते हैं, आप अपनी गहराई में जितना ही उतरते जाते हैं, आप सार्वभौमिकता और शाश्वतता पर उतना ही अधिक यकीन करने लगते हैं. प्रकृति के प्रत्येक कण में परमात्मा है तो वह हर एक इंसान में है. पर आपके मन में यह सोच तभी उपलब्ध हो सकती है, जब आप अपने धर्मग्रंथों को सच्चाई से पढ़ते हैं और सच्चाई से गहराई में उतरते हैं. मतभेद तब सतह पर उभर कर आते हैं जब दोनों तरफ से अपरिपक्व सोच हो एक तरफ भी परिपक्व सोच हो तो दिव्यता के प्रति, ईश्वर के प्रति, प्रभुसत्ता के प्रति कच्ची सोच को जन्म नहीं दे सकती. मैं नहीं कहूंगा कि कोई धर्म आतंकवाद के लिए विशेष रूप से कारण हो सकता है. गलतियां कहीं से भी हो सकती हैं, कारण कोई भी हो सकता है. अपराध को अपराध के नजरिए से ही देखे जाने की आवश्यकता है. नैतिक रूप से जो गलत है उसका नैतिक रूप से ही समाधान खोजने की आवश्यकता है.

प्रश्न: तो क्या आप यह मानते हैं कि मौजूदा दौर में आतंकवादनुमा जो अपराध है, उसमें धर्म का कोई लेना-देना नहीं है, धर्म की कोई भूमिका नहीं है?

उत्तर: मैं यह नहीं कहूंगा कि धर्म का कोई लेना-देना नहीं है. मैं यह कहूंगा कि धर्म को जिस रूप में हम लोग समझते हैं या धर्म को जिस तरह समझा जा रहा है, वह धर्म का सही अर्थ नहीं है. धर्म का जो अर्थ निकाला जा रहा है, वह धर्म का असली अर्थ नहीं है. जिस अर्थ के आधार पर धर्म को समझा जा रहा है वह अर्थ ही गलत है. इस गलत अर्थ को आधार मानते हुए कहें तो यह कह सकते हैं कि धर्म का लेना-देना है. पर धर्म की दृष्टि से पूछें तो मेरा तो मत यही है कि धर्म को हम लोग समझ ही नहीं पाए. धर्म उन शाश्वत गुणों का नाम है जो मानव के अंदर मानवता लाते हैं. इंसान को इंसानियत समझाते हैं.

प्रश्न: आतंकवाद के अपराध से आक्रांत इस आपत्ति-काल में क्या युग-निर्माताओं का यह कर्तव्य नहीं बनता कि वे धर्म-पीठों से यह आह्वान करें कि वे आतंकवाद की सार्वजनिक भर्त्सना करने के लिए आगे आएं?

उत्तर: निश्चित रूप से और हर तरीके से इस प्रयास के लिए हमलोगों का समर्थन भी रहता है कि कहीं पर ऐसी कोई भी चीज जो समाज के हित में नहीं है, उसके लिए हम लोग संगठित रूप से कैसे प्रयास कर सकते हैं, इस पर हम हमेशा विचार करते हैं. व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष धर्म पीठ के बारे में सोचना या उसको कहना हमारी रणनीति में शामिल नहीं रहा है. उसका मूल कारण यह नहीं है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से कोई अड़चन है, बल्कि इसके पीछे स्पष्ट चिंतन है कि जहां से कोई सकारात्मक परिणाम सामने आने की संभावना नहीं हो, ऐसी जगह ऊर्जा लगाने से बेहतर है कि आप अपनी ऊर्जा उस जगह लगाएं, जहां समाज के लिए आप कुछ संरचनात्मक कर सकते हों. हमारा उद्देश्य मतभेदों को और बढ़ाना नहीं है, बल्कि तालमेल को ज्यादा स्थापित करना है. तो ऐसे सारे मसले जिनसे समाज में विषमता या विरोधाभास बढ़ने की संभावना हो, उनमें सीधे इन्वॉल्व नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि हम उन मसलों के प्रति सचेत नहीं हैं या सजग नहीं हैं. घाव हो रहा है, यह हम लोगों को भी पता है, लेकिन घाव को कुरेदने की नहीं बल्कि उसकी मरहम पट्टी करने की आवश्यकता है. हमलोग बुराई उछालने के बजाय अच्छाई को बढ़ाने का कार्य करते हैं. बुराई अपने आप ही समय के साथ कमजोर होती चली जाएगी.

प्रश्न: धर्मांतरण को लेकर आपका क्या विचार है? धर्म किसी भी व्यक्ति का निज अधिकार है. इसमें राजनीति क्यों हस्तक्षेप करती है? मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देने में राजनीति की क्या भूमिका रही है?

उत्तर: मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा. इसे राजनीतिज्ञ ही बेहतर बता पाएंगे. लेकिन मैं यह जरूर बोलना चाहूंगा कि धर्म को सम्यक रूप से समझा नहीं गया, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें जन्म लेती हैं. हमें अगर कोई बात समझनी है तो उसके लिए अपनी पहचान बदलने की क्या आवश्यकता है. वेद और उपनिषद पढ़ने के लिए दारा शिकोह को धर्म बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी और कुरान पढ़ने के लिए मुझे कोई धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं. बाहर से पहचान बदल भी जाए, पर अंदर से मानवीय मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को भूलता जाए, उससे ज्यादा अच्छा है कि आदमी के अंदर इंसानियत आए, मानवता आए. जो जहां है, समाज के लिए वहीं से उपयोगी हो सकता है.

मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देने में राजनीति की भूमिका का जहां तक सवाल है, तो मैं एक ग्रीक दार्शनिक के कथन का संदर्भ लूंगा. उन्होंने कहा था, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू द पॉलिटिक्स, इट डज़ नॉट मीन पॉलिटिक्स डज़ नॉट टेक इंटरेस्ट इन यू. ...मैं राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेता, इसका यह मतलब नहीं कि राजनीति मुझमें दिलचस्पी नहीं लेती. दिक्कत यहां आ जाती है कि राज की जो नीति अपने देश में विकसित थी वह यह थी कि राजनीति से जुड़ा हर व्यक्ति खुद को समाज का अभिन्न अंग मान कर सेवक की तरह कार्य करे, वह भाव कहीं से लुप्त होता चला गया है. भारतवर्ष में राज की वह आदर्श नीति थी, वह अपने रास्ते से भटक गई है. पद, सत्ता और निज स्वार्थ ही उद्देश्य बन कर रह जाए तो स्वाभाविक है उसका नकारात्मक असर देश-समाज पर पड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिजली विभाग की लापरवाही से मरते लोग

अखिल पांडेय

उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही जगजाहिर है. उनकी लापरवाही से किसी के घर का चिराग बुझ जाए, इससे भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता. अधिकारियों की हीलाहवाली व लापरवाही का खामियाजा बेचारे गरीब संविदाकर्मियों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है. लापरवाह अधिकारी हर साल सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं. बावजूद इसके न वे अपनी कार्यशैली में कोई परिवर्तन कर रहे हैं और न ही विभाग की ओर से ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई ही की जा रही है. उल्टा जान से हाथ धोए कर्मचारी के परिजनों को मुआवजा देने में विभाग का दम निकल रहा है. अधिकारियों की लापरवाही से दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं का आंकड़ा आसमान छू रहा है. वर्ष 2004-05 में प्रदेश में जहां विद्युत दुर्घटनाओं से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 494 थी जो 10 साल के बाद वर्ष 2013-14 में 611 के आंकड़े तक पहुंच गई है. वर्ष 2014-15 के जनवरी 2015 तक ही बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं का आंकड़ा तकरीबन 1185 पहुंच गया है, जिसमें 566 मानवीय घातक दुर्घटनाएं हैं. घातक विद्युत दुर्घनाओं में 95 फीसदी लोगों की जानें चली जाती हैं. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस वित्तीय वर्ष भी मरने वालों की संख्या 600 पार कर जायेगी. कुल विद्युत दुर्घटनाओं के तीन सालों पर नजर डालें तो वर्ष 2012-13 में जहां कुल विद्युत दुर्घटनाएं 1399 थीं वहीं वर्ष 2013-14 में वह बढ़कर 1432 हो गयी है. बिजली विभाग का मुखिया हमारे सूबे का भी मुखिया है बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यह बेहद सोचनीय विषय है. जबकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ऊर्जा मंत्री होने के नाते अधिकारियों की हर खबर जरूर होगी. वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री के तौर पर यासिर शाह को भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे दुर्घटना में मारे गए या घायल हुए परिजनों को न्याय मिल सके. घर के

मौत के आंकड़े चौंकाने वाले

वर्ष 2013-14 में मरने वालों की संख्या 611
वर्ष 2012-13 में कुल दुर्घटनाएं 1399
वर्ष 2013-14 में 1432 और जनवरी 2015 तक 1185 दुर्घटनाएं

घोटाला करने पर हो ध्यान तो जाएगी ही जान

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है. कारपोरेशन के अधिकारियों-कर्मचारियों का पूरा ध्यान धन बटोरने पर लगा है, इसीलिए सारी प्राथमिकताएं गौण हो गई हैं. भ्रष्टाचार के कारण कारपोरेशन का घाटा गहरा होता चला जा रहा है. ऊर्जा विभाग को भ्रष्टाचार और घोटालेबाजों ने अपने चंगुल में जकड़ रखा है. अब तक हजारों करोड़ के घोटाले उजागर कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई शून्य है. ऊर्जा सेक्टर में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ने वाले व्हिसिल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल को इसी वजह से अपनी नौकरी गंवानी पड़ी. ऊर्जा महकमे के अरबों के घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की कई याचिकाएं अदालत में लम्बित हैं. भ्रष्टाचार के खिलाफ दाखिल उनकी याचिकाएं बिना सुने और उन्हें बिना सूचना दिए ही खारिज कर दी जाती हैं. जबकि नंदलाल जायसवाल की याचिका उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम के हजारों करोड़ रुपये के घोटाले को उजागर करने वाला प्रामाणिक दस्तावेज है. व्हिसिल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल ने यूपी के जिन बड़े बिजली घोटालों का पर्दाफाश किया है उनमें पावर कॉरपोरेशन में हुआ पांच हजार करोड़ का घोटाला शामिल है. तत्कालीन मायावती सरकार ने जांच के आदेश दिए, पर जांच शुरू ही नहीं हुई. मौजूदा राज्य सरकार भी इसकी जांच के लिए प्रयासरत नहीं है. इसी तरह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 1600 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ. इस मामले को भी श्री जायसवाल ने उठाया और जांच भी शुरू हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. विद्युत नियामक आयोग की शह पर जेपी समूह समेत निजी बिजली-घरानों को लाभ पहुंचाये जाने से करीब 30 हजार करोड़ रुपये की क्षति हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत नियामक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष राजेश अवस्थी हटा तो दिए गए, पर घोटाले की जांच अभी भी फाइलों में ही बंद है. जल विद्युत निगम में 750 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ. तत्कालीन एमडी आलोक टंडन समेत कई अभियंताओं के इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है. इस मामले में जांच जारी है, नतीजा कब आएगा कोई नहीं कह सकता.

कमाऊ सदस्य की विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अगर जान चली जाए तो परिवार का आसरा ही छिन जाता है. ऐसे में कम से कम विभाग को शोक संतृप्त परिवार को मुआवजे के तौर पर जीवन यापन के लिए सहायता राशि प्रदान करनी चाहिए. लेकिन इस मामले में पावर कारपोरेशन पूरी तरह से संवेदनहीन है. बिजली से होने वाली दुर्घटना में अगर किसी की जान जाती है तो विभाग की ओर से महज एक लाख रुपये देने की ही व्यवस्था है. वहीं 50 हजार रुपये ठेकेदार की ओर से खानापूर्ति की तौर पर दे दिए जाते हैं. यानि दुर्घटना में मरने वाले की जान की कीमत बिजली विभाग के लिए महज डेढ़ लाख रुपये ही है. जिसमें भी कई मामलों में पावर कारपोरेशन प्रबंधन कोताही कर जाता है. वहीं पशुहानि व सम्पत्तियों और फसलों के नष्ट होने पर विभाग हमेशा ही मुआवजे पर खामोश ही रहता है. पावर कारपोरेशन वित्तीय भार वहन करने का भी रोना रोता है. राजधानी लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा होता ही जा रहा है. बावजूद इसके इन घटनाओं को रोकने के लिए न तो शासन ही गंभीर है और न ही पावर कारपोरेशन प्रबंधन. बस कारपोरेशन यह स्वीकार जरूर कर रहा है कि उसके अधिकारी लापरवाह हैं और उनकी लापरवाही से ही दुर्घटनाओं का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है. आये दिन दुर्घटनाओं से चिंतित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने मामले को गम्भीरता से जरूर लिया. आयोग के सचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव ने 28 नवम्बर 2014 को पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष सहित सभी बिजली कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिये थे. जिस पर पावर कारपोरेशन ने पहली बार माना है कि बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लाइनों व अनुरक्षण कार्य के रख-रखाव के लिए क्षेत्रीय अधिकारी दिये गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं जिससे विद्युत दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और लोगों की जानें जा रही हैं. आम तौर पर बिजली दुर्घटनाओं पर अपनी गलती न होने के लिए पल्ला झाड़ने वाले पावर कारपोरेशन की यह स्वीकारोक्ति बिजली विभाग की लचर हालत को खुद ब खुद उजागर करती है. इस मसले पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्पष्ट कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से दिन-प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं व मौतों पर सूबे के मुखिया अखिलेश यादव व विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सहित मानवाधिकार आयोग को दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. साथ ही मुआवजे में किसी तरह की कोई देरी नहीं करनी चाहिए. कार्रवाई में देरी ही संदेह के तमाम सवाल खड़े करती है. श्री वर्मा ने कहा कि विद्युत दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं लेकिन बिजली कंपनियों की उदासीनता सामने आने के बाद भी कठोर कार्रवाई नहीं किया जाना गंभीर चिंता का विषय है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा में चले 77वें स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के समापन पर राज्यपाल राम नाईक ने पीठासीन अधिकारियों को कई नसीहतें दीं. उन्होंने कहा कि सदन के काम-काज में सबसे बड़ी समस्या सदस्यों का वेल में आ जाना है. अब तो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य भी वेल में जाने लगे हैं. प्रश्नकाल और शून्य काल की हत्या नहीं होनी चाहिए. सदस्य मेहनत करके सवाल बनाते हैं. उनके जवाब के लिए गांव से लेकर दिल्ली तक हिल जाता है. हंगामे के चलते प्रश्नकाल हो ही नहीं पाता.

स्पीकर ने सदन में बढ़ते विरोध पर जताई चिंता

दीनबंधु कबीर

लखनऊ में हुए स्पीकरों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सदन में बढ़ते शोर पर चिंता तो जताई गई लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया कि सदनों में शोर क्यों बढ़ रहे हैं. सदन में बढ़ते विरोध के स्वर को सदन की मर्यादा पर कुठाराघात तो माना गया, लेकिन यह विचार में नहीं आया कि जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उसके खिलाफ सदन में शोर क्यों नहीं बरपे. सदन में जन प्रतिनिधियों से कुलीनपन की अपेक्षा की गई, लेकिन पीठासीन पदाधिकारियों ने सरकारों से यह अपेक्षा नहीं की कि जनता की आशाओं-उम्मीदों को वे पूरा करें तो सदन में खुद ब खुद शांति आ जाएगी.

सम्मेलन का लब्बो-लुबाव यही रहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने के नाम पर विरोध के स्वर को थामने की कोशिशें हो रही हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा में देशभर की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इसी बात की भूमिका बनाई जाती रही कि सदन के वेल में आकर जनप्रतिनिधियों के विरोध के स्वर बुलंद करने पर कैसे अंकुश लगे. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक तो इस चलन को कैंसर बताते हैं और इसके इलाज के लिए कारगर कीमोथिरेपी की वकालत करते हैं. प्रश्नकाल और शून्यकाल में बाधा न हो, इसकी चिंता तो जायज है, लेकिन जनता से चुनकर आने वाले जन प्रतिनिधि सदन में अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पाएं इसकी पेशबंदी लोकतंत्र के लिए कोई सकारात्मक चिंता नहीं है. सम्मेलन के दौरान विधानसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष की भी अधिकतर सीटें खाली रहीं. बसपा और कांग्रेस के अधिकांश सदस्य नदारद रहे और भाजपा के विधायक भी पीठासीन सम्मेलन में नहीं पहुंचे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा में चले 77वें स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के समापन पर राज्यपाल राम नाईक ने पीठासीन अधिकारियों को कई नसीहतें दीं. उन्होंने कहा कि सदन के काम-काज में सबसे बड़ी समस्या सदस्यों का वेल में आ जाना है. अब तो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य भी वेल में जाने लगे हैं. प्रश्नकाल और शून्य काल की हत्या नहीं होनी चाहिए. सदस्य मेहनत करके सवाल बनाते हैं. उनके जवाब के लिए गांव से लेकर दिल्ली तक हिल जाता है. हंगामे के चलते प्रश्नकाल हो ही नहीं पाता. अध्यक्ष को यह ध्यान रखना होगा कि हंगामे के चलते अध्ययनशील सांसदों के बोलने का मौका न चला जाए.

हालांकि राज्यपाल ने यह जरूर कहा कि विपक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए. लेकिन साथ ही यह भी जोड़ दिया कि आजकल टीवी पर सदनों की लाइव कार्यवाही दिखती है. बच्चे सदन में झगड़ा देखकर कहते हैं कि इससे अच्छा तो हमारे स्कूल का अनुशासन है. सदन के आचरण का फर्क नई पीढ़ी पर पड़ता है. विपक्ष को भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल विरोध के लिए महत्वपूर्ण विषयों को न रोकें.

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सदस्यों के बेहतर आचरण की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले विरोध के नए-नए तरीके खोज लेते हैं. वेल में आने के नियम का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए. सदन की कार्यवाही लाइव होने के नफा-नुकसान दोनों हैं. कुछ सांसद अपने क्षेत्र में टीवी पर दिखने के लिए भी हंगामा करते हैं. लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह भी कहा कि देश की प्रगति में विधायी निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है. सदन में जितनी रचनात्मक चर्चा होगी कानून उतने ही बेहतर बनेंगे. उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी प्रशंसा की और कहा कि वे उत्तर प्रदेश को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आजादी के 60 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ें और अधिक गहरी हुई हैं. देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं पहले से अधिक सुदृढ़ हुई हैं और उनका स्वरूप भी निखरा है. सदन को लोकतंत्र का मन्दिर बताते हुए सीएम ने कहा कि जनता की आशाएं और अपेक्षाएं प्रत्यक्ष रूप से सदन से जुड़ी हैं. इसलिए सदस्यों की पहली प्राथमिकता जनता के विश्वास को सदन के प्रति मजबूत बनाने की होनी चाहिए.

पीठासीन अधिकारी एक जनप्रतिनिधि भी होता है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है. अखिलेश ने यह माना कि विगत कुछ वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा है कि पीठासीन अधिकारियों को अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. उन्हें सदन के संचालन एवं उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं. विधायी संस्थाएं आजादी के संघर्ष की देन हैं. आजादी के संघर्ष को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सशक्त मंच की भूमिका का उल्लेख करते हुए अखिलेश ने कहा कि इसी मंच से राज्य के महान नेताओं ने राजनीतिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन की आवाज बुलन्द की है. उत्तर प्रदेश विधान मंडल को देश का सबसे बड़ा विधान मंडल बताते हुए उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे महान राजनेताओं ने इसी सदन से होते हुए देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया. उत्तर प्रदेश विधान सभा में पीठासीन अधिकारी के पद की गरिमा में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने जिस परम्परा की नींव रखी, उसे नफीसुल हसन, आत्माराम गोविन्द खेर, मदन मोहन वर्मा, नियाज हसन सहित अन्य सभी अध्यक्षों ने दृढ़ता के साथ निभाया और आगे बढ़ाया. महान समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विरासत को पुख्ता करने में मुलायम सिंह यादव के महत्वपूर्ण योगदान की भी सीएम ने चर्चा की. उल्लेखनीय है कि विधायी निकायों के पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन वर्ष 1921 से लगातार आयोजित हो रहा है. यह सम्मेलन विभिन्न राज्यों में आयोजित होते रहे हैं. उत्तर प्रदेश में यह सम्मेलन इससे पहले वर्ष 1961 तथा वर्ष 1985 में आयोजित हो चुका है.

पेपरलेस सदन पर सहमति

सदन को बोली विहीन करने की चर्चा के बाद उसे कागज विहीन करने के मसले पर भी चर्चा हुई. पेपरलेस सदन की आवश्यकता पर चर्चा के दौरान फिलहाल लेस पेपर सदन करने की सहमति बनी. नजीर के तौर पर हिमाचल प्रदेश और गोवा विधानसभा ने प्रेजेंटेशन दिया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कहना था कि पेपरलेस प्रणाली से हर साल लगभग 15 करोड़ रुपये का प्रिंटिंग, वितरण और कागज का खर्च बचा है. बिहार सहित कुछ विधानसभाओं ने कम्प्यूटराइजेशन के लिए बजट की मांग की. हालांकि पंजाब का सुझाव आया कि पेपरलेस होने से इतने खर्चे बचेंगे कि पुराने बजट में ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है. कुछ विधानसभाओं का कहना था कि बजट जैसे विधायी कार्यों के लिए फिलहाल कागजी रिपोर्टों का जारी रखना जरूरी है. यह तय हुआ कि पहले सदन को लेस पेपर की ओर आगे बढ़ाया जाए, इसके बाद पूरी तरह से ऑनलाइन करने की ओर कदम आगे बढ़ाया जाएगा.

विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि यूपी में कार्यसूची पहले ही ऑनलाइन की जा चुकी है. अगले चरण में सदस्यों से नोटिस और उन्हें सूचना देने की प्रक्रिया को भी ई-मेल से भेजने की व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाएगा. इसके लिए सदस्यों और विधानसभा सचिवालय के बीच संवाद की प्रक्रिया भी ऑनलाइन करने की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है. सदन को जवाबदेह बनाने के लिए मध्य प्रदेश ने भी कई नए प्रयोग किए हैं. मध्यप्रदेश विधानसभा के सचिव एपी सिंह ने बताया कि सदन में दिए जाने वाले मंत्रियों के आश्वासनों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है. किसी मसले पर सुबह सदन में आश्वासन आता है और शाम तक वेबसाइट पर ऑनलाइन हो जाता है. साथ ही संबंधित विभाग को भी उसे तुरंत भेज दिया जाता है. एक साल के भीतर इस प्रयोग से 80 फीसदी से अधिक आश्वासनों पर कार्रवाई हुई है.

"लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सदस्यों के बेहतर आचरण की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले विरोध के नए-नए तरीके खोज लेते हैं. वेल में आने के नियम का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए. सदन की कार्यवाही लाइव होने के नफा-नुकसान दोनों हैं. कुछ सांसद अपने क्षेत्र में टीवी पर दिखने के लिए भी हंगामा करते हैं. लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह भी कहा कि देश की प्रगति में विधायी निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है. सदन में जितनी रचनात्मक चर्चा होगी कानून उतने ही बेहतर बनेंगे. उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी प्रशंसा की और कहा कि वे उत्तर प्रदेश को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं."

वेल में आते ही हो जाएं निलंबन

स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बड़ी लाइन खींची. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्पीकर की भूमिका केवल सदन की कार्यवाही तक ही सीमित न हो बल्कि वे विकास के लिए भी प्रभावी पहल करें. महाजन ने कहा कि यह नियम है कि यदि कोई सदस्य वेल में आता है तो उसकी सदस्यता उस सत्र में निश्चित समय के लिए निलंबित हो सकती है. जब यह नियम है तो निलंबन स्वत: ही क्यों न हो जाए. इसके लिए अध्यक्ष को निर्णय क्यों करना पड़ता है. खुद ही यह सवाल उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्पीकर कहीं ऊपर से नहीं आता बल्कि वह भी जनप्रतिनिधि होता है इसलिए वह भी कार्रवाई से बचना चाहता है. होना यह चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज देखकर पार्टियां खुद ही यह निर्णय ले लें. छत्तीसगढ़ में वेल में आने के बाद स्वत: निलंबन की व्यवस्था लागू है. हालांकि कुछ विधानसभा अध्यक्षों ने इसके व्यावहारिक पक्ष को रखते हुए कहा कि दरअसल सदस्य पर कार्रवाई किए जाने से उस क्षेत्र या जनता के मुद्दे प्रभावित होते हैं जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा होता है. इसलिए विवेक के आधार पर निर्णय ही बेहतर विकल्प है.